विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत

NBT
नवभारत टाइम्स

विकसित उत्तर प्रदेश
विकसित भारत

READER ENGAGEMENT INITIATIVE

बेनेट, कोलमेन ऍंड कंपनी लिमिटेड
द टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रयागपुर टावर, 38/22, मीराबाई मार्ग, स्टेट गेस्ट हाउस के सामने, लखनऊ-226001

नवभारत टाइम्स

विशेष धन्यवाद
एस पी गोयल, आईएएस
मुख्य सचिव
संजय प्रसाद, आईएएस
प्रमुख सचिव, सूचना
विशाल सिंह, आईएएस
निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन
डॉ. के वी राजू
मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार

प्रोजेक्ट हेड
धनुष वीर सिंह

रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन
अनिल कुमार सिंह,
मुदित शुक्ला, शिवांग अग्रवाल

एडिटर
अभिषेक कुमार सिंह

एडिटोरियल कोऑर्डिनेशन
अमूल रस्तोगी

कंटेंट डेवलपमेंट
अमिल भटनागर

डिजाइन
नीरज कुमार श्रीवास्तव
कम्बर अली

फोटो
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

फोटो इंहैंसमेंट
प्रीप्रेस टीम, लखनऊ

प्रिंटर
लस्ट्रा प्रिंट प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

COPYRIGHT© BENNETT, COLEMAN & CO. LTD

All rights reserved: Worldwide. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electrical, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the copyright holder. The opinions and views contained in this publication are not necessarily those of the Publisher's.

Disclaimer: Due care and diligence has been taken while compiling this book. The Publisher does not hold any responsibility for any mistakes that may have crept in inadvertently. The Publisher shall be free from any liability for damages and losses of any nature arising from or related to the content of the book.

उत्तर प्रदेश देश में नंबर

- उत्तर प्रदेश को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में देश में पहला स्थान मिला।
- उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में लगातार देश में प्रथम स्थान पर है, जहां वर्ष 2023-24 में 177 मिलियन टन गन्ना उत्पादन, वर्ष 2024-25 में लगभग 4.2 मिलियन टन शीरा और वर्ष 2024-25 में लगभग 91.1 लाख टन (9.11 मिलियन टन) चीनी का उत्पादन हुआ।
- इथेनॉल उत्पादन और आपूर्ति में देश में प्रथम स्थान।
- उत्तर प्रदेश ई-मार्केट प्लेस (GeM) के तहत सबसे अधिक सरकारी खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने वर्ष 2024-25 में GeM के माध्यम से कुल 5.43 लाख करोड़ रुपये के 72 लाख से अधिक खरीद ऑर्डर निष्पादित किए हैं।
- क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह-2023 में राज्य को छह श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- एक अभियान के तहत 2025 में राज्य में 37.21 करोड़ पौधरोपण का रिकॉर्ड।
- वर्ष 2023-24 में, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार दिया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है।
- कौशल विकास नीति को लागू करने वाला यूपी पहला राज्य है और (एनपीएस) के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण करने में देश में प्रथम स्थान पर है।
- भारत स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता-2022 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए।
- नौवें स्मार्ट सिटी एक्सपो में, कानपुर को पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण और विकास कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ विरासत एवं ऐतिहासिक वास्तुकला और लैंडमार्क प्रस्तुति पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों और पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के अंतर्गत 56 लाख से अधिक आवासों के निर्माण में देश में प्रथम स्थान।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन में देश में प्रथम। लगभग 2.86 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कर यूपी देश में प्रथम।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को लगभग 20 लाख ऋण वितरित करके देश में प्रथम।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2.68 करोड़ स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करके देश में प्रथम।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड सुनिश्चित करने में देश में सर्वोच्च स्थान।
- व्यापार सुगमता में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य।
- 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करके देश में प्रथम
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में अव्वल।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2.28 करोड़ नामांकन के साथ देश में प्रथम ज्योति बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1.12 करोड़ से अधिक नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
- अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव-2024 में 25,12,585 दीप प्रज्वलित कर गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक बार फिर नाम दर्ज हुआ।

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICA
First Conv
30th June 20

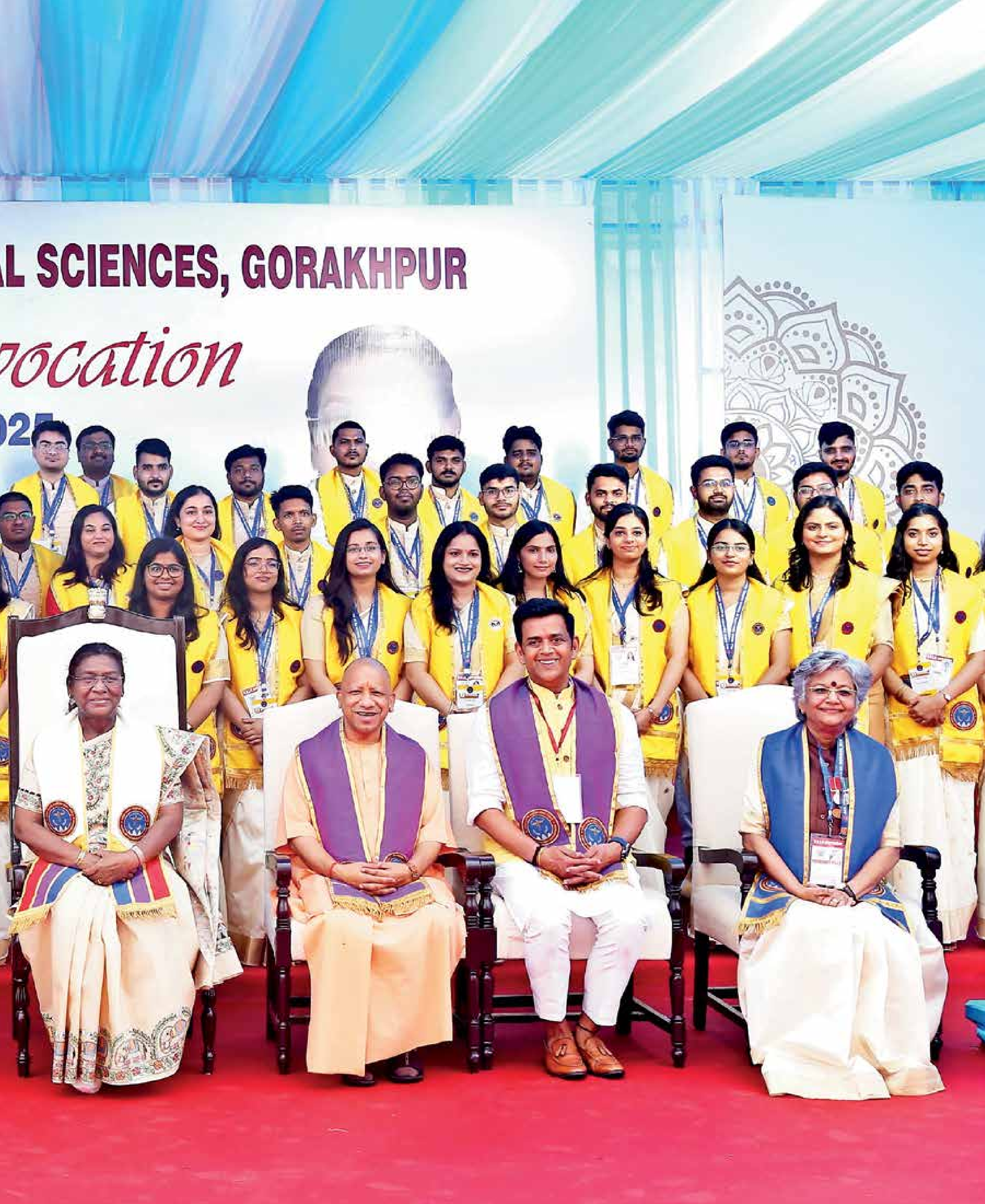
AL SCIENCES, GORAKHPUR
vocation

भविष्य की नई दिशा

नेतृत्व का असली उद्देश्य होता है,उनकी मदद करना जो पीछे छूट गए हैं और उन लोगों को और बेहतर बनाना जो पहले से अच्छा कर रहे हैं। बीते आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में यही हुआ है।

उत्तर प्रदेश इस बदलाव का जीवंत उदाहरण है कि एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व किसी राज्य की दिशा कैसे बदल सकता है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला, तब उन्होंने विकास और बदलाव का एक स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया। राज्य में आमूलचूल सुधार की जरूरत थी और उन्होंने इसके लिए दिन-रात अथक परिश्रम किया। आठ साल बाद, वही सपना अब साकार हो रहा है।

इस दौरान राज्य ने अभूतपूर्व विकास देखा है। शासन ने आमजन की जरूरतों को प्राथमिकता दी है। जो लोग पहले की सरकारों की अनदेखी से निराश थे, उन्हें लगा कि अब उनकी आवाज सुनी जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए रोजमर्रा के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। भ्रष्टाचार और अक्षमता से जूझते प्रदेश में उन्होंने नई ऊर्जा का संचार किया। कड़े निर्णय लिए गए और कानून-व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अपराध पर लगाम लगी, माफिया राज का खात्मा हुआ और समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। यह मॉडल आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है।

बेहतर शासन का एक आधार जनकल्याण है। मुख्यमंत्री ने अनेक योजनाएं शुरू कीं, जिनसे लोगों का जीवन सरल हुआ है। जनहित को केंद्र रखते हुए निर्णय लिए गए और 'डबल इंजन सरकार' की नीति का प्रदेश के नागरिकों व इसके विकास पर गहर असर हुआ है। इन वर्षों में ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ, जो निवेश, विनिर्माण और व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है।

योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो आर्थिक छलांग राज्य ने लगाई है, वह ऐतिहासिक है। 2018 और 2023 के निवेशक सम्मेलन से लेकर 2024 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह तक यूपी निवेश का पसंदीदा केंद्र बन गया है। अब देश ही नहीं, दुनिया भी यूपी की संभावनाओं को पहचानने लगी है।

इन उपलब्धियों के केंद्र में मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व है। उनका विकास मॉडल सर्व-समावेशी है, जो आज की जरूरतों को समझते हुए भविष्य के लिए तैयार किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' नीति और योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली मिलकर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से ले जा रही है। 5 ट्रिलियन डॉलर वाली भारत की अर्थव्यवस्था अब सपना नहीं, एक लक्ष्य है—जिसे उत्तर प्रदेश साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

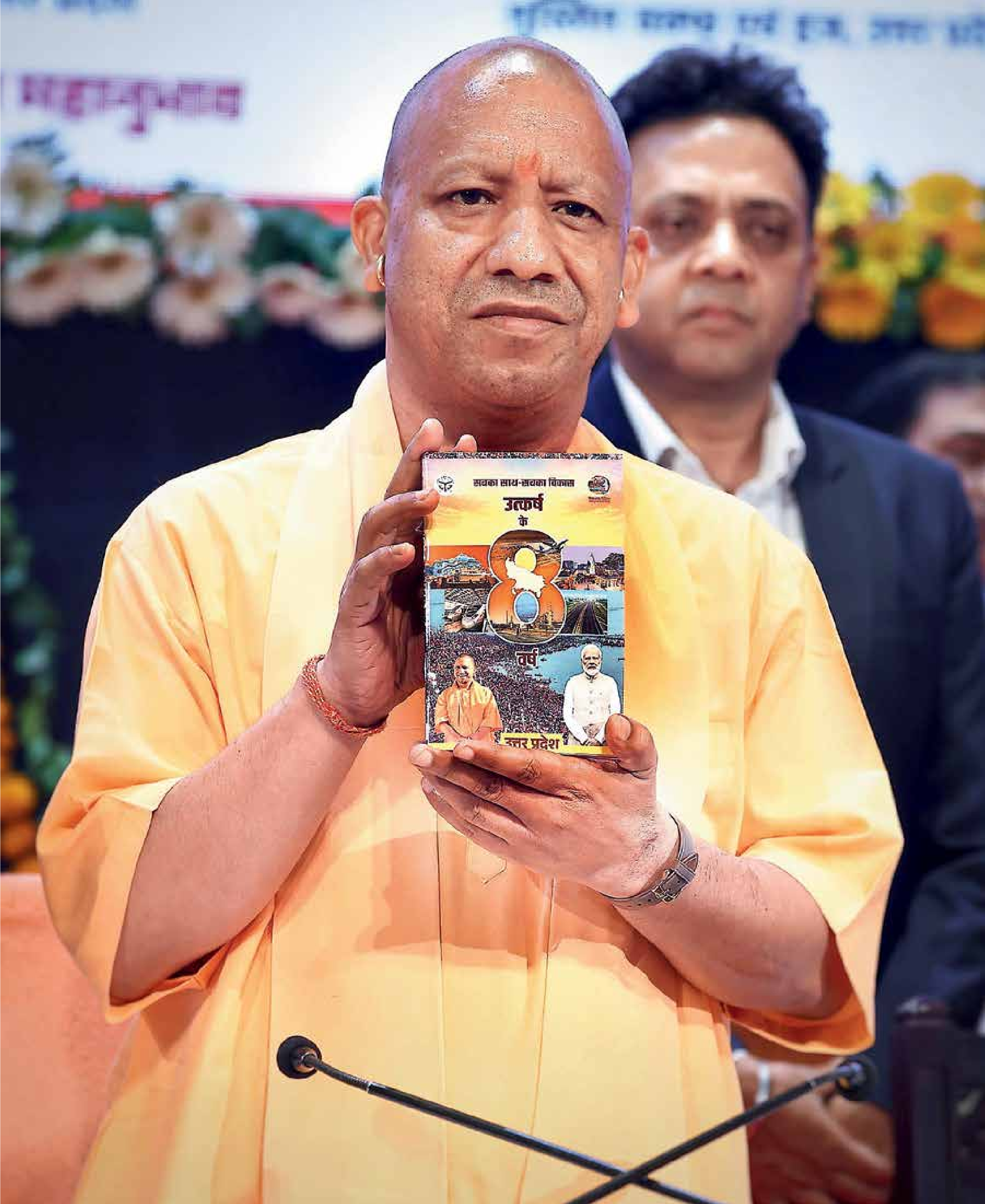
सबका साथ-सबका विकास
उत्कर्ष
के
8
वर्ष
उत्तर प्रदेश

विषय सूची

उत्तर प्रदेश में स्वर्णिम काल का आगमन 14

ट्रिलियन-डॉलर विजन
1.एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर 22
2.भागीरथ प्रयास से तीव्र विकास 24
3.यूपी को मिली बजट की शक्ति 30
4.एक अभूतपूर्व उपलब्धि 36

इन्फ्रास्ट्रक्चर
1.भविष्य का निर्माण 40
2.मनोरंजन का 'कैलेडोस्कोप': योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 48

औद्योगिक विकास
1. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चल रहा औद्योगिकीकरण का स्वर्णिम युग 52
2.एक जनपद एक उत्पाद लोकल से ग्लोबल तक 58
3.नवाचार से प्रेरित नीतियां 64

ग्रामीण एवं कृषि
1.जमीनी स्तर पर क्रांति 70
2.किसानों के लिए हर बूंद है कीमती 74
3.यूपी में पशु कल्याण क्रांति 76
4.गन्ने की तरक्की का मीठा स्वाद 78
5.प्रगति के बीज बोना 80

युवा और महिला
1.युवा प्रगति की ओर 86
2.मिशन रोजगार 92
3.सशक्त महिला लाभार्थी 96

शहरी विकास
1.पौधरोपण से पर्यावरण संरक्षण 102

विषय सूची

2.अयोध्याः आस्था और प्रगति का नगर 104
3.खुशहाल जीवन 108
4.शहरी क्षेत्रों में अमूल चूल परिवर्तन 110

कानून व्यवस्था
1.अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस 116

शिक्षा
1.शिक्षा में एक नया अध्याय 126

हेल्थकेयर
1. एक बड़ी जीत 132
2.सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य 134

ऊर्जा
1.जगमगाता उत्तर प्रदेश 142

राजस्व
1.बेहतर होती वित्तीय स्थिति 148

सामाजिक सुरक्षा
1.जन जन से सरोकार 154

क्षेत्रीय संतुलन
1.जिलों की नई उड़ान 162
2.जनजातियों का उत्थान 166
3.समृद्धि की ओर गांव 168

डिजिटाइजेशन
1.सीमाओं से परे : डिजिटलीकरण 170

पर्यटन
1.विश्व का स्वागत करता यूपी 176
2.दिव्यता, भक्ति और विकास की त्रिवेणी 180
3.दिव्यता की अनुभूति 186

डबल इंजन सरकार का

सकारात्मक प्रभाव

उत्तर प्रदेश में स्वर्णिम काल का आगमन

उत्तर प्रदेश में बदलाव की शुरुआत आज से आठ साल पहले हुई, जब मौजूदा सरकार ने जनता का भरोसा जीतकर सत्ता संभाली और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना गया। यह एक नए दौर की शुरुआत थी, जब प्रदेश ने विकास और सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाए। मुख्यमंत्री योगी को मिला प्रचंड जनादेश इस बात का संकेत था कि जनता पुराने नेताओं की नीतियों से तंग आ चुकी थी और बदलाव चाहती थी। बीते वर्षों में शासन के हर क्षेत्र में हुए सुधारों ने आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और राज्य को एक नई दिशा दी है।

उत्तर प्रदेश के कायाकल्प की यात्रा आज से आठ वर्ष पहले शुरू हुई, जब वर्तमान सरकार को जनादेश मिला और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। यह वास्तव में एक नए युग की शुरुआत थी—एक ऐसा सवेरा, जिसने उम्मीदों और संभावनाओं की नई रोशनी बिखेरी। प्रदेश में बदलाव की लहर तेज होने लगी और लोगों की भावनाएं इन सकारात्मक परिवर्तनों के समर्थन में मजबूती से सामने आने लगीं।

कानून का शासन कायम रखना

नागरिकों की सुरक्षा इसकी मूलभूत जरूरतों में से एक है। सरकार का यह दायित्व है कि वह समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखे और अपराध पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाए। पहले के नेता नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कदम उठाए।

उन्होंने नए संकल्पों को लागू करने और उन्हें धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी ली। उत्तर प्रदेश हमेशा से सत्ता के केंद्र में रहा है। ऐसे में एक बार फिर पूरे देश की निगाहें प्रदेश और उसके नए मुखिया पर टिकी थीं। मुख्यमंत्री ने पल भर में ही नजारा बदल दिया। पूरे प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं को संदेश दिया गया कि नई सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर जोर देगी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस बलों को और अधिक सशक्त बनाया गया। उन्हें बेहतर सुविधाओं और तकनीक से सशक्त बनाया गया, ताकि प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके और उनका खात्मा किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए सुधार लागू किए गए हैं, जो एक बड़ा मुद्दा रहा। सुरक्षा के लिए निगरानी और गश्त बढ़ाने से लेकर अपराधियों को जेलों में रखने के लिए प्रभावी अभियोजन के प्रावधान किए गए। इस संदर्भ में महिलाओं में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता अभियान

चलाए गए। पिछले आठ वर्षों में 8,000 से अधिक मुठभेड़ों को अंजाम दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 222 अपराधी ढेर हुए और 8,118 से अधिक अपराधी घायल हुए। करीब 80,000 अपराधियों को जेल भेजा गया है और 900 से ज्यादा लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कई अपराधी या तो गंभीर अपराधों में शामिल थे या फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोपी थे।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की विशेष उपलब्धि

वर्ष 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट योगी सरकार के समर्पित प्रयासों का नतीजा था। इस समिट के दौरान 40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। वहीं 26,954 से अधिक एमओयू साइन किए गए, जिससे भविष्य में 1.1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन्वेस्टर समिट की बदौलत पूरे राज्य को निवेश के लिए हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 17.70 लाख करोड़ रुपये, पूर्वांचल में करीब 11 लाख करोड़ रुपये, बुंदेलखंड में 5 लाख करोड़ रुपये और मध्यांचल में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे से लेकर सड़क और भवन तक की मौजूदा ढांचागत परियोजनाएं इस क्षेत्र में हो रहे निवेश का प्रतीक हैं। जीआईएस ने उन निवेशकों के लिए विश्वास का एक माध्यम उत्पन्न किया, जो पहले यूपी के छोटे क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा में 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12%, औद्योगिक पार्कों में 11% और शिक्षा, लॉजिस्टिक्स में 9% निवेश भी हुआ है। असीम संभावनाओं वाला राज्य उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसने महज 8 साल की छोटी सी अवधि में अपनी संभावनाओं को तेज गति से बढ़ाया है। इसमें व्यवस्थित और पारदर्शी नीतियों की अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन ने राज्य के विकास को अमूल्य गति दी है। भारत की क्षमता और प्रतिभा ने मजबूत नेतृत्व के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो प्रदर्शन किया है, उससे देश को नई दिशा मिली है।

यह भी एक उपलब्धि है कि जी-20

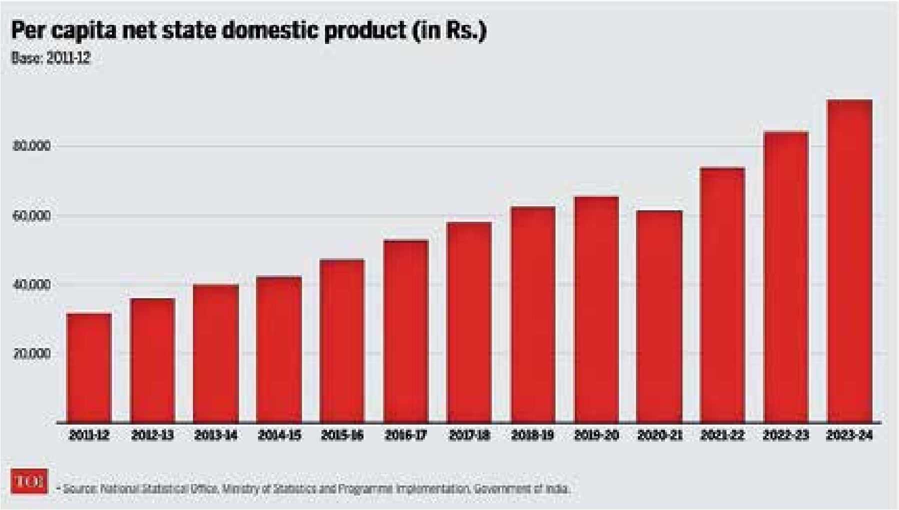

की 11 बैठकें चार महानगरों में हुईं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश को अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, बुनियादी ढांचे और विकास के दायरे और पैमाने को दुनिया के सामने रखने और राज्य को वैश्विक मानचित्र पर लाने का अनूठा अवसर मिला।

इसके ठोस परिणाम तब देखने को मिले, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय महाकुम्भ का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़ा। इस धार्मिक समागम को एक दिव्य आयोजन माना जाता था और दुनिया भर के पर्यटक इसका हिस्सा बनना चाहते थे, क्योंकि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी। राज्य को अब प्रगति के इंजन के रूप में देखा जा रहा है और आज की नीतियों से इसका भविष्य उज्ज्वल हो गया है।

अनुकरणीय आत्मनिर्भरता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का विजन रखा है। इस सपने को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार साकार कर रही है और राज्य इस विजन में 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने की राह पर है। भविष्य का ऐसा साहसिक विचार तभी संभव है जब सरकार के पास सच्ची नीयत, पारदर्शी नीतियां, वित्तीय अनुशासन हो।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए अपना सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो अमृत काल को दर्शाता है। यह 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट है जिसमें विकास और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र 'सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन' से संकेत लेते हुए, यूपी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी बजट के माध्यम से अपने भविष्य का खाका पेश किया है। ज्ञान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गढ़ा गया एक संक्षिप्त नाम था, जो 'गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति' का प्रतीक है - राष्ट्र के चार प्रमुख वर्ग जिनके प्रति समर्पित हैं। 2024-25 के लिए यूपी सरकार की राजकोषीय रणनीति एक ऐसे बजट से शुरू हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस कदमों की रूपरेखा तैयार की गई है। नया बजट प्रगति और कल्याण केंद्रित है सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुआई वाली सरकार ने पहले ही नीतियों, बुनियादी ढांचे और योजनाओं का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश में 'जीवन को सुगम' और 'कारोबार को आसान' बना रहा है और नई वित्तीय योजना - जो यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी है - ने

कानून और व्यवस्था

- 2016 से अब तक डकैती के मामलों में 85% की भारी गिरावट आई है।
- चोरी के मामलों में 77% की कमी दर्ज की गई है।
- हत्या के मामलों में 41% की गिरावट आई है।
- दहेज हत्या के मामलों में भी उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

कृषि

- राज्य की कृषि विकास दर 2016–17 में 5% थी, जो अब बढ़कर 13.70% से अधिक हो गई है।
- किसानों के 36,000 करोड़ के ऋण माफ किए गए।
- 2016–17 में खाद्यान्न उत्पादन 557 लाख मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष बढ़कर 725.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया। यानी लगभग 20% की वृद्धि।

प्रगतिशील और सीखने के लिए तैयार रहने की मानसिकता के साथ राज्य के मंत्री प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम के साथ आईआईएम-लखनऊ गए और वहां आयोजित पहले 'मंथन' मॉड्यूल में भाग लिया।

राज्य को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया है। पिछले 8 वर्षों में यूपी की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। राज्य की जीडीपी में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है। विकास की गति ऊपर की ओर है और इस सरकार के लिए आसमान ही सीमा है।

एमएसएमई से संवार रहे राज्य का भविष्य

राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं जैसे आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षा आदि पर विशेष जोर देते हुए कई अन्य सुविधाओं को लगातार बढ़ा रही है, साथ ही बुनियादी ढांचे, बिजली, सिंचाई और शहरी विकास पर भी जोर दे रही है। ओडीओपी योजनाओं और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, सरकार 155 औद्योगिक समूहों को एक समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना बना रही है। इस रणनीतिक कदम से यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) द्वारा प्रशासित इन क्लस्टरों की 50,000 से अधिक औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। समर्पित ई-कॉम पोर्टल यूपीसीडा द्वारा विकसित किया जा रहा है, और यह इन 155 क्लस्टरों में काम कर रहे कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं और तैयार माल विक्रेताओं को जोड़ेगा।

निवेशकों के लिए डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में निवेश मित्र पहले से ही चालू है, जिसमें उद्यमी 37 विभागों की लगभग 454

सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 'अचीवर स्टेट' बन गया है।

परिवहन के नए रास्ते तैयार करना

आज उत्तर प्रदेश को भारत की 'एक्सप्रेसवे राजधानी' के रूप में जाना जाता है। इनमें से 7 संचालित हैं, जबकि शेष पर काम जोरों पर है। पिछले 8 वर्षों में, डबल इंजन सरकार ने एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को अभूतपूर्व गति और विकास के नए रास्ते उपलब्ध कराए हैं। आस-पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। 2017 से पहले, केवल 4 हवाई अड्डे चालू थे और अब यह संख्या 16 तक पहुंच गई है। राज्य में चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी चालू हैं, और जेवर में एक निर्माणाधीन है। अगले एक से डेढ़ साल में, यूपी में 21 हवाई अड्डे होंगे। पूरा होने पर जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।

सेहतमंद राज्य है समृद्ध राज्य

कोविड-19 महामारी ने कई देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों को पंगु बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

ने सबसे आगे रहकर लड़ाई का नेतृत्व किया और सरकार ने कई नई चुनौतियों का मुकाबला किया जो अपनी तरह की अनूठी थीं। महामारी से निपटने के लिए अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक राज्यव्यापी टीम तैनात की गई थी। मामलों की पहचान की गई और उन्हें स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए अलग किया गया। स्थिति की नियमित निगरानी की गई और टीम को निर्देश दिए गए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त और समय पर संसाधन (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा दोनों) उपलब्ध हों। महामारी के दौरान, 16.88 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई उत्तर प्रदेश में कुल टीकाकरण 39.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। राज्य अब स्वास्थ्य सेवा में 'एक जिला एक मेडिकल कॉलेज' की नीति पर काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में, राज्य भर में कई मेडिकल कॉलेज चालू हो गए हैं और लगभग 22 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। विशेष संचारी रोग नियंत्रण/ दस्तक अभियान के तहत एईएस-जेई वायरस के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया गया। सीएम के प्रयासों से पूर्वांचल इंसेफेलाइटिस से मुक्त हो गया। आज इस बीमारी से होने वाली मौतों पर 96% तक नियंत्रण पा लिया गया है।

हर तरफ प्रगति

पिछले 8 वर्षों के स्मरणीय और दीर्घकालिक निर्णयों में से एक किसानों का 36,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ करना रहा है। किसानों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं।

NEW
INDIA'S
GROWTH
KEN
HALL 1
IT & ELECTRONICS

1 ट्रिलियन-डॉलर विज़न

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर

1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। व्यापक सुधारों, योजनाबद्ध नीतियों और नवोन्मेषी पहलों के माध्यम से प्रगति करते हुए महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ा रहा है।

प्रति व्यक्ति आय

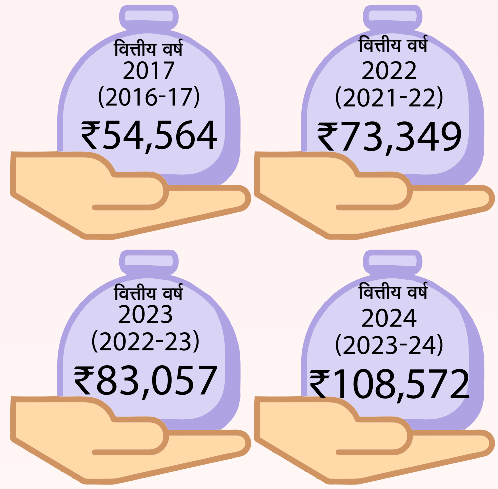

पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राज्य का लगातार बढ़ता वार्षिक बजट और साथ ही राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में तेजी से हुई वृद्धि। इन दोनों ने मिलकर प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की यात्रा को और सरल बना दिया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उत्तर प्रदेश के बजट की सबसे खास बात यह है कि अब यह केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित आवंटन के जरिए विकास का माध्यम बन चुका है। पहले जहां बजट महज एक औपचारिक वार्षिक अभ्यास माना जाता था, वहीं पिछले आठ वर्षों में यह विकास की ठोस दिशा देने वाला दस्तावेज बन गया है।

बजट का आकार वर्ष 2018-19 में 4,28,760.94 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 8,08,736.06 करोड़ हो गया है, यानी लगभग दोगुना हो गया है। उदाहरण के लिए, 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) 30.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2024-25 की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। यह एक वर्ष में ही घातांक वृद्धि है।

2025-26 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 2.6% (79,516 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान स्तर पर राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 2.1% (59,008 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है।

2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% (91,400 करोड़ रुपये) रहने का लक्ष्य है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2024-25 में

राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.4% रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025-26 का नवीनतम बजट राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा है, जिसमें 22% बुनियादी ढांचे, 13% शिक्षा और 11% कृषि के लिए आवंटित किया गया है। राजकोषीय घाटा 2.97% दर्ज किया गया, और कुल ऋण 9,03,924.54 करोड़ रुपये रहा।

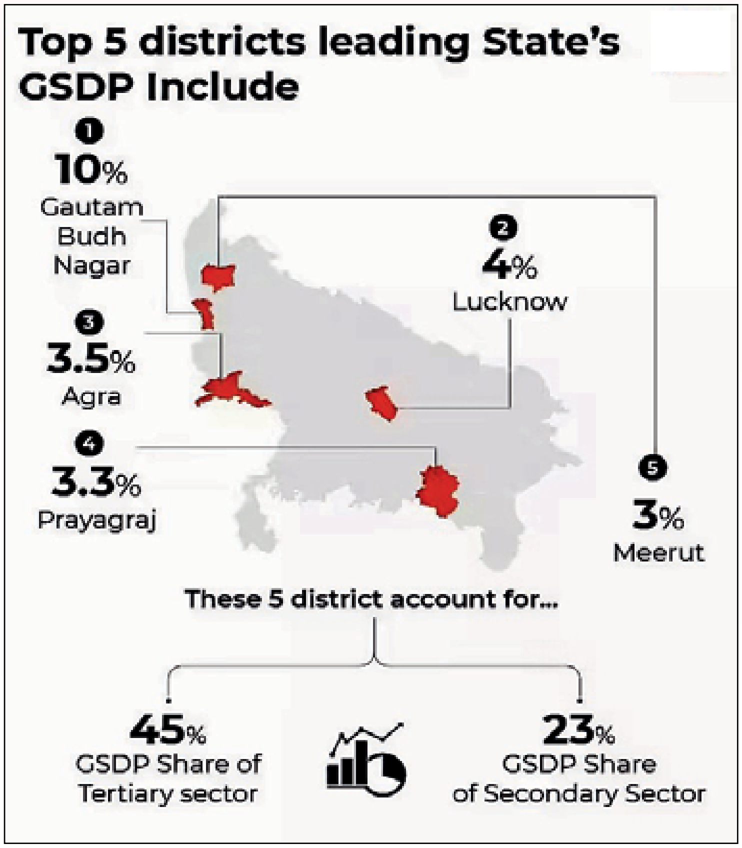

- 2025-26 का बजट 2024-25 के बजट की तुलना में 9.8% की वृद्धि दर्शाता है।
- बजट आकार में वृद्धि राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के अनुरूप है, जैसा कि हालिया बजट घोषणाओं में उजागर किया गया है।
- स्वास्थ्य : उत्तर प्रदेश ने 2025-26 में स्वास्थ्य पर अपने व्यय का 6.6% आवंटित किया है। यह 2024-25 में राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए औसत आवंटन (6.2%) से अधिक है।
- ऊर्जा : उत्तर प्रदेश ने 2025-26 में ऊर्जा के लिए अपने व्यय का 6.7% आवंटित किया है। यह 2024-25 में राज्यों द्वारा ऊर्जा के लिए औसत आवंटन (5%) से अधिक है।

भागीरथ प्रयास से तीव्र विकास

उत्तर प्रदेश जीआईएस 2023

फरवरी 2023 में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ने दुनिया को उत्साहित कर दिया। साथ ही, निवेशकों को राज्य की प्रगति ने प्रभावित किया है।

उत्तर प्रदेश अपनी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को धरातल पर उतारने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसकी झलक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में भी देखने को मिली। यूपी ने विश्व के सामने अपनी क्षमता और कार्यकुशलता को प्रदर्शित किया। 10 साझेदार देशों (नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, इटली और मॉरीशस) ने भी समिट को सफल बनाने में भरपूर योगदान किया। 40 देशों से लगभग 1000 प्रतिनिधियों और 25000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने 'निवेश महाकुम्भ' में हिस्सा लिया।

इन्वेस्टर्स समिट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश-विदेश के उद्योग जगत के दिग्गजों का स्वागत किया। समिट में आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन सुनील वच्छानी, ज्यूरिख एयरपोर्ट एशिया के सीईओ डेनियल बर्चर समेत कई प्रमुख निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश एमओयू हुए। इस निवेश से 1.1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर का सृजन होगा।

कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने वाली स्थिर सरकार है। राजनैतिक परिवेश की स्थिरता और प्रशासन की कार्यकुशलता से निवेशक आकर्षित हुए हैं। राज्य ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान दिया है। इससे आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि यूपी ने नई पहचान बनाई है। प्रदेश को सुशासन, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। प्रदेश में बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। यूपी का यह विकास पूरे विश्व से निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। राज्य समग्र विकास का साक्षी बन रहा है। यहां व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) ने निवेशकों

विभिन्न स्थानों पर यूपी के मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा आयोजित रोड शो में सम्मिलित तथा बी2बी बैठकों की जबरदस्त सफलता ने 10 लाख करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की, जो मुख्य कार्यक्रम से बहुत पहले हासिल कर लिया गया था और लक्ष्य को संशोधित करना पड़ा।

की सोच को बदला है।

आज का उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए एक उम्मीद बन गया है और देश के विकास को गति दे रहा है। सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो काम हुए हैं, उनसे प्रदेश को काफी लाभ हुआ है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 को मील का पत्थर कहना सही होगा। यह आयोजन प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं पर खरा उतरा। इसने एक ओर जहां निवेशकों को निवेश के लिए आधार दिया, वहीं युवाओं के सपनों को नए पंख दिए। प्रदेश के युवा 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपनों को साकार करने की दिशा में अहम योगदान दे सकते हैं।

आयोजन की सफलता के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को बताया कि हमारे पास ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र' पर 37 विभागों की 454 सेवाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश में निवेशकों की सहायता के लिए 'उद्यमी मित्र' तैनात किए जा रहे हैं। मैं न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, बल्कि ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में भी विश्वास रखता हूं।

यह तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म विजन को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश ने बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश के लिए अनुकूल माहौल स्थापित किया है। प्रदेश में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। जीआईएस-2023 की सफलता इसी का परिणाम है। योगी सरकार अब निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत 'उद्यमी मित्र'की नियुक्ति कर रही है। वे निवेशकों से सपंर्क स्थापित कर निवेश में आने वाली उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में किसी भी ऊंचाई तक जाने का पूरा सामर्थ्य है। मैं इस प्रदेश की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। आने वाले समय में यूपी का डिफेंस कॉरिडोर देश की सामरिक शक्ति का बैकबोन साबित होगा। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर,

निवेश से बदला परिवेश

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास की अनुकरणीय यात्रा की है। राज्य को अब प्रगति के इंजन के रूप में देखा जा रहा है और आज की नीतियों से इसका भविष्य उज्ज्वल हो गया है। इस दौरान राज्य में हुए विभिन्न आयोजनों ने न केवल देश बल्कि विदेशों से भी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वर्तमान में यूपी प्रधानमंत्री के विजन 'रिफॉर्म, परफॉर्म ट्रांसफॉर्म' को आत्मसात करके 'देश के विकास इंजन' की भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। 33 सेक्टोरल नीतियां लागू की गई हैं, 'निवेश मित्र' पोर्टल पर 37 विभागों की 454 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

नौकरियों और रोजगार के अवसरों का सृजन

- 40 देशों की भागीदारी
- देशों की पार्टनर कंट्री के तौर पर सहभागिता
- 25000+ प्रतिनिधि
- 1000 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि
- 1100 बी2बी मीटिंग
- 500 बी2जी मीटिंग
- 16 देशों के 21 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन हुआ
- 10 घरेलू रोड शो
- 75वां जिला निवेशक सम्मेलन
- 40 लाख करोड़ रुपये का निवेश
- 26,954 एमओयू
- 1.1 करोड़ रोजगार के अवसर

कनेक्टीविटी पर बहुत तेज गति से काम हुआ है। योगी सरकार ने यूपी को निवेश अनुकूल बना दिया है।

जीआईएस-2023 में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश सरकार की उदार नीतियों पर पूरा भरोसा जताया और राज्य को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बताया। इस दौरान उद्योग जगत की तमाम हस्तियों ने प्रदेश की स्थायी प्रगति की इस यात्रा में भागीदार बनने की अपनी स्पष्ट मंशा भी व्यक्त की। यूपीजीआईएस में 26,954 एमओयू साइन हुए हैं। यह इस बात का साक्षी है कि यूपी प्रधानमंत्री के विजन 'रिफॉर्म, परफॉर्म ट्रांसफॉर्म' को आत्मसात करके 'देश के विकास इंजन' की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आज का प्रदेश उत्तम कानून-व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग अनुकूल नीतियों वाला राज्य बन चुका है। यहां निवेश करके अपार अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों के साथ 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश एमओयू के साथ प्रदेश ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इसे 'निवेश महाकुम्भ' की संज्ञा दी गई। इस मंच से प्रदेश सरकार ने देश और विदेश के कॉर्पोरेट दिग्गजों के सामने अपनी असीम क्षमता का प्रदर्शन किया। वैश्विक निवेशकों के बीच नए भारत व उत्तर प्रदेश के विकास का विषय चर्चा का केंद्र रहा। इसके समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, तो देश भी समृद्धशाली बनेगा।

आज का उत्तर प्रदेश नए लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा चुका है। ग्रोथ इंजन के रूप में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ निवेश क्षेत्र के तौर पर वैश्विक समुदाय की मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। देश के किसी एक राज्य में संख्या के लिहाज से यह सबसे अधिक है। देश के उद्योगों का आधार होने के अलावा एमएसएमई, कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। यहां का एमएसएमई सेक्टर भविष्य में देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनेगा। प्रदेश ने एमएसएमई सेक्टर को पर्याप्त मजबूती दी है। यूपी में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। प्रदेश में सड़क परिवहन, राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे का बढ़ता नेटवर्क यहां के आर्थिक विकास को गति दे रहा है।

प्रदेश की एक जनपद- एक उत्पाद योजना को देश के दूसरे राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही योगी सरकार की इस पहल की प्रशंसा कर चुके हैं। यह राज्य की सफल नीतियों का परिचायक है। इसने पारंपरिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर आर्थिक सबलता दी और स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया है। यूपी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया है।

यूपी को मिली बजट की शक्ति

बजट: 2025-26

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा,राज्य के बजट के आकार में वृद्धि डबल इंजन सरकार की प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास' के विजन का भी प्रतिबिंब है।

राज्य का 2025-26 का बजट राज्य के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में एक ऐतिहासिक कदम है। बजट में परिकल्पित नीतियां सफलता की कहानी को आगे बढ़ाएंगी इसमें किसी को कोई संदेह नही है।

बजट की नींव 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के विचारों पर आधारित है जो भारत की संस्कृति का सम्मान करती है। सरकार के लिए, समग्र विकास पहले दिन से ही प्राथमिकता रही है। और सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण साथ-साथ चलें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज का हर वर्ग सरकारी योजना से लाभान्वित हो सके।

आर्थिक और औद्योगिक विकास के नजरिए से, कोई भी देख सकता है कि बजट में बुनियादी सुविधाओं के विकास से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की पहल तक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत रूपरेखा शामिल है। 2025-26 के बजट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है, जिससे आम आदमी का जीवन बदल जाएगा।

यूपी बजट की अहम बातें:

- 2025-26 के लिए जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुमान 11.85% की वृद्धि दर दर्शाते हैं
- प्रति व्यक्ति आय 2016-2017 में 54,564 रुपये से बढ़कर 2024-2025 में 1,88,572 रुपये हो गई है
- यूपी सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के स्तर तक पहुंचने के लिए उच्च विकास दर का लक्ष्य बना रही है।
- उत्तर प्रदेश ऋण-जीएसडीपी अनुपात को लगभग 30% तक कम करने में सक्षम रहा है, जिसे 2025-26 में 29.4% होने का अनुमान है। इस प्रवृत्ति को जारी रखने की आवश्यकता है।
- आर्थिक अनुशासन बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसमें एफआरबीएम सीमा शामिल है, जो वर्तमान में 3.5% है।
- बजट में 28,478.34 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। राजस्व बचत 79,516.36 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

- यूपी ने 2025-26 में अपने नकद-जमा अनुपात को मौजूदा 67% से बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य रखा है।

महत्वपूर्ण विशेषताएं: यूपी का बजट 2025-26 कुल बजट कोष 8,08,736.06 करोड़ रुपये है, जिसमें बुनियादी ढांचे, उद्योग, गतिशीलता और निवेश प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नया बजट पिछले वर्ष के 7,36,437 करोड़ रुपये के परिव्यय से अधिक है, जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की योजनाएं शामिल थीं। कुल सात एक्सप्रेसवे विकसित किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच संपर्क प्रदान करते हैं।

- विकलांग रखरखाव अनुदान के लिए 1,424 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए योजना निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान के लिए 2,980 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

- मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो आकस्मिक मृत्यु/विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- बेटियों (सभी श्रेणियों) की शादी के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दूरी के कारण स्कूल छोड़ने वाले छात्र हैं।
- राज्य के बुनकरों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना शुरू की गई।
- पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी में बदलने की योजना को मंजूरी दी गई। उज्ज्वला योजना के तहत दो मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।
- सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन काम के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए 24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 8 डाटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे।

वर्ष-दर-वर्ष बढ़ता यूपी का बजट आकार

2018-19
₹4,28,760.94 करोड़

2019-20
₹4,79,701.10 करोड़

2020-21
₹5,12,860.79 करोड़

2021-22
₹5,50,270.78 करोड़

2022-23
₹6,15,518.97 करोड़

2023-24
₹6,90,242.43 करोड़

2024-25
₹7,66,513.36 करोड़

7,36,437.71 करोड़ (मुख्य बजट) +12,209.93 करोड़ (प्रथम अनुपूरक) +17,865.72 करोड़ (द्वितीय अनुपूरक)

2025-26
₹8,08,736.06 करोड़

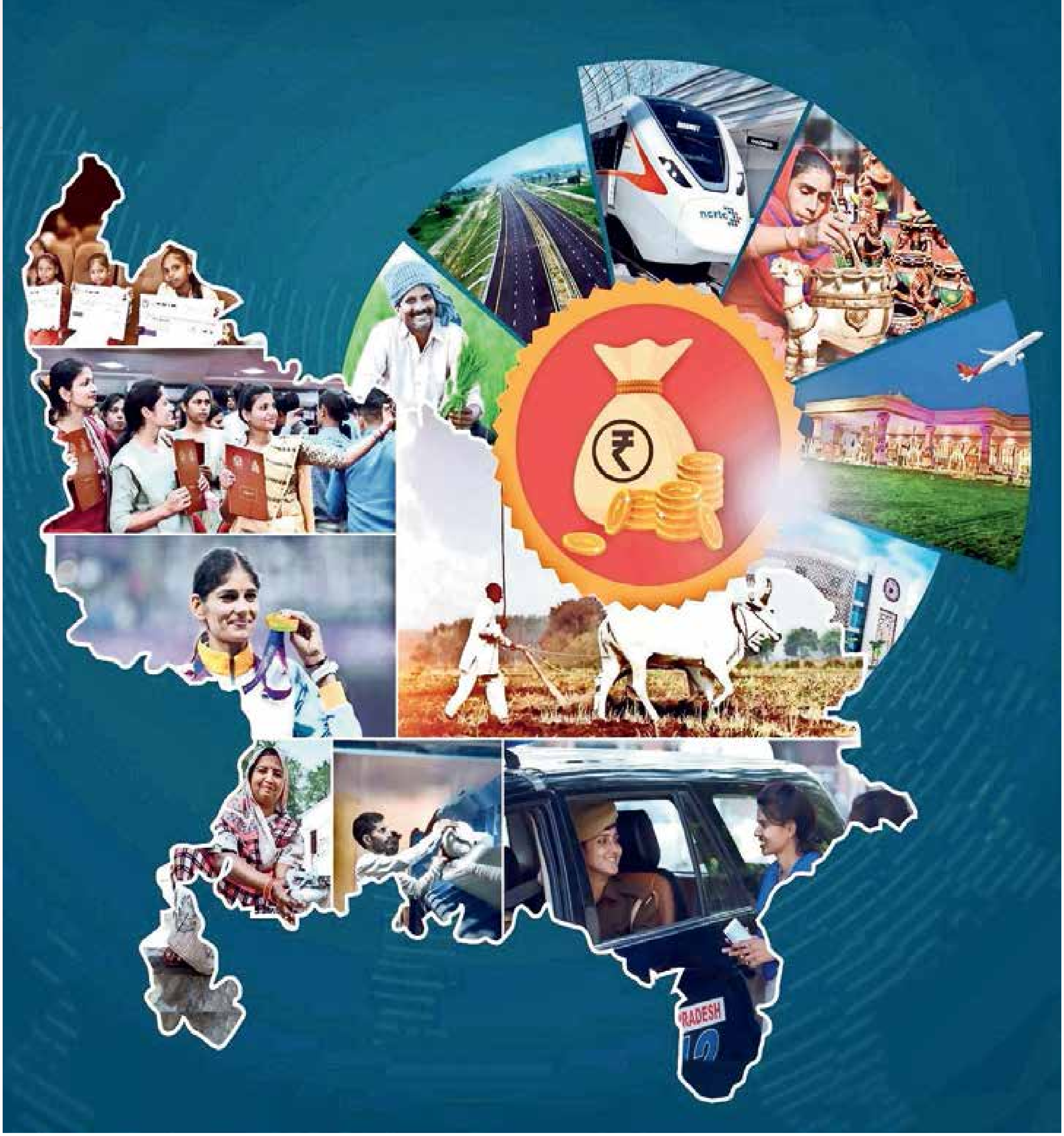

- सामान्य वर्ग के पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित
- मुख्यमंत्री हरित सड़क योजना के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित
- साइबर सुरक्षा में तकनीकी शोध के लिए पार्क की स्थापना को मंजूरी
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगारों/श्रमिकों के लिए अड्डे बनाने की योजना बना रहा है, जहां कैंटीन, पेयजल, स्नानघर, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- यूपी सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2024 से 'जीरो पॉवर्टी अभियान' शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनकी वार्षिक आय कम

से कम 1,25,000 रुपये तक पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है।

बजट की मुख्य विशेषताएं

- विधानसभा का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, जो एक संस्था के रूप में बीआर अंबेडकर की विचारधारा को बढ़ावा देगा और यूपी में संवैधानिक मूल्यों को लागू करेगा।
- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अयोध्या में भविष्योन्मुखी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है।

बुनियादी ढांचे के एक्सप्रेसवे से उन्नयन

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे (कौसिया, जिला हरदोई) तक एक प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण इसके निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपये आवंटित किए गए मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार को 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

कृषि का हरित भविष्य बीज पार्क विकास

उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति, 2024 के तहत बीज पार्क विकास परियोजना को कुल 251 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसके लिए 124 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 509 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। कृषि क्षमता, कौशल विकास और उत्पादन वृद्धि को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रमों के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए करीब 86 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

यूपी का गौरव-पर्यटन

यह सर्वविदित तथ्य है कि यूपी देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। यह राज्य इतिहास और संस्कृति का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। हाल के दिनों में देश और दुनिया भर से धार्मिक पर्यटन में भारी वृद्धि हुई है। सरकार अपनी बजटीय नीतियों के माध्यम से इसे बढ़ावा देने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास अभियान के लिए अपने 2025-26 के बजट के हिस्से के रूप में धार्मिक पर्यटन के लिए 400 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं।

प्रमुख तीर्थ जिलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- अयोध्या में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- भगवान कृष्ण से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्थान मथुरा में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 125 करोड़ रुपये मिले हैं।
- श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के मथुरा वृंदावन कॉरिडोर को 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- वैदिक ज्ञान और अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- पर्यटन पहलों का समर्थन करने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर और मां काली खोह मंदिर सहित मिर्जापुर के प्रमुख मंदिरों में भूमि खरीद और बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- उत्तर प्रदेश में संरक्षित मंदिरों का हो रहा पुनर्निर्माण। भगवान राम से जुड़े होने के कारण प्रसिद्ध चित्रकूट के लिए पर्यटन के सुधार के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत

कानून और व्यवस्था तथा राज्य न्यायपालिका को सशक्त बनाना

कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में राज्य में कानून प्रवर्तन, न्यायिक बुनियादी ढांचे और फौरेंसिक विज्ञान के सुधार के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया गया है।

- अभियोजन सेवाओं, पुलिस बुनियादी ढांचे, फौरेंसिक सुविधाओं और जेल विकास के लिए 338.62 करोड़ रुपये आवंटित
- राज्य में बहुमंजिला पुलिस भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित
- वाराणसी, चंदौली, संत कबीर नगर और गाजियाबाद जैसे जिलों में नए अभियोजन कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित। आगे की धनराशि ललितपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा और फिरोजाबाद में कार्यालय। बुनियादी ढांचे का हो रहा कायाकल्प।
- महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में तैनात

तीन महिला-विशिष्ट प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) बटालियनों के लिए वाहनों की खरीद के लिए 20.76 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया।

- अपराध स्थल की जांच को और अधिक कुशल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य फौरेंसिक विज्ञान संस्थान के लिए वाहन खरीद के लिए 3.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- अग्नि प्रतिक्रिया तंत्र को आधुनिक बनाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए नए अग्निशमन वाहनों की खरीद के लिए 62.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और अर्ध-सरकारी पुलिस भवनों पर सौर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- प्रयागराज जेल सहित जिला कारागारों के लिए मोटरसाइकिल और वाहनों की खरीद के लिए 92.8 लाख रुपये की मंजूरी।
- छह प्रमुख जेलों में ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए 88.36 लाख रुपये स्वीकृत
- रेलवे सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 25 लाख रुपये आवंटित किए गए।
- अभियोजन विभाग के तहत गुप्त सेवा व्यय के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

10 महान विभूतियों के नाम पर शुरू की गई योजनाएं

राज्य सरकार ने देश की 10 प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित करते हुए उनके नाम पर कई नई योजनाएं और संस्थान आरंभ किए हैं:

- कृषि मंडियों में माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामगृह
- सरदार पटेल के नाम पर जिला आर्थिक क्षेत्र
- अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर महिला छात्रावास
- छात्राओं को स्कूटी वितरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना
- संत कबीर के नाम पर 10 टेक्सटाइल पार्क
- चौधरी चरण सिंह के नाम पर बीज पार्क
- अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शहरी/डिजिटल पुस्तकालय
- बिरसा मुंडा के नाम पर आदिवासी संग्रहालय
- संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क

एक अभूतपूर्व उपलब्धि

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता का परिणाम था, जिसका उद्देश्य राज्य में ऐसे स्तर पर निवेश लाना था, जिसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री ने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए प्रदेश को एक नई ऊंचाई प्रदान की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निवेश पर जब यह कहा तो उनकी सकारात्मक सोच और प्रगतिशील विचारधारा का पता चल गया- "उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्निहित ताकत, वर्तमान जनसांख्यिकी और भविष्य की विकास संभावनाओं के साथ आकर्षक निवेश स्थल बन गया है। हमारी नीतियों का उद्देश्य समावेशी, सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। हम देश में सबसे बेहतरीन कारोबारी माहौल और उत्तरदायी नीतिगत ढांचे प्रदान करते हैं।"

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का विचार मुख्यमंत्री का एक ऐसा विजन था, जिससे निवेश को अभूतपूर्व पैमाने पर लाया जा सके। पहले की सरकारों ने उद्योगों में निवेश को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया था, जिससे राज्य विकास के क्षेत्र में पीछे की ओर चला गया था। योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में सकारात्मक रुख का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को एक अलग स्तर पर लाने के लिए अकेले ही राजनीति से ऊपर उठकर काम किया।

2018 से आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ने 1 ट्रिलियन डॉलर के विज़न और देश के आर्थिक कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। जो कंपनियां कभी राज्य में निवेश को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थीं, वही अब राज्य के भविष्य को संवारने की दिशा में योगदान दे रही हैं।

आर्थिक विशेषज्ञ और संस्थाएं अब तेजी से यह स्वीकार कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में विकसित भारत के विकास का साधन बनने की क्षमता है। हाल ही में लखनऊ में नियोजन विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में कहा गया कि राज्य में अपार आर्थिक सफलता की क्षमता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सबसे पसंदीदा निवेश स्थलों के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित रिफॉर्म-परफॉर्म-ट्रांसफॉर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास पर महत्वपूर्ण जोर देते हुए विकास के एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है, जिसमें प्रभावशाली शासन सुधार, एक संरचित कानून और व्यवस्था की स्थिति, प्रगतिशील नीतियां और हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, औद्योगिक गलियारों और अन्य को शामिल करते हुए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है।

पहला उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन 29 जुलाई, 2018 को आयोजित किया गया था, और दूसरा अगले साल 28 जुलाई को हुआ था। पहले ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में 61,800 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 81 परियोजनाएं शुरू की गईं,

जबकि दूसरे में 67,000 करोड़ रुपये की 290 परियोजनाएं आकार लेती नजर आईं। 2022 में हुए तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में कॉरपोरेट और उद्योग जगत के 60 से अधिक प्रमुखों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में 75,000 करोड़ रुपये की लगभग 2,000 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की मेजबानी करने के बाद, राज्य एक वर्ष की छोटी अवधि में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश और 33.50 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ 14000 से अधिक परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम रहा है। पिछले साल जीबीसी 4.0 आयोजित किया गया था और ग्राउंडब्रेकिंग समारोह के पांच महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में 1.14 लाख करोड़ रुपये की 3,984 परियोजनाओं ने वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। जीबीसी 4.0 के दौरान 14,701 परियोजनाओं में कुल 10.81 लाख करोड़ रुपये के निवेश को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए, जिससे 34 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। जीबीसी 4.0 ने उत्तर प्रदेश राज्य के चार क्षेत्रों और 75 जिलों में परियोजनाओं की शुरुआत की। उद्घाटन की गई परियोजनाओं में, उत्तर प्रदेश के आठ आकांक्षी जिले 1.57 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र सहित इन जिलों की पहचान प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत की गई है। कार्यक्रम का लक्ष्य क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक संरचना को बदलना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल के अंत में एक और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) आयोजित करने पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेश धरातल पर आकार ले सके। इसके अलावा नए निवेश को आकर्षित करने के लिए एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य सरकार 2029 तक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगी। सरकार ने राज्य सरकार की नीतियों का प्रचार करने, निवेशकों को आकर्षित करने और राज्य को सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए भारत और विदेशों के प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार की एक टीम ने ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में निवेश के विकल्प तलाशने के लिए जल्द ही जापान का दौरा करने का भी प्रस्ताव रखा है। आईटी, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ईवी और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न विकल्पों की भी योजना बनाई जा रही है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के प्रयास में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए दांव बढ़ा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि राज्य अगले 4 वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर के रास्ते पर हो। विभिन्न रोड शो आयोजित हुए जिसमें अहमदाबाद के रोड शो में फोकस सोलर पीवी मॉड्यूल और चिकित्सा स्वास्थ्य पर था जबकि मुंबई में टेक्सटाइल्स, रसद और भंडारण पर ध्यान केंद्रित करने वाले रोड शो आयोजित किये गए। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर क्षेत्रों पर फोकस के साथ बेंगलुरु, प्लेज पार्क और खाद्य प्रसंस्करण और फर्नीचर पर ध्यान केंद्रित करने वाले दिल्ली और कोलकाता और ,ऑटोमोबाइल और ईवी व शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले चेन्नई और हैदराबाद में सफल रोड शो आयोजित किए गए।

निवेश का प्रवेश

- जीबीसी 3.0 ने लगभग 3.35 मिलियन युवाओं के लिए रोजगार सृजित किया।
- पहले ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में 60,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव निष्पादित किए गए।
- ग्राउंडब्रेकिंग समारोह 4 .0 में 500 करोड़ रुपये से अधिक की 262 परियोजनाएं और 100-500 करोड़ रुपये की 889 औद्योगिक परियोजनाएं थीं, जिन्हें जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा।
- समारोह में 3,500 से अधिक निवेशकों ने हिस्सा लिया।
- सरकार ने बताया था कि ग्राउंडब्रेकिंग समारोह के चौथे संस्करण में 10 लाख करोड़ रुपये की कुल 14,000 परियोजनाएं निष्पादित की गईं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

भविष्य का निर्माण

बुनियादी ढांचे का विकास

उत्तर प्रदेश ने वैश्विक स्तर का आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और यह प्रगति बुनियादी ढांचे के हर पहलू को शामिल करती है।

किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगतिका पैमाना यह भी कि उसमें बुनियादी ढांचे को बनाने और संचालित करने की क्षमता है। प्राचीन काल में, सभ्यताओं का विकास हुआ क्योंकि अच्छे नेता आगे देखते थे। शहरों को सत्ताशीन लोगों के विचार और दृष्टि पर बनाया गया था। वे इतिहास का हिस्सा बनने के लिए गए जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की विकास की कहानी और इसकी विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना इसी कहानी को आगे बढ़ा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक टेम्पलेट बन जाएगा

देश में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने तेजी से विकास का खाका बनाया जिसमें महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की गई। बुनियादी ढांचे की परिकल्पना में

उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़े होने का तमगा हटा चुका है और अब यह प्रगतिशील श्रेणी में बदल गया है। उदासीनता के वर्षों और दिन चले गए हैं और राज्य अब उन्नत और विकसित

पूर्ण सड़कें (पीएमजीएसवाई)

- 2018-2019 – 56,002 किमी.
- 2019-2020 – 56, 379 किमी.
- 2020-2021 – 57, 089 किमी.
- 2021-2022 – 60,062 किमी.
- 2022-2023 – 65,133 किमी.
- 2023-2024 – 72,026 किमी.
- 2024-2025 – 75,080 किमी.

सड़क परियोजना व्यय (पीएमजीएसवाई)

- 2018-2019 – ₹16,288 करोड़
- 2019-2020 – ₹16,644 करोड़
- 2020-2021 – ₹17,084 करोड़
- 2021-2022 – ₹19,147 करोड़
- 2022-2023 – ₹21,959 करोड़
- 2023-2024 – ₹25,891 करोड़
- 2024-2025 – ₹28,567 करोड़

समाजों के साथ कंधा मिला रहा है। उत्तर प्रदेश ने वैश्विक स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। और इस प्रगति में बुनियादी ढांचे के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। डबल इंजन सरकार ने हमेशा विकास के आसपास ध्यान केंद्रित किया है और न केवल एक क्षेत्र को बढ़ाया है। राज्य में विकसित होने वाली हवा, पानी, सड़क और रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी, राज्य की उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों को भारत और विदेशों में बाजारों में अपने सामान भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न तरीकों को निर्बाध रूप से एकीकृत करने में सक्षम करेगी।

पिछले आठ वर्षों में सुशासन, विकास और नीतिगत सुधारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरह बदल गई है। परिणामस्वरूप, राज्य व्यवसाय और निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्यों में शामिल हो गया है

जलमार्ग यातायात

भारत में जलमार्ग परिवहन के क्षेत्र में छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर देश की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना शुरू करने के लिए पहला राज्य बन गया है। परियोजना को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (एनडब्ल्यू 1) के रूप में जाना जाता है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक फैली हुई है। वाराणसी से हल्दिया तक लगभग 1,100 किमी में जल यातायात पहले से ही परिचालित है। उत्तर भारत और कोलकाता बंदरगाह

के बीच एक गलियारे में आपूर्ति मार्ग और अन्य के लिए आपूर्ति मार्ग में विकसित करने की अत्यधिक संभावना है। एनडब्ल्यू 1 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख कैचमेंट क्षेत्र का 26% शामिल है और वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख निर्यात केंद्रों को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अज़्ी घाट और राजघाट (वाराणसी) जैसे राज्य में प्रमुख स्मारक इस दिशा में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। जलमार्ग अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक व्यापार और पर्यटन दोनों को सुविधाजनक राज्य के लिए बहुआयामी परिवहन और यात्रा मार्ग बनाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (एनडब्ल्यू 1) के तहत परिचालन सुविधाओं में वाराणसी में एक बहु मोडल टर्मिनल और गाजीपुर, राजघाट, रामनगर (वाराणसी) और प्रयागराज में फ्लोटिंग टर्मिनल शामिल हैं। इसके अलावा, दादरी में एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब और बोराकी में एक बहु मोडल ट्रांसपोर्ट हब का विकास रसद बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए प्रगति पर है।

एयरवेज

सरकार हमेशा ही चाहती रही है कि लोगों को जितना संभव हो सके हवाई यात्रा करने का अवसर होना चाहिए। हवाई यात्रा और मार्गों के नेटवर्क का विस्तार करने से हवाई यात्रा सस्ती बनाने के लिए, इस उद्योग में प्रगति का स्तर असाधारण रहा है। वायुमार्ग के प्रमुख पहलुओं में से एक है सही बुनियादी ढांचा है। बड़े पैमाने पर हवाई अड्डे, एकाधिक रनवे और समर्पित

विमानन सेटअप विमानन उत्तर प्रदेश में निर्बाध हवाई यात्रा सुविधाएं प्रदान करता है। प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बरेली, ग़ाज़ियाबाद हिंडन, अलीगढ़, आज़मगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और गोरखपुर समेत विभिन्न शहरों में राज्य में कुल 11 घरेलू हवाई अड्डे हैं। ये हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख शहरों और महानगरों को जोड़ते हैं, जिससे राज्य में आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। घरेलू उड़ानों के अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार अब अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए परिचालन की उड़ानें भी काम कर रही है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में कुल चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो दुनिया के प्रमुख स्थलों से कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में स्थित, ये हवाई अड्डे विदेशी यात्रियों के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक विनिमय की सुविधा के लिए बेहतर हवाई यात्रा विकल्प प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में जेवर में निर्माणाधीन नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने अंतिम चरणों में है और जल्द ही परिचालन किया जाएगा। यह देश के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक बनने के लिए तैयार है, जो लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जेवर हवाई अड्डा एनसीआर क्षेत्र का ताज होगा। हवाई अड्डे को एक स्विस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है जो विमानन बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञ है।

एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तुलना यूरोपीय फ्रीवे के साथ की जाती है। यह न केवल राज्य के विभिन्न हिस्सों को देश के केंद्र में जोड़ता है, यह व्यापार के लिए भी एक मार्ग खुलता है। औसत नागरिक को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लाभ देने से, सड़क की सबसे अधिक यात्रा करने वाला सड़क पुरानी कहावत को बदलने का सबसे अच्छा विकल्प है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण राज्य भर में क्षेत्रीय परिवहन और कनेक्टिविटी प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन ला रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे सात प्रमुख एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय में काफी कमी आई है, साथ ही श्रम और कच्चे माल की त्वरित ढुलाई से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं । इसके अलावा, राज्य में 5 और एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं, जिसके बन जाने से प्रदेश में कुल 12 एक्सप्रेसवे

हो जाएंगे। राज्य को एक एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आज उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत एक्सप्रेसवे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा । इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद, उत्तर प्रदेश में देश का 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा । गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना परियोजनाओं में से एक है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विकास मॉडल का शानदार उदाहरण के रूप में है। ,यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, अमरोहा, रायबरेली और प्रतापगढ़ से गुजरते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा।

पहले गंगा एक्सप्रेसवे ने हाल ही में दो विश्व रिकॉर्ड बना कर राज्य के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। हरदोई-उन्नाव डिवीजन में, 24 घंटे के भीतर 34.2 किलोमीटर के बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाने से एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई थी। प्रक्रिया में 20,105 घन मीटर बिटुमिनस मिश्रण को तैनात करके कैरिजवे के 0.17 वर्गमीटर क्षेत्र को कवर करने में शामिल प्रक्रिया, वैश्विक स्तर पर 24 घंटे में की गई उच्चतम निर्माण प्रगति। बिटुमिनस सामग्री बिछाने का पिछला रिकॉर्ड 2023 में गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर बनाया गया था। प्रति घंटे 200 टन की क्षमता वाले पांच गर्म मिश्रण संयंत्र प्रत्येक हार्डोई नोड को पूरा करने में मदद कर रहे हैं।

इस उपलब्धि में जोड़कर, एक द्वितीय विश्व रिकॉर्ड एक दिन में 10 किमी थ्री बीम क्रैश बाधाओं को स्थापित करके सेट किया गया था। देश में किसी भी एक्सप्रेसवे पर इन तरह का निर्माण कार्य पहली बार किया गया था। निरंतर मॉनिटरिंग द्वारा समर्थित

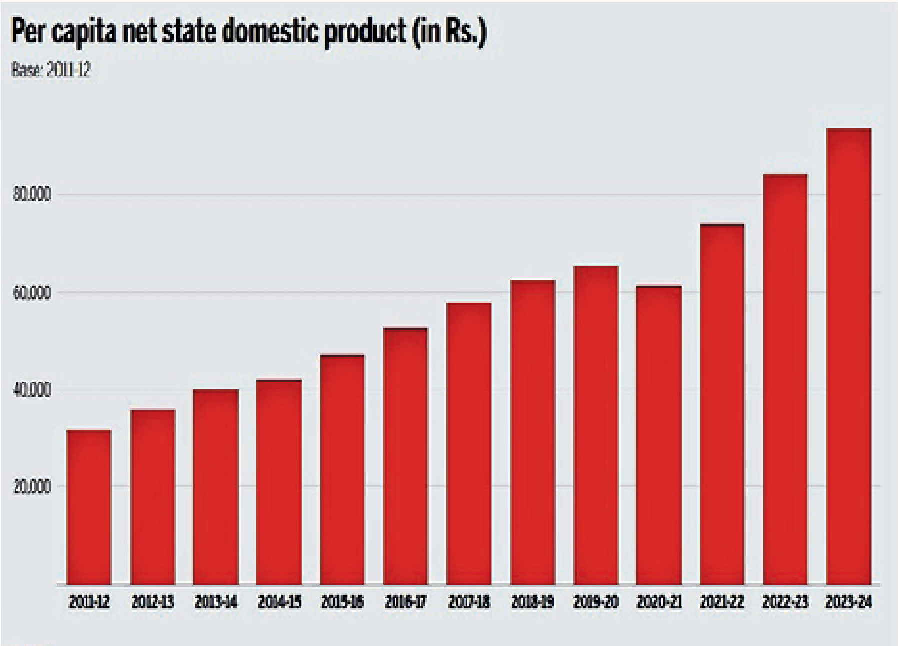

कानपुर मेट्रो का दूसरा चरण

- मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार से आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक की यात्रा केवल 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाएगी।
- पूरा कानपुर मेट्रो नेटवर्क 15 किलोमीटर लंबा हो जाएगा।
- 7 किलोमीटर का भूमिगत गलियारा चुन्नीगंज और कानपुर सेंट्रल को 5 स्टेशनों से जोड़ता है।
- कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण की लागत 2,000 करोड़ रुपये है और इसे निर्धारित समय से पहले केवल 3 साल और 4 महीने में पूरा किया गया है।

गति, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ यह योगी सरकार के अविश्वसनीय फोकस का एक अनुपम उदाहरण है। सीएम योगी ने अप्रैल के महीने में हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के प्रमुख वर्गों का निरीक्षण किया था, जिसमें शाहजहांपुर में आपातकालीन हवाई पट्टी और हापुड़ में गंगा सेतु शामिल थे, और अधिकारियों को समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए एक्सप्रेसवे की सवारी गुणवत्ता और उपयोगकर्ता सुविधा का मूल्यांकन एटीएच ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड द्वारा विकसित एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाता है।

हाल ही में 91 किलोमीटर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे समाप्त हो गया,

गोरखपुर से आजमगढ़ से जुड़ा हुआ, उद्घाटन के लिए तैयार है। यह लिंक न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि प्रमुख विनिर्माण केंद्रों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में भी कार्य करता है। पहले के समय में, एक समझ थी कि राज्य के पूर्वी हिस्से को अक्सर अनदेखा और उपेक्षित किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित किया कि विकास का मतलब राज्य के हर हिस्से को कवर करना है। सड़कों में रहने और बेहतर आजीविका के बेहतर मानक का एक आवश्यक घटक है। सड़कें वाहनों को नहीं लेती हैं बल्कि उन लोगों के सपने भी करती हैं जो दुनिया को अपने घरों से परे देखना चाहते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल और 11 विकास के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, बलिआ लिंक एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का अधिकतम हिस्सा है।

- चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़कर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबादके माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर हवाई अड्डे लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- इसके अलावा चार नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए प्रक्रिया जारी है _ विंध्य एक्सप्रेसवे मिर्जापुर वाराणसी-चंदौली - सोनभद्र (320 किमी), चंदौली से गाजीपुर तक पूर्वांचल

लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए स्पूर का निर्माण। चित्रकूट से रीवा मार्ग के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण, मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है।

- डिफेंस कॉरिडोर के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने अलग लकीर खींची है। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य और देश के भीतर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान संदर्भ में, यूपी में सबसे ज्यादा उपलब्ध श्रम बल है जो इसे देश में शीर्ष विनिर्माण स्थलों में से एक बनाता है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (डिफेन्स कॉरिडोर) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करने का इरादा रखती है। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, आगरा और चित्रकूट में 06 नोड्स में रक्षा औद्योगिक गलियारे का विकास हो रहा है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में इसकी एक बड़ी भूमिका है। रक्षा औद्योगिक गलियारे में, झंसी नोड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल विनिर्माण इकाई के तहत, 30 हजार करोड़ की कीमत की निवेश परियोजनाएं इस प्रक्रिया के तहत हैं, अब तक उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (अद्यतन) रुपये के निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार है 170 ज्ञापन के साथ 28,481 करोड़ रुपये (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 145 उद्योगों के साथ हैं, और शेष 25 संस्थानों के साथ हैं। भूमि को 57 उद्योगों को आवंटित किया गया है, जो अद्यतन के विभिन्न नोड्स में 9,463 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए तैयार हैं और 13,736 रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ, यह स्पष्ट हो गया है कि जब सैन्य कौशल की बात आती है तो देश तैयार है। हमारी सशस्त्र बलों ने बहादुरी का उदाहरण दिया और देश के संसाधन दाहिने हाथों में हैं। रक्षा कॉरिडोर का विकास केवल उन प्रमुख क्षेत्रों के अलावा जोड़ देगा, जिसमें बुनियादी ढांचा बनाया गया है, अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अपना मिशन बना दिया है कि राज्य को अपने डिजिटल दृष्टिकोण के संदर्भ में आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि इसे आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत चमत्कार बनाया जा सके। पार्कों का विचार सरल है क्योंकि न केवल निवेश के अवसरों को आकर्षित करता है; यह स्थानीय रोजगार भी उत्पन्न करता है। कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि राज्य को बुनियादी ढांचे में बदल दिया गया है

> आगरा में मेट्रो सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। पूरी तरह से संचालित होने पर आगरा मेट्रो में कुल 2 लाइनें होंगी, जिनकी लंबाई 29 .65 किलोमीटर होगी। पहले चरण में पीली लाइन (सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट) पर 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरे चरण में नीली लाइन (आगरा कैंट से कालिंदी विहार) पर 15 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।

- साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिक अनुसंधान पार्क स्थापित करने के लिए कार्रवाई प्रस्तावित।
- राज्य में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क (16,000 किमी से अधिक) है।
- भारत का पहला फ्रेट गांव वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित हुआ। राज्य के कुल मोबाइल विनिर्माण में राज्य का योगदान लगभग 45 प्रतिशत है। फिल्म सिटी, खिलौना पार्क, परिधान पार्क, हस्तशिल्प पार्क, रसद हब यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।
- ग्रेटर नोएडा में आईआईटी जीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, अन्नाओ में ट्रांसजंगा सिटी,

गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में परिधान पार्क और कई फ़्लैटेड फैक्ट्री परिसरों को विकसित किया जा रहा है।

- प्रधान मंत्री गाती शक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान को लागू करने के लिए अग्रणी राज्य।
- लखनऊ में प्रधान मित्रा मेगा वस्त्र चिह्न की नींव पत्थर रखी गई है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीआईडीए) के गठन ने 47 वर्षों के बाद एक नए शहर की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। बुंदेलखंड के बहुआयामी विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं और 06 औद्योगिक गलियारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित किए जा रहे हैं।
- बरेली के बहेड़ी में मेगा फूड पार्क का विकास
- ललितपुर, झांसी में 1472 एकड़ भूमि पर फार्मा पार्क की स्थापना और कन्नौज में इंट्रा पार्क की स्थापना की। "येडा' में चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना।
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत प्रयागराज और आगरा में प्रत्येक 1 एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना प्रक्रिया में है।
- लखनऊ में अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन मिशन का निर्माण किया जा रहा है।

मनोरंजन का 'कैलेडोस्कोप': योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट

फिल्म सिटी

यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही अपना खुद का फिल्म उद्योग होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों की बदौलत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा में जल्द ही साकार होने वाला है

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में स्थित इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण, मीडिया, मनोरंजन और पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डेवलपर का चयन पारदर्शी वैश्विक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर के स्वामित्व वाली डेवलपर कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने लगभग सभी प्रारंभिक कार्य पूरे कर लिए हैं। बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी को 18% की उच्चतम सकल राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश करके बोलीदाता के रूप में चुना गया था। कंपनी को पिछले साल यह कार्य मिला था। निर्माण स्थल का भू-तकनीकी सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है और कंपनी ने अपने बिल्डिंग प्लान को अंतिम रूप दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण पहले चरण में 13-14 आधुनिक फिल्म साउंड स्टूडियो और लगभग 3 लाख वर्ग मीटर में फैले एक फिल्म संस्थान के साथ शुरू होना है। पूरी परियोजना आठ वर्षों में तीन चरणों में पूरी होगी। फिल्म सिटी का विकास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-21 में कुल 1,000 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है। पहले चरण में 230 एकड़ जमीन शामिल होगी, जिसकी अनुमानित लागत 1,510 करोड़ रुपये है। भविष्य में, शेष 770 एकड़ जमीन को दूसरे और तीसरे चरण में विकसित किया जाएगा। YEIDA इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। भूमि अधिग्रहण से लेकर किसानों के मुआवजे तक सब कुछ पूरी पारदर्शिता

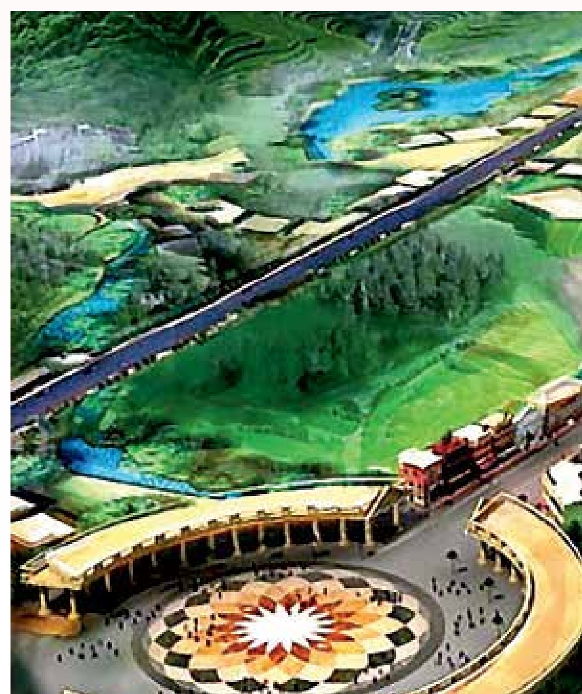

मिलेंगे अवसर अपार

- YEIDA ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के विकास के लिए 230 एकड़ जमीन सौंप दी है
- इससे 5-7 लाख रोजगार पैदा होंगे

के साथ किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करेगी, बल्कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

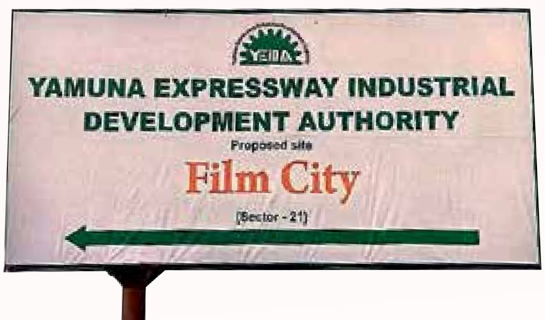

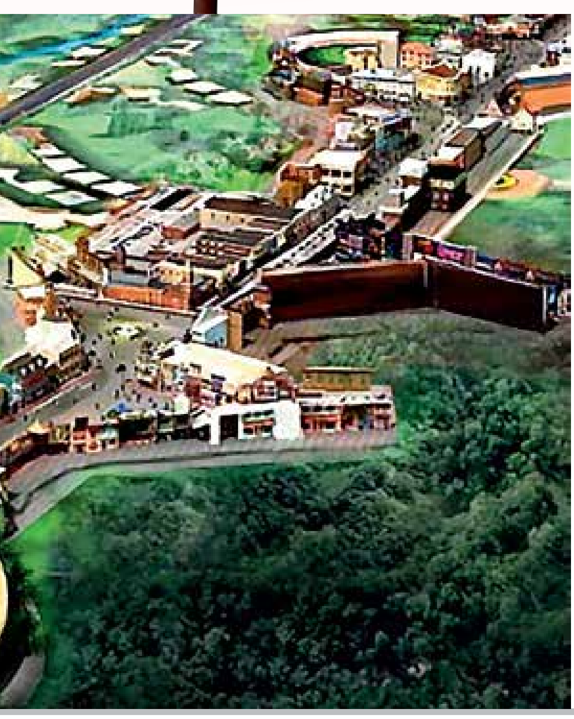

सपनों की रूपहली दुनिया

कई शूट शेड्यूल की सुविधा

1000 एकड़ के लैंडमार्क में कई स्टूडियो, फिल्म सेट और बैकलॉग होंगे। इसके अलावा, फिल्मों के निर्माण और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आवश्यक सभी प्रावधान और सुविधाएं इस फिल्म सिटी की सीमा के भीतर मौजूद होंगी।

पांच जोन

फिल्म सिटी को 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा - प्रवेश कार्यालय, शूटिंग और लॉजिंग क्षेत्र, थीम पार्क, बाहरी स्थान, विश्वविद्यालय / स्टूडियो और हवाई अड्डा।

स्पेशल इफेक्ट्स स्टूडियो

यहां क्लब हाउस, फूड कोर्ट सबकुछ होगा। फिल्म निर्माण, स्टूडियो, बाहरी स्थान, पोस्ट प्रोडक्शन, स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो, होटल, गांव, वर्कशॉप, पर्यटन और मनोरंजन, फिल्म विश्वविद्यालय, रिटेल और शॉपिंग एरिया, फूड कोर्ट, मनोरंजन पार्क,आतिथ्य, सम्मेलन केंद्र और खेल मैदान तक पहुंच आसान होगी। सुलभ सुविधाएं देने वाली सारी चीजें बेहद करीब और एक दूसरे से जुड़ी होंगी।

पर्यटन व मनोरंजन भी

फिल्म सिटी न केवल फिल्म निर्माण और प्रोडक्शन की मांग को पूरा करेगी, बल्कि पर्यटन और मनोरंजन के लिए इसे एक केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। यहां उद्यान, लैंडस्केप, मनोरंजन पार्क, होटल और रेस्तरां के साथ-साथ शॉपिंग और छुट्टी मनाने वालों के लिए और उनकी खरीदारी संबंधी जरूरतों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में विकसित किया जाएगा।

फिल्म के लिए वन स्टॉप शॉप

इसे कई स्टूडियो के साथ बनाया जाएगा, जिनमें से कुछ को राज्य की कला और शिल्प के लिए प्रदर्शनी के रूप में तैयार किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं को एक ही छत के नीचे प्री-प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएं और उनसे जुड़ी प्रौद्योगिकियां मिल सकेंगी।

गांव और बाहरी सेट

फिल्म सिटी में ग्रामीण पृष्ठभूमि और सेट के साथ राज्य विशिष्ट कथाओं वाला एक विशेष स्थान होगा। इसमें आउटडोर लोकेशन को भी शामिल किया जाएगा।

फिल्म विश्वविद्यालय

यहां छात्रों और फिल्म आधारित शोधकर्ताओं को प्रमुख मीडिया पेशेवरों द्वारा सलाह और सिखाने का अवसर मिलेगा और उद्योग में बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का अवसर भी मिलेगा। यह नौकरी प्रशिक्षण और सीखने वालों के लिए एक लाइव पेट्री-डिश जैसा होगा।

हेलीपैड और संग्रहालय

यह रिटेल सेंटर, फूड कोर्ट, एम्फीथिएटर, व्यूइंग गैलरी, हेलीपैड, टॉयलेट, एंटरटेनमेंट पार्क, म्यूजियम और कॉमन पार्किंग से परिपूर्ण होगी। संग्रहालय में भारतीय फिल्म उद्योग और इसकी विरासत को दर्शाने वाली कलाकृतियां और प्राचीन संग्रह होंगे।

फाइव स्टार आतिथ्य से लेकर बजट होटलों तक की सुविधा

इसमें फाइव स्टार और थ्री स्टार होटल होंगे। इसके अलावा, बजट होटल, डॉर्मेट्री और कन्वेंशन हॉल भी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का लक्ष्य यूनिवर्सल स्टूडियो, पाइनवुड स्टूडियो, वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, बॉलीवुड संग्रहालय, सेवन वंडर्स, शूटिंग फ्लोर के साथ टिकट और सूचना केंद्र की सुविधा भी प्रदान करना है।

औद्योगिक विकास

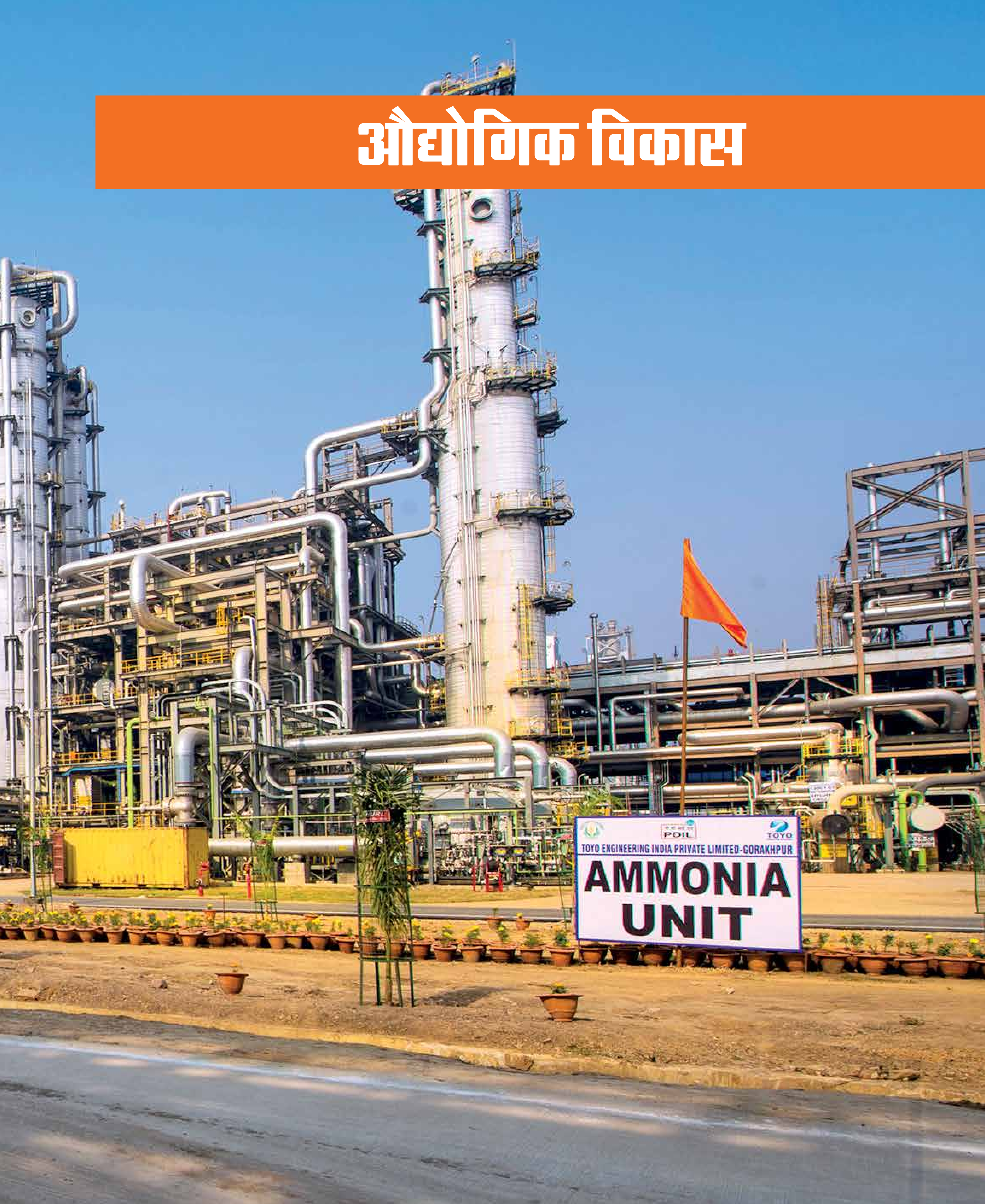
PDIL
TOYO
TOYO ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED-GORAKHPUR
AMMONIA
UNIT

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चल रहा औद्योगिकीकरण का स्वर्णिम युग

एमएसएमई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

देश की सबसे तेजी से बढ़ती राज्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक, उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी है, निवेश-उन्मुख नीतियां लागू की हैं और समग्र व्यावसायिक माहौल में अभूतपूर्व सुधार किए हैं।

पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और भारत में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरा है। देश में सबसे तेजी से बढ़ती राज्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार मूलभूत सुविधाओं के विकास में तेजी लाई है, निवेश-उन्मुखी नीतियों की घोषणा की है और कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किए हैं, जिससे राज्य की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से प्रगतिशील राज्य में बदल गई है।

कानून-व्यवस्था और बिजली आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, सक्रिय नीति निर्माण और इन्वेस्ट यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र और ऑनलाइन प्रोत्साहन-लाभ प्रबंधन प्रणाली (ओआईएमएस) जैसी डिजिटल सुविधाओं ने निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और राज्य में कारोबार करने के लिए अनुकूल माहौल बना है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि सुचारू नीति क्रियान्वयन, व्यापार में सुगमता तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सतत विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से राज्य के सभी क्षेत्रों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह तथा नागरिकों के जीवन में सुधार के लिए दीर्घकालिक मूल्य एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

- 08 वर्षों में राज्य को लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन किया गया है। इसके माध्यम से 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है तथा लाखों अन्य लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।
- फरवरी 2024 में GBC@4 के माध्यम से 10.11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन प्रारंभ।
- रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप 33 क्षेत्रीय नीतियां लागू, सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत

भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल्स में से एक 'निवेश मित्र' का क्रियान्वयन। उद्यमियों को 43 विभागों की 487 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

- उद्यमियों से लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों के 97 प्रतिशत से अधिक के निपटान दर के साथ, 'निवेश मित्र' देश में वर्तमान में संचालित सबसे कुशल सिंगल विंडो पोर्टल्स में से एक है। अब तक, 12.5 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की जा चुकी हैं। उद्योगों की सुविधा के लिए 4674 विनियामक अनुपालन बोझ कम किए गए।
- प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत,

उत्तर प्रदेश का निर्यात

2018-2019 – 16.3 बिलियन

2019-2020 – 17 बिलियन

2020-2021 – 16.4 बिलियन

2021- (कोविड-19)

2022 – 20.9 बिलियन

2022-2023 – 21.7 बिलियन

2023-2024 – 20.6 बिलियन

2024-2025 – 22 बिलियन

लखनऊ हरदोई में एक मेगा एकीकृत कपड़ा और परिधान पार्क, हरदोई और कानपुर में एक मेगा लीड क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क और गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर और हापुड़ में रासायनिक और फार्मा पार्क जैसे क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है। निवेश प्रोत्साहन और निवेशक सुविधा राज्य ने एक समर्पित, सशक्त निवेश प्रोत्साहन एजेंसी, इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की है, जो क्षेत्रीय फोकस के साथ-साथ वैश्विक पहुंच के साथ पूर्ण-सेवा निवेशक सुविधा, हैंडहोल्डिंग और विवाद समाधान प्रदान करती है। एजेंसी के पारदर्शी, सक्रिय और

निवेशक-अनुकूल कामकाज के कारण उत्तर प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। एजेंसी व्यापार के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के निर्माण और पुनर्गठन में भी सहायक भूमिका निभाती है।

- निवेश यूपी पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि समझौता ज्ञापनों के निष्पादन, निवेश अनुमोदन और परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और राज्य के आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप काम को गति दी जा सके।
- राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए वर्ष 2020 से ही समय-सीमा निर्धारित की है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और निवेशकों को उचित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य की निवेश प्रोत्साहन संस्था इन्वेस्ट यूपी द्वारा एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल निवेश सारथी विकसित किया गया है। यह पोर्टल निवेशकों को उनकी शंकाओं और शिकायतों के समाधान, निवेश आशय पंजीकरण, परियोजना सुविधा और निगरानी के लिए एक एकीकृत समाधान प्रदान करता है।

नीति आधारित शासन

उत्तर प्रदेश में नीति आधारित शासन पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण, रक्षा और एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, कपड़ा, एमएसएमई आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 35 से अधिक क्षेत्र-विशिष्ट और लक्षित नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों में पूंजी अनुदान, 100% एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क छूट, बिजली शुल्क छूट, साथ ही बड़ी परियोजनाओं और प्रमुख निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन उपाय शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों को दर्शाते हैं।

इन नीतियों में पूंजी अनुदान, 100 प्रतिशत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क में छूट, बिजली दरों में छूट के साथ-साथ बड़ी परियोजनाओं और प्रमुख निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन उपाय शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों को दर्शाते हैं। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में फॉर्च्यून 500 कंपनियों द्वारा समर्पित एफडीआई और निवेश नीति लागू की है।

वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख नई नीतियों की घोषणा की। इनमें सेमीकंडक्टर नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, बायो-प्लास्टिक नीति, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति, एयरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति और प्रतिस्पर्धी वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शामिल हैं। ये नीतियां राज्य को आर्थिक दृष्टि से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सेमीकंडक्टर नीति-2024 का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति के अंतर्गत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है तथा अनुकूल नीतिगत ढांचा विकसित किया जा रहा है, ताकि राज्य को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 का मुख्य उद्देश्य राज्य में कार्बन एमिशन तथा भारत के जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। यह नीति राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन एवं अमोनिया के उत्पादन, बाजार विकास, मांग एकत्रीकरण तथा अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए निवेश को प्रोत्साहित करती है।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 का उद्देश्य अग्रणी शिक्षण संस्थानों को आकर्षित करना, शैक्षिक गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना है। यह नीति घरेलू एवं विदेशी संस्थानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचे के विस्तार को सुनिश्चित करती है, ताकि राज्य के युवाओं को सशक्त बनाया जा सके तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

एक अभिनव पहल के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने बायो-प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 लागू की है, जिसका उद्देश्य बायो-डिग्रेडेबल एवं कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश ऐसी नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नीति बायो-प्लास्टिक बनाने वाली इकाइयों को आकर्षक सब्सिडी प्रदान करती है और उन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

नीति-2024 को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो निवेशकों को 30% अग्रिम भूमि सब्सिडी और 100% स्टांप शुल्क छूट प्रदान करता है।

यह पहल उत्तर प्रदेश को भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिससे रोजगार बढ़ने, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार और आर्थिक विकास में तेजी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 का उद्देश्य राज्य को एक प्रमुख एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के अनुरूप स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। यह नवाचार और वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में स्टार्टअप और एमएसएमई का समर्थन करने पर केंद्रित है। नीति में एआई और सॉफ्टवेयर विकास केंद्र सहित अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है।

यह पहल न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक नेता के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थापना करके आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देती है। हाल ही में, राज्य सरकार ने एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक क्षमताओं को आकर्षित करने और बनाने के लिए वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए एक हब बनाना है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की भूमिका को सुदृढ़ किया गया, जिससे 2030 तक 25 लाख से अधिक नौकरियां होंगी।

कुछ और नीतियां:

श्रम-केंद्रित क्षेत्र की नीतिः इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों को बनाना है, खासकर उन क्षेत्रों में जो वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रसद और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसी श्रम-केंद्रित हैं। नीति में महिलाओं और युवाओं के लिए श्रमिकों में अपनी भागीदारी का विस्तार करने के लिए विशेष प्रावधान हैं।

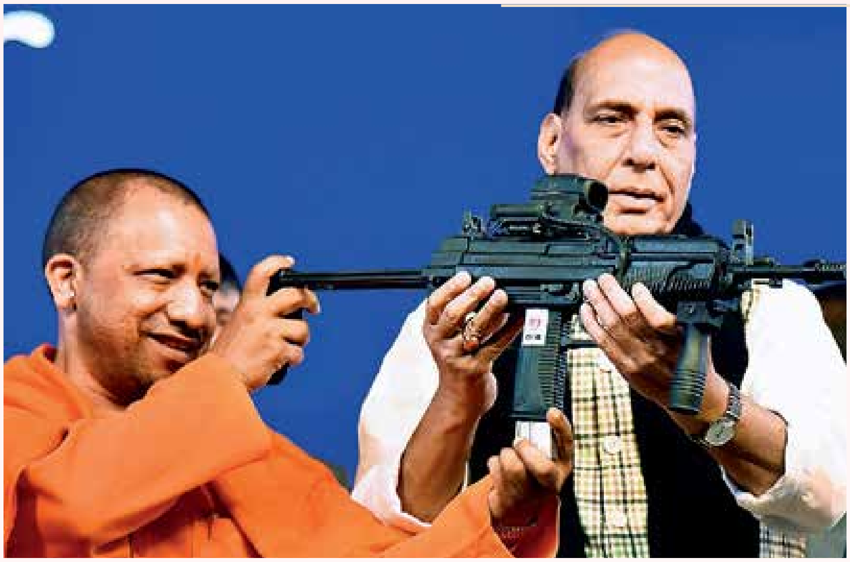

जूते, चमड़े और गैर-चमड़े के क्षेत्र से जुड़ी विकास नीति -2025

इस नीति को राज्य के समृद्ध चमड़े के उद्योग में निर्यात वृद्धि और रोजगार उत्पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ तैयार किया गया है। यह नीति निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और राज्य में रोजगार के अवसरों को सृजित करने में अहम भूमिका निभाएगी।

सुविधाओं वाला यूपी

- उत्तर प्रदेश हरित औद्योगिक केंद्रों के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर
- उत्तर प्रदेश को $ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बदलने के लक्ष्य के साथ योगी सरकार सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दे रही है। इस दृष्टि के अनुरूप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने सौर ऊर्जा के साथ औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली देने के लिए एक प्रमुख पहल शुरू की है।
- औद्योगिक बुनियादी ढांचे को हरियाली और आत्मनिर्भर बनाने के अपने मिशन के हिस्से के रूप में, यूपीसीडा ने सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए 13 नई साइटों की पहचान की है। यह पहल राज्य की सौर ऊर्जा नीति -2022 के साथ संरेखित करती है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा लागत को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, और कार्बन उत्सर्जन काटना है।
- पहचाने गए स्थानों में सुरजपुर साइट -5, ईपीआईपी (गौतम बुद्ध नगर), टीडीएस सिटी (गाजियाबाद), सेज (मोरादाबाद), बागपत, आगरा, मथुरा, झांसी, प्रयागराज और शाहजहांपुर जैसे सामरिक औद्योगिक केंद्र शामिल हैं जो सौर-सक्षम क्षेत्र बनने के लिए तैयार हैं।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को न केवल उत्पादन में नेतृत्व करना चाहिए बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल भी होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, यूपीसीडा ने "सौर औद्योगिक क्षेत्र" की अवधारणा को अपनाया है। कानपुर में यूपीसीडा मुख्यालय में 82.98 लाख रुपये की लागत से 150 किलोवाट सौर संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जो वित्तीय व्यवहार्यता और पारिस्थितिकीय जिम्मेदारी का एक उदाहरण स्थापित करते हैं।
- पावरिंग इंडस्ट्रीज से परे, यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्रों की सौंदर्य और कार्यात्मक गुणवत्ता को भी बढ़ा रहा है। अपनी "सौर पथ" पहल के तहत, रात में अच्छी तरह से प्रकाशित मार्गों को सुनिश्चित करने के लिए ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण नियंत्रण की सहायता के लिए ग्रीन बेल्ट विकसित किए जा रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र को अधिक दृष्टि से आकर्षक और निवेश के अनुकूल बनाते हैं।

एक जनपद एक उत्पाद लोकल से ग्लोबल तक

ओडीओपी

ओडीओपी का विचार सरकार की रणनीति से बिल्कुल मेल खाता है, जो बेहतर नीतियों के साथ कार्य करने में विश्वास रखती है। किसी विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देने के विचार ने एक विशिष्ट क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है।

यूपी का ओडीओपी विचार सरकार की उस नीति के बिल्कुल अनुकूल है जो केवल मास्टरस्ट्रोक में विश्वास करती है। किसी विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देने के बहुत ही सरल विचार ने एक क्षेत्र के पूरे भाग्य को बदल दिया। पिछले कुछ वर्षों में, इस नीति का एमएसएमई क्षेत्र पर कई गुना प्रभाव पड़ा है, इसने शिल्प और कौशल को संरक्षित और विकसित करने में भी कामयाबी हासिल की है जो अन्यथा खो गए होते। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य था और अब यह कलात्मक अखंडता को जीवित रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल ने राज्य के 75 जिलों में से प्रत्येक के अनूठे स्थानीय शिल्प, उद्योग और उत्पादों को बढ़ावा दिया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित कर रही है, रोजगार पैदा कर रही है, साथ ही निर्यात को बढ़ावा दे रही है और राज्य के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने की दृष्टि रखती है।

ओडीओपी योजना में प्रत्येक जिले से एक अद्वितीय उत्पाद की पहचान और चयन करना शामिल है, जो हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह चयन जिले के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व पर आधारित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि चुने गए उत्पाद में विकास, नवाचार और बाजार विस्तार की क्षमता है।

ओडीओपी योजना ने निर्यात को लगभग दोगुना कर दिया है। एक विश्लेषण से पता चलता है कि कई कारक इसमें भूमिका निभा रहे हैं जिसमें बेहतर उत्पाद गुणवत्ता, बेहतर विपणन रणनीति और नए बाजारों तक पहुंच शामिल है। कई उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग, वैश्विक मंच पर उनकी विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता की रक्षा करना भी ओडीओपी के माध्यम से संभव हुआ।

ओडीओपी पहल में शामिल कारीगरों और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के

लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किए हैं। ये केंद्र प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी सहायता जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और वैश्विक बाजारों में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है।

उत्तर प्रदेश में ओडीओपी प्रभावशाली रणनीति

- **सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी):** लगभग 10 ओडीओपी सीएफसी बनाए गए हैं और 18 और निर्माणाधीन हैं। ये केंद्र उत्पादन से लेकर पैकेजिंग और विपणन तक आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं, और कारीगरों को सभी पहलुओं में सहायता करते हैं।
- **प्रशिक्षण और टूलकिट वितरण:** लगभग 83,473 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया है और 80,872 को आधुनिक टूलकिट प्रदान किए गए हैं। यह पहल विभिन्न ओडीक्यूपी क्षेत्रों में कौशल विकास और गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण रही है।
- **वित्तीय सहायता:** लगभग 22,838 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया है, जो पहल के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करता है और ओडीओपी उद्यमों के विकास और स्थिरता को सुविधाजनक बनाता है।
- **जीआई टैग:** 32 ओडीओपी उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करना और 20 और उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन करना

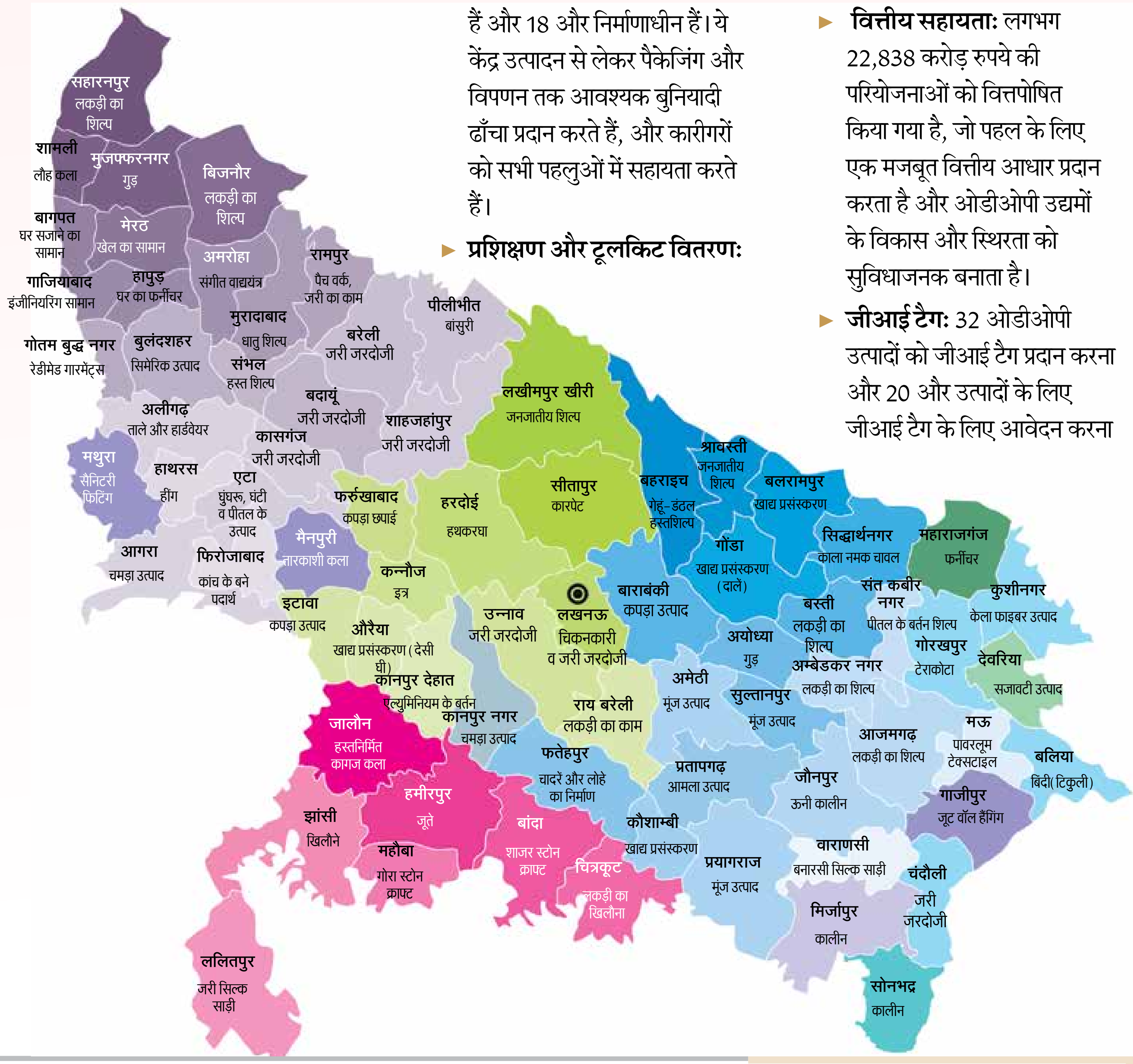

इन उत्पादों की ब्रांडिंग और वैश्विक मान्यता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- **प्रचार संबंधी गतिविधियां:** 9 ओडीओपी शिखर सम्मेलनों और विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों सहित 100 से अधिक प्रचार कार्यक्रमों ने ओडीओपी उत्पादों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार करते हुए विपणन और आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **ODOPmart.com:** odopmart.com का शुभारंभ और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 20,000 से अधिक उत्पादों की सफल बिक्री डिजिटल मार्केटिंग और बिक्री में महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही है।
- **ओडीओपी यूनिटी मॉल:** आगरा, वाराणसी और लखनऊ में 3 ओडीओपी यूनिटी मॉल विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ओडीओपी उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए समर्पित स्थान प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय मान्यता:** उत्तर प्रदेश राज्य को इस पहल की सफलता और प्रभाव को मान्यता देते हुए भारत सरकार द्वारा ओडीओपी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

- **नीतिगत अवरोधों को दूर करना:** स्थानीय जरूरतों के अनुरूप वैश्विक

बेंचमार्क वाली नीतियां और योजनाएं विकसित करना।

- **ओडीओपी योजनाएं:** मार्जिन मनी, कौशल विकास, टूलकिट वितरण, बाजार विकास सहायता और ब्रांडिंग के लिए योजनाओं की शुरुआत।
- **वित्त तक पहुंच में सुधार:** प्रौद्योगिकी और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से वित्त तक पहुंच को आसान बनाना।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** डिजाइन लैब, परीक्षण प्रयोगशालाओं, कच्चे माल के बैंकों आदि को संबोधित करते हुए सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रमुख जिले और उत्पाद:

- **आगरा:** चमड़ा उत्पाद, पत्थर/संगमरमर उत्कीर्णन हस्तशिल्प।
- **अलीगढ़:** धातु हस्तशिल्प, ताले और हार्डवेयर।
- **कानपुर नगर:** चमड़ा उत्पाद, होजरी और कपड़ा उत्पाद।
- **वाराणसी:** रेशम उत्पाद, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के बर्तन और खिलौने।
- **मुरादाबाद:** धातु शिल्प।
- **लखनऊ:** चिकनकारी और जरी-जरदोजी।
- **मेरठ:** खेल के सामान।
- **फिरोजाबाद:** कांच के बने पदार्थ।

ये जिले उत्तर प्रदेश की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हस्तशिल्प से लेकर खेल के सामान तक की विविधता प्रदर्शित करते हैं। नीति निर्माण से लेकर कौशल विकास और विपणन सहायता तक ओडीओपी पहल का व्यापक दृष्टिकोण इन स्थानीय उद्योगों को ऊपर उठाने के लिए एक ठोस प्रयास को दर्शाता है। स्थानीय उद्योगों के बिना कोई भी राज्य लाभ नहीं उठा सकता है और सरकार इससे सफलतापूर्वक लाभ प्राप्त करने में सक्षम रही है।

ओडीओपी पहल के तहत योजनाएं

1. कौशल विकास और टूलकिट वितरण योजना

उद्देश्य: ओडीओपी कारीगरों/श्रमिकों

की क्षमता निर्माण।

सहायता: अकुशल कारीगरों को 200 रुपये प्रतिदिन के वजीफे के साथ 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना और संबंधित उन्नत टूलकिट का निःशुल्क वितरण के साथ-साथ पूर्व शिक्षण (आरपीएल) प्रमाणन की मान्यता प्रदान करना।

2. मार्केटिंग विकास सहायता (एमडीए) योजना

उद्देश्य: बेहतर पहुंच और विपणन संवर्धन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में ओडीओपी कारीगरों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

सहायता: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई-कॉमर्स पोर्टल पर स्टाल शुल्क, यात्रा और पंजीकरण की 75% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

3. सामान्य सुविधा केंद्र योजना

उद्देश्य: परीक्षण प्रयोगशालाओं, डिजाइन केंद्रों, कच्चे माल के बैंकों, सामान्य उत्पादन केंद्रों, पैकेजिंग, लेबलिंग और बारकोडिंग सुविधाओं और उत्पाद प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्रों सहित सामान्य सुविधा केंद्रों को विकसित करके ओडीओपी निर्माताओं की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करना।

सहायता: परियोजना लागत का 60 से 90% प्रदान करता है।

4. वित्तीय सहायता (मार्जिन मनी) योजना

उद्देश्य: ओडीओपी कारीगरों, श्रमिकों और उद्यमियों को अपने उद्योग स्थापित करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना।

सहायता: 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी लाभ परियोजना लागत का 25% (अधिकतम 6.25 लाख रुपये) से लेकर 1.5 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए 10% (अधिकतम 20 लाख रुपये) तक है। ये ऋण प्रदान करने के लिए सभी राष्ट्रीय, ग्रामीण और अनुसूचित बैंक शामिल हैं।

ओडीओपी के साथ संयुक्त कार्यक्रम:

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ओडीओपी कारीगरों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
- **भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य चमड़ा उद्योग का विकास और आधुनिकीकरण करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, नवाचार बढ़ाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक के ऋण सहित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है।
- **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY):** नियोक्ताओं

ओडीओपी में जोड़े गए 12 नए उत्पाद

बागपत
कृषि उपकरण और सहायक उपकरण

सहारनपुर
होजरी उत्पाद

फिरोजाबाद
खाद्य प्रसंस्करण

गाजियाबाद
धातु उत्पाद और कपड़ा/परिधान आइटम

अमरोहा
धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प

आगरा
पेठा उद्योग और सभी प्रकार के जूते

हमीरपुर
धातु उत्पाद

बरेली
लकड़ी के उत्पाद

एटा
तांबे की घंटियां व अन्य उत्पाद

प्रतापगढ़
खाद्य प्रसंस्करण

बिजनौर
रस और संबंधित उत्पाद

बलिया
सत्तू उत्पाद

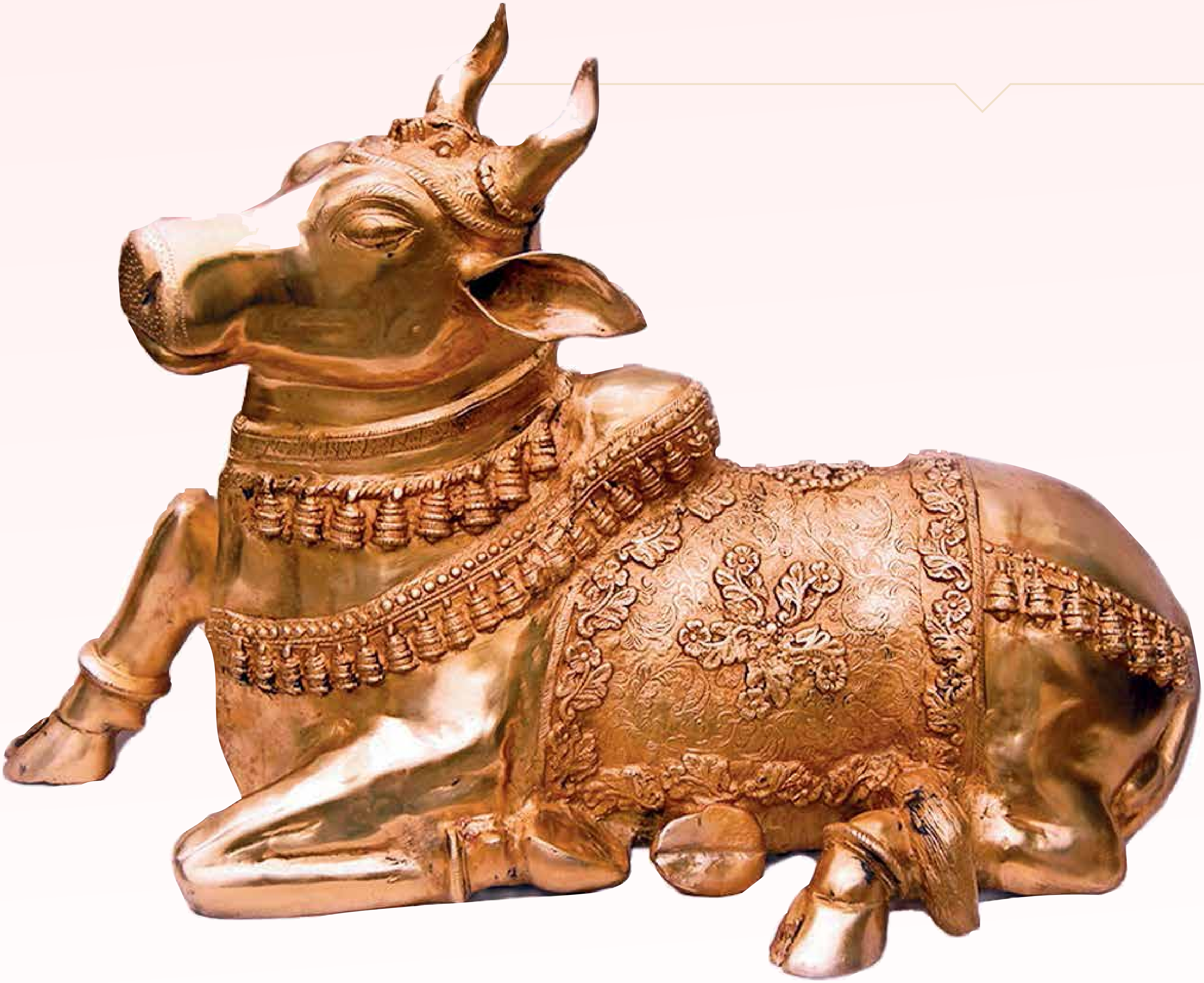

को नई नौकरियां सृजित करने और महामारी के दौरान खोई गई नौकरियों को फिर से बहाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, नए कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अंशदान के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।

- **टेक्सटाइल पार्क योजना (MoT): कपड़ा** उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करती है, कपड़ा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देती है।

ये योजनाएं और कार्यक्रम ओडीओपी पहल का अभिन्न अंग हैं, जो वित्तीय सहायता और कौशल विकास से लेकर विपणन और बुनियादी ढांचे के विकास तक व्यापक सहायता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाना, उत्पाद की गुणवत्ता और विपणन क्षमता को बढ़ाना और उत्तर प्रदेश के विशिष्ट उत्पाद क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्प कौशल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुई है, जिसमें 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का पुनरुद्धार हुआ है।

योगी आदित्यनाथ ने योजना की सफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा, “पहले, चीनी सामान हमारे बाजारों पर हावी थे। आज, लोग गर्व से ओडीओपी आइटम उपहार में देते हैं।”

नवाचार से प्रेरित नीतियां

नीतिगत सुधार

किसी भी राज्य का भविष्य उसकी नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नीतियों को ऐसा स्वरूप दिया गया है कि राज्य को भविष्य की परियोजनाओं के लिए अधिकतम निवेश मिल सके और साथ ही मौजूदा नीतियों को भी बढ़ावा मिले।

सरकार के 360 डिग्री विजन ने 'डबल इंजन' प्रगति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इतने विशाल आकार और जनसंख्या वाले राज्य को ऐसी नीतिगत योजना की आवश्यकता है, जो विकास का 'ट्रिकल डाउन' प्रभाव सुनिश्चित करे। पहले यह माना गया था कि यदि नीतियां व्यवसायों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करती हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों से निवेश आकर्षित होगा जिसे आगे सभी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। इसलिए, राज्य उन बड़े कॉर्पोरेट समूहों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है जो उत्तर प्रदेश के उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं। यह एमएसएमई की क्रांतिकारी प्रगति के साथ-साथ हो रहा है।

सशक्त नीतियां

डिजिटल निवेशक रिलेशनशिप पोर्टल 'निवेश सारथी' के पूरक के रूप में कार्य कर रहे मुख्यमंत्री 'उद्यमी मित्र', पोर्टल के तहत 118 उद्यमी मित्रों का चयन किया गया है, जो योग्य विशेषज्ञ हैं और निवेशकों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने और बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। प्रत्येक निवेशक को एक मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो निवेशक को व्यक्तिगत मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करता है, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करता है और उन्हें नीतियों और सेवाओं पर सलाह देता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न नीतियों के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक केंद्रीकृत 'ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली' विकसित की गई है, जिसका संचालन हमारी ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली निवेश मित्र के अंतर्गत किया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से, संबंधित विभागों द्वारा प्रोत्साहनों के लिए आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है और प्रत्येक चरण पर आवेदन की स्थिति को अपडेट किया जाता है, ताकि आवेदक अपने प्रोत्साहन आवेदन की

स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकें।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत तीन देशों को ध्यान में रखते हुए डेस्क स्थापित किए गए हैं। इनमें अमेरिका प्लस डेस्क (अमेरिका और कनाडा), यूरोप प्लस डेस्क (यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड) और जापान प्लस डेस्क (जापान और दक्षिण कोरिया) शामिल हैं। इन डेस्कों के माध्यम से, वैश्विक निवेशकों के साथ बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करके उत्तर प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में स्थापित किया जा रहा है।

ट्रिलियन डॉलर के विज़न को साकार करना

- अगले 2-3 वर्षों में यूपी 1,50,000 एकड़ से अधिक का औद्योगिक भूमि बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित राज्य विकास प्राधिकरणों में भूखंडों का अधिग्रहण करेगा। राज्य के पास पहले से ही लगभग 54,000 एकड़ का भूमि बैंक है।
- सरकार चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 25) के अंत तक कुल भूमि बैंक को 82,000 एकड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जून तक लगभग 21,751 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
- इस परियोजना में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण और सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे।
- विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित 42,000 से अधिक उद्योगों में से एक तिहाई नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा में स्थित हैं।
- पिछले वर्ष मुख्यमंत्री को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 60,000 से 80,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक सुधारों, डिजिटल पहलों और निवेशक-अनुकूल नीतियों के माध्यम से व्यवसायों और निवेश को सुगम बनाने में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। उत्तर प्रदेश को 2022 में व्यापार सुगमता में 'शीर्ष उपलब्धि' और 2022, 2023 और 2024 में लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में 'उपलब्धि' के रूप में मान्यता दी गई है।

इसके अलावा, राज्य को 2021 के सुशासन सूचकांक में प्रथम और निर्यात तैयारी सूचकांक में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे यह भारत में सबसे सुरक्षित और निवेशक-अनुकूल स्थलों में से एक के रूप में स्थापित हुआ है।

उत्तर प्रदेश का समर्पित ऑनलाइन पोर्टल 'निवेश मित्र' सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम 43 विभागों की सेवाओं को एकीकृत करता है, जो अनुमोदन, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए 520 से अधिक सेवाएँ प्रदान करता है। यह आवेदन जमा करने और ट्रैकिंग की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे देरी और प्रशासनिक परेशानियाँ कम होती हैं। पिछले वर्ष, चिकित्सा प्रतिष्ठान, कृषि, बागवानी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, फिल्म एवं मनोरंजन, उत्पाद शुल्क, फार्मास्यूटिकल्स, भूविज्ञान एवं खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनुमोदन सेवाओं को भी निवेश मित्र पोर्टल सेवाओं में शामिल किया गया है। उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत 97 प्रतिशत से अधिक लाइसेंसिंग आवेदनों के निपटारे के साथ, निवेश मित्र पोर्टल अब देश के सबसे कुशल "सिंगल विंडो " पोर्टलों में से एक बन गया है।

'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए, निवेश मित्र पोर्टल में व्यापक प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य एक पारदर्शी, कुशल और प्रभावी ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली स्थापित करना है। सभी प्रकार के लाइसेंस के लिए आवेदन अब अनिवार्य रूप से केवल निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं; आवेदनों को भौतिक या विभागीय रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। अब तक, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 18 लाख से अधिक अनुमोदन डिजिटल रूप से जारी किए जा चुके हैं।

देश में एमएसएमई का केंद्र है उत्तर प्रदेश

- 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है।
- एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एमएसएमई नीति-2022 प्रख्यापित।

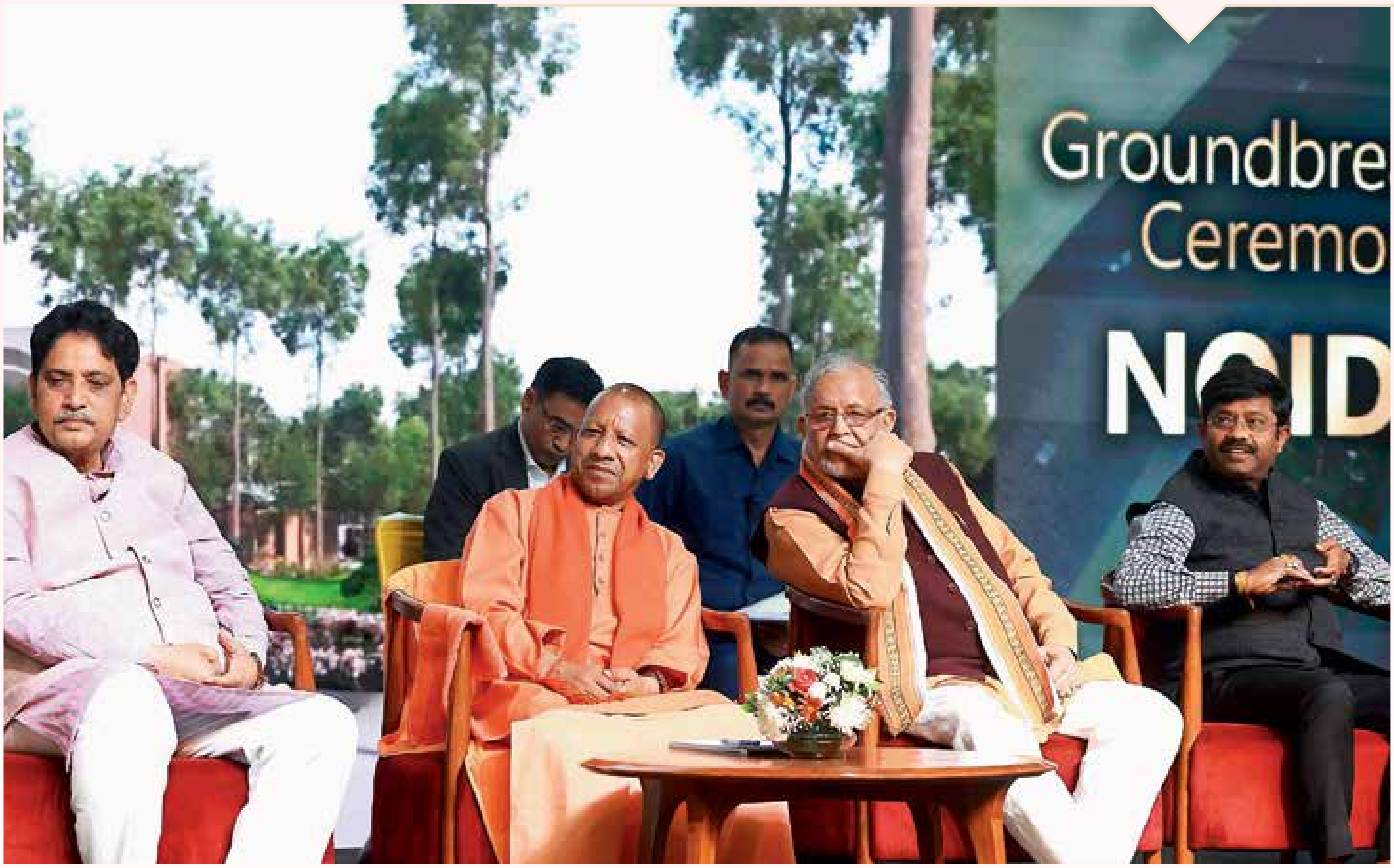

- प्रदेश में 11 प्ले पार्कों (उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड़, संभल, झांसी एवं मथुरा) को स्वीकृति।
- 10 जिलों में संत कबीर के नाम पर टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना, 02 जिलों में संत रविदास के नाम पर लेदर पार्क बनाने की तैयारी।
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमी की मृत्यु या विकलांगता पर 05 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान।
- प्रदेश में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया जा रहा है, वर्ष 2024 में देश-विदेश के 500 से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया, जिसमें 2,200 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्राप्त हुए।
- राज्य में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन नीति-2023 की घोषणा की गई।
- अप्रैल 2000 से जून 2017 तक राज्य को 3303 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। जबकि अप्रैल 2017 से सितंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश को 14008 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ।
- राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात नीति 2020-25 प्रख्यापित। प्रत्येक जिले में निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन।
- एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम (ओडीओपी) के शुभारंभ के बाद से, राज्य का निर्यात 88,967 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया। इस योजना के तहत, प्रति वर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है।

ग्रामीण एवं कृषि

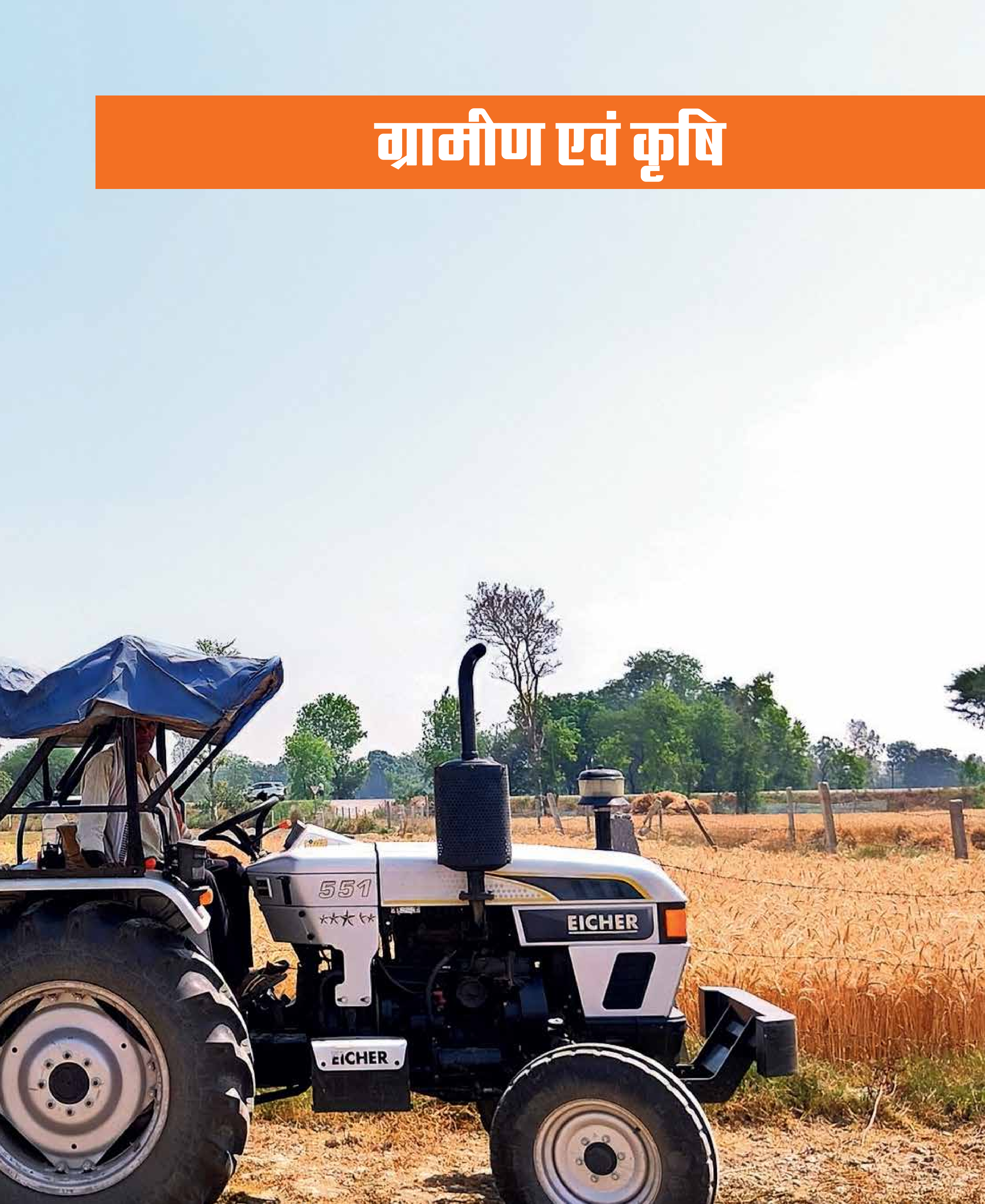

जमीनी स्तर पर क्रांति

ग्रामीण विकास

कोई भी देश तभी आगे बढ़ने की सोच सकता है, जब गांवों में बदलाव आए। आधुनिक युग में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इनके आत्मनिर्भर होने से कृषि और अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

विकास एक सीढ़ी की तरह है। पहले पायदान से शुरुआत होती है और लगातार प्रयासों के साथ शिखर तक पहुंचा जाता है। शासन के संदर्भ में विकास की श्रृंखला को कामकाज के मूल स्तर से ही शुरू करना चाहिए। कोई भी देश तभी आगे बढ़ने की सोच सकता है, जब गांवों में बदलाव आए। आधुनिक युग में, गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। गाँवों के आत्मनिर्भर होने से कृषि और अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

पिछले आठ वर्षों में, उत्तर प्रदेश 56.50 लाख से अधिक परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लगभग 36.15 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि 35.77 लाख घर पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 2.57 लाख घरों को मंजूरी मिलने और

नई एफपीओ नीति- 2020

यूपी कैबिनेट की नई एफपीओ नीति–2020, केंद्र सरकार के 2023–24 तक देश में 10,000 सक्षम इकाइयां बनाने के फैसले को रफ्तार दे रही है। राज्य में वर्तमान में 3175 एफपीओ हैं जिनमें लगभग 2.15 लाख किसान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 1,000 एफपीओ स्थापित करना है। हर ब्लॉक में एक एफपीओ होगा, जिसमें 300 से 500 किसान शामिल होंगे। राज्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ भी समन्वय करेगा ताकि एफपीओ को बैंकों से कार्यशील पूंजी के रूप में ऋण हासिल करने में मदद मिल सके या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोर, ब्रैंडिंग और पैकेजिंग इकाइयों, गोदामों आदि की स्थापना की जा सके। हर एफपीओ अधिकतम 2 करोड़ रुपये के ऋण के हकदार होंगे। एफपीओ प्रसंस्करण, ब्रैंडिंग और मार्केटिंग की अपनी आवश्यकता के अनुसार चिह्नित उत्पाद के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकते हैं। विशेष रूप से, 'एक जनपद, एक उत्पाद' नीति को इस पहल से ताकत मिलेगी।

2.53 लाख घरों के पूरा होने के बाद आवास की स्थिति में दस गुना सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रत्येक लाभार्थी, जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं थी, को अनिवार्य रूप से आवास का पट्टा प्रदान किया है।

इस विजन को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार ने 100 विकास खंडों को आकांक्षात्मक विकास खंडों के रूप में चुना है। विकास लाभार्थियों की सतत निगरानी हेतु मुख्यमंत्री फेलो की तैनाती भी की जा रही है। मातृभूमि योजना गाँव के विकास में आम लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित है।

राज्य सरकार की एक और उपलब्धि कीर्तिमान स्थापित करना रही है। कई नीतियों और पहलों ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसी क्रम में, सरोवर निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

अच्छे बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। राज्य के 165 विकास खंड मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ने के लिए 1385 किलोमीटर लंबाई के 149 कार्य पूरे हो चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही लगभग 40 हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा और लगभग 16 हजार किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण किया जाएगा। एकल-उपयोग अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करके लगभग 100 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 वर्षों में राज्य की कायापलट कर दी है और गांवों की प्रगति अभूतपूर्व है। राज्य में 33,157 से अधिक ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाएं बनाई गई हैं और सौर ऊर्जा पर 900 मेगावाट के सौर पैनल लगाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत, गरीब परिवारों की 95 लाख से अधिक महिलाओं को 8 लाख 55 हज़ार 479 स्वयं सहायता समूहों, 685 ग्राम संगठनों और 2 हज़ार 945 संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से, 779 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर

और 25,916 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया।

पहली बार, G-em पोर्टल को भारत सरकार के सॉफ्टवेयर ई-ग्राम स्वराज्य के साथ एकीकृत किया गया और ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन क्रय प्रणाली से जोड़ा गया।

ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिवारों की सहायता हेतु पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से अब तक कुल 2022 आश्रित परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

32,074 किमी (अप्रैल, 2017 से अब तक 25,000 किमी) लंबाई में ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया है, साथ ही 10,000 किमी लंबाई में सड़कों का

चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य भी किया गया है। प्रतिवर्ष औसतन 4076 किमी सड़कों का नव निर्माण तथा 3184 किमी सड़कों का चौड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण किया गया है। प्रतिदिन औसतन 9 किमी सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा प्रतिदिन औसतन 11 किमी सड़कों का नव निर्माण किया जा रहा है।

कुल 46 नए राष्ट्रीय राजमार्ग (लंबाई 4115 किमी) चयनित किए गए हैं। 70 नए राज्य राजमार्ग (लंबाई 5604 किमी) और 57 नए प्रमुख जिला मार्ग (लंबाई 2831 किमी) घोषित किए गए हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सचिवालय के दैनिक संचालन और सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायत सहायक लेखाकार एंट्री ऑपरेटर की नीति स्थापित की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 83,066 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का रखरखाव एवं मरम्मत, 24,580 आंगनवाड़ी भवनों का सुदृढ़ीकरण, 79,718 शौचालयों का नवीनीकरण कार्य किया गया है।

10,500 विद्युत कर्मियों द्वारा 1120 करोड़ रुपये के बिजली बिल संग्रहण

का कार्य किया गया, जिससे स्वयं सहायता समूहों (विद्युत सब्सिडी) की महिलाओं को 14.60 करोड़ रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ। राज्य में स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा 2510 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस का लक्ष्य प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार 2024 तक पाइप पेयजल योजना के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाने में सफल रही है। भूजल प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से अटल भूजल योजना के अंतर्गत 550 ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा योजना विकसित की गई है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत करोड़ों घरों को नल का पानी वितरित किया जा चुका है।

पूरी तरह ODF+ : स्वच्छ और सशक्त उत्तर प्रदेश

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 100% खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया।
- 95,767 गांवों ने ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
- पिछले 9 महीनों में, 80,000 से अधिक गांवों ने खुले में शौच से मुक्त का दर्जा प्राप्त किया है
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, पहले चरण में 2.68 करोड़ इज्जत घर/व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। यह देश में सबसे अधिक शौचालय निर्माण वाला पहला राज्य है।
- ग्रामीण क्षेत्रों की सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए, 1,100 प्रखंडों में सामुदायिक/सार्वजनिक/पिंक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

किसानों के लिए हर बूंद है कीमती

(सिंचाई सुधार: एक नई शुरुआत)

यह सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुए हैं। सिंचाई व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और एक समर्पित नीतिगत ढांचे के परिणामस्वरूप सिंचाई योजना में व्यापक बदलाव आया है।

एक अर्थव्यवस्था, जो तेजी से विकास करना चाहती है, वह हमेशा अपने मूलभूत तत्वों पर आधारित होती है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसान हितैषी योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने में सफल रही है। जहां, पहले किसानों को बुनियादी सिंचाई अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण खेत सूखे रहते थे। ऐसे में उनके नेतृत्व में पूर्ण सुधार और समर्पित नीति परिवर्तनकारी सिंचाई योजना तैयार की गई।

सिंचाई तक पहुंच बढ़ी है और दो करोड़ से अधिक किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले एक वर्ष में 394 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुईं, जिससे 64 लाख किसानों को लाभ हुआ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में 1,100 से अधिक सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से कई पूरी हो चुकी हैं। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को एक मॉडल कृषि राज्य के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुई हैं।

राज्य में कुल 976 नई बहाली सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई हैं। 48.32 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण हुआ है, जिससे 185.33 लाख किसानों को लाभ हुआ है। 6,600 सरकारी ट्यूबवेल्स का आधुनिकीकरण किया गया है और 3,376 नए सरकारी ट्यूबवेल्स का निर्माण किया गया है, साथ ही 1,750 सरकारी ट्यूबवेल्स का पुनर्निर्माण किया गया है।

सरकार 3 लाख 49 हजार 666 किलोमीटर नहरों की गाद सफाई कर रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत,

14,822.64 करोड़ रुपये की 67 सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कुल 39 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 12 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 11 परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 11,36,917 उथले बोरिंग ट्यूबवेल्स, 11,003 गहरे बोरिंग और 29,054 मध्यम बोरिंग का काम पूरा किया गया है। मध्य गंगा नहर परियोजना चरण-2, कन्हार सिंचाई परियोजना और महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के पूरा होने पर 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण होगा, जिससे 6.77 लाख किसानों को लाभ होगा।

विभाग ने अटल भूजल योजना के तहत भूजल प्रबंधन के लिए 26 विकास खंडों की पहचान की है। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के संकल्प से 14 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक हर साल निरंतर ट्रीजिंग कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ट्रीजिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों में बाढ़ सुरक्षा के सफल परिणामों का प्रभाव अध्ययन किया गया। सरकार सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाने के लिए और अधिक संसाधन तैनात करने की योजना बना रही है। सरकार की कल्याणकारी सोच ने नीचे से ऊपर तक दृष्टिकोण को सार्थक बनाया है। कृषि के बुनियादी स्तर पर विकास हो रहा है और इसके परिणाम ऊपरी स्तरों तक गूंज रहे हैं।

उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां 76% कृषि भूमि पर खेती होती है और 86% कुल भूमि सिंचित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, तीन प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं—सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना और बांणसागर परियोजना—पूरी हुईं और लोगों को समर्पित की गईं।

मध्य गंगा नगर परियोजना के चरण 2, कन्हार सिंचाई परियोजना और महाराजगंज में रोहिन नदी पर एक नए बैराज का काम चल रहा है।

नई पहलों से 5 लाख हेक्टेयर और सिंचाई क्षमता जुड़ेगी, जिससे 7 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।

आगामी केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के पूरा होने पर, झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर में 2.51 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी और 21 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा।

यूपी में पशु कल्याण क्रांति

पशुधन

नए उत्तर प्रदेश में हर जीवन का अपना महत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पशुपालन और डेयरी विकास उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ है, क्योंकि यह आजीविका, पोषण सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का एक जरिया है।

2017 से मुख्यमंत्री के गौ संरक्षण प्रयासों ने राज्य को एक नया जीवन दिया है, जहां 7,717 गौशालाओं में 16,09,557 निराश्रित गायों को रखा गया है। यह आंकड़ा गायों के प्रति राज्य की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सहयोग योजना के तहत 2,37,369 गायों को इच्छुक किसानों और पशुपालकों को सौंपा गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

गायों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कुल 14.50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया है। अभियान के तहत जिन गायों का टीकाकरण किया गया, उनमें से 1.92 करोड़ गायों को लम्पी स्किन रोग से बचाव के लिए टीका लगाया गया।

सरकार ने मुफ्त पशु चिकित्सा सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1962 भी स्थापित किया है। यह पहल पशुपालकों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इससे उनके पशुओं की सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार कहा है कि पशुपालन और डेयरी विकास उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो आजीविका, पोषण और सुरक्षा के साधन हैं।

जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई प्रोत्साहन आधारित योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और स्वदेशी गोवंश संवर्धन योजना जैसे कार्यक्रमों ने पशुपालकों को नई राह दिखाई है।

- मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गाय सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक इच्छुक किसान/पशुपालक परिवार को एक गाय और 1500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान।
- राज्य में पहली बार गायों के रखरखाव के लिए 50 रुपये प्रतिदिन की दर से

- डीबीटी के माध्यम से गौ आश्रय स्थलों को धनराशि हस्तांतरित की गई।
- निराश्रित गायों के संरक्षण के लिए 7713 गौ आश्रय स्थल स्थापित किए गए तथा 16,09,557 लाख गायों को संरक्षित किया गया।
- मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत 2,37,369 गायें इच्छुक किसान/पशुपालक परिवारों को सौंपी गईं।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है। साथ ही, डीबीटी के माध्यम से, प्रति गाय 50 रुपये प्रति दिन की दर से 1,500 रुपये की मासिक राशि गाय आश्रयों को चारे के लिए हस्तांतरित की जा रही है। इन योजनाओं से पशुपालक परिवारों की आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण स्वावलंबन को बढ़ावा मिला है।

राज्य को दूध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखने के लिए, 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये की लागत से नंद बाबा दूध मिशन शुरू किया गया। दुग्ध संघों को सुदृढ़ करने के लिए 220 समितियों का गठन एवं 450 समितियों का पुनर्गठन किया गया, जबकि 1,22,951 उपभोक्ताओं, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं पराग मित्रों को ई-कॉमर्स पोर्टल से जोड़ा गया।

अन्य कदम:

- बांदा जिले में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया डेयरी प्लांट, वाराणसी जिले में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का पाउडर प्लांट।
- मेरठ जिले में 04 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट पूर्ण होने की स्थिति में है।

मत्स्य पालन उन्नति

- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गोरखपुर, झांसी और चंदौली जिलों में नई मछली मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- यूएई के एक्वा ब्रिज ग्रुप से 4,000 करोड़ के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश अपने मत्स्य पालन क्षेत्र को बदलने के लिए तैयार है, जो भारत के जलीय कृषि उद्योग में सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक है।
- यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीआईडीए) के तहत उन्नाव जिले के सरैया गांव में प्रस्तावित यह परियोजना छह जिलों-सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, अयोध्या, बाराबंकी और रायबरेली तक विस्तारित होगी।

- उत्तर प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेयरी विकास एवं उत्पाद प्रोत्साहन नीति का प्रवर्तन।
- दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

अन्य पहलुओं में विकास

- कुक्कुट विकास नीति के तहत 60 हजार पक्षी क्षमता की 4 इकाइयां तथा 10 हजार पक्षी क्षमता की 375 इकाइयां क्रियाशील हैं।
- निषाद राज नाव अनुदान योजना के तहत नाव खरीदने के लिए अनुदान का प्रावधान।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना (पशुपालन घटक) के तहत मार्च 2024 तक 5 लाख 60 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित
- देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, 'लाल सिर वाला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र', गोरखपुर जिले के कैम्पियर रेंज में स्थापित किया गया है।

गन्ने की तरक्की का मीठा स्वाद

गन्ना क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार

प्रदेश सरकार गन्ना किसानों की समृद्धि के लिए किसान हितैषी योजनाएं चला रही है। बेहतर कीमत, समय पर भुगतान और आधुनिक तकनीक से आय बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे पहले कभी भी किसान अपनी उपज पर इतना संतुष्ट नहीं हुआ था। सबसे बढ़कर, वे योगी सरकार की उनके कल्याण के लिए की गई मंशा से खुश हैं। दरअसल, योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में उनकी जरूरतों को बेहतरीन तरीके से पूरा किया है।

जहां तक गन्ना किसानों की बात है, तो 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने से गन्ना किसानों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ।

इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 46.50 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों को अब तक आठ सालों में कुल 2,80,223 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह बड़ी रकम साल 1995 से 15 मार्च 2017 तक यानी आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य की कमान योगी के हाथों में आने से 22 साल पहले किए गए कुल भुगतान से 66,703 करोड़ रुपये ज्यादा है। योगी सरकार की किसान हितैषी सोच का अंदाजा यहां प्रस्तुत दस्तावेजी तथ्यों से भी लगाया जा सकता है:

- वर्ष 2016-17 में गन्ना रकबा 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 29.66 लाख हेक्टेयर हो गया, जिससे किसानों की आय में 370 रुपये प्रति क्विंटल की औसत दर से 43,364 रुपये

प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2016-17 से पहले जहां गन्ना उत्पादन 72 टन प्रति हेक्टेयर था, वह वर्ष 2024-25 में बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर हो गया है।
- वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं। वर्ष 2017 से पहले चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता जो 7.50 लाख टीसीडी थी, वह अब बढ़कर 8.36 लाख टीसीडी हो गई है।
- मार्च, 2017 से अब तक 03 नई चीनी मिलों की स्थापना, 06 चीनी मिलों का पुनः संचालन तथा 38 चीनी मिलों की क्षमता का विस्तार किया गया है, जिससे लगभग 1.25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

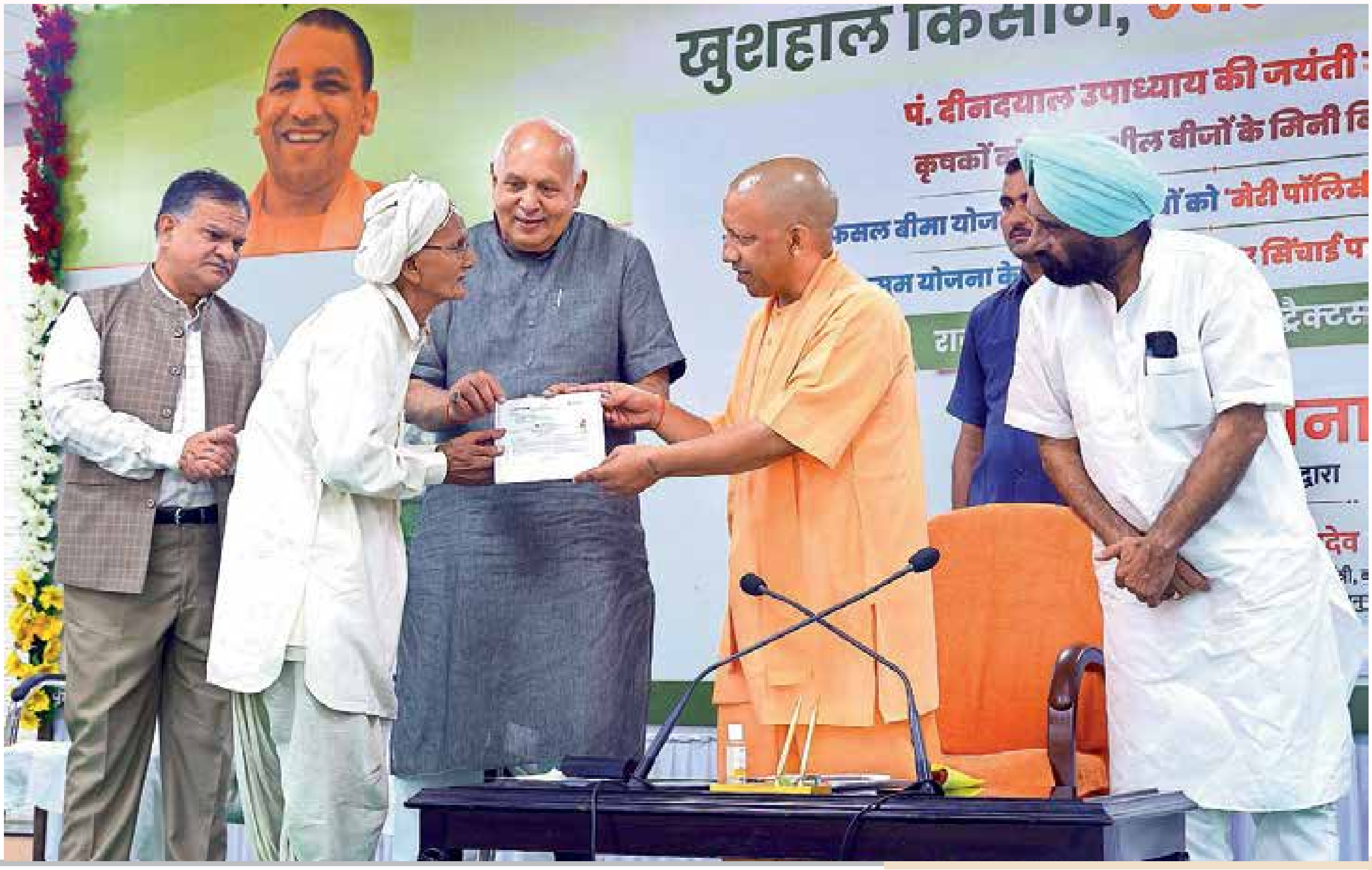

प्रगति के बीज बोना

कृषि सुधार

किसानों को कृषि और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उनकी आय बढ़ाने और उसे दोगुना करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में खेती सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नींव होगी।

समाज और सभ्यता का विकास किसानों के कंधों पर टिका हुआ है। आविष्कारों से पहले, समाज की नींव किसानों ने रखी थी, जिन्होंने खाद्यान्न उगाया था। कृषि अंततः अस्तित्व का सिद्धांत बन गई। आधुनिक अर्थव्यवस्था में, हर सरकार कृषि और इसके लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करती है।

उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में अपने सकारात्मक कृषि परिवर्तनों के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा की है। भूमि उत्पादकता बढ़ाने से लेकर खेती की जगह बढ़ाने और किसानों के लिए विभिन्न उपकरणों और संसाधनों तक, कृषि राज्य के ट्रिलियन-डॉलर विजन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रही है।

जब किसान बढ़ता है, तो राष्ट्र बढ़ता है। मुख्यमंत्री, शुरू से ही जानते थे कि किसानों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में 8.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 13.7 प्रतिशत हो गई है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के किसान को नया जीवन दिया है, जो कभी असंवेदनशील राजनेताओं के बहकावे में आ गया था। 9 जलवायु क्षेत्रों और 187.70 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के साथ, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां कुल उपलब्ध भूमि का 76 प्रतिशत कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है, 86 प्रतिशत से अधिक सिंचित भूमि का कवरेज है। वर्ष 2016-2017 में राज्य में केवल 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जबकि वर्ष 2023-24 में लगभग 669 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होने का अनुमान है। वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादकता लगभग 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष

कृषि और खाद्य विकास

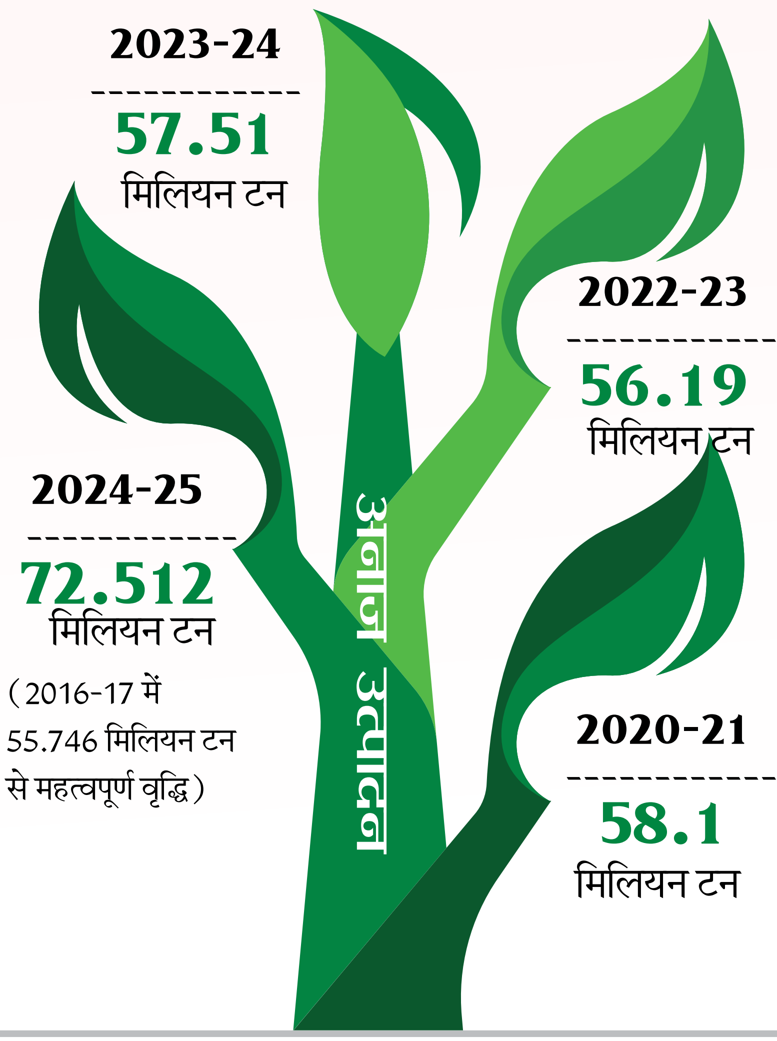

- कृषि क्षेत्र ने 13.5% की वृद्धि दर दर्ज की है और यह राज्य की जीडीपी में 28% का योगदान दे रहा है।
- सरकार के पहले कैबिनेट निर्णय के तहत 36,000 करोड़ रुपये के किसानों के कर्ज माफ किए गए, जिससे किसानों की आर्थिक परेशानी कम हुई।
- प्रधानमंत्री–कुसुम योजना के तहत 86,000 किसानों को सोलर पैनलों का लाभ मिला है, वहीं 14 लाख निजी नलकूपों को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
- राज्य के पास कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां देश की लगभग 10–11% उपजाऊ कृषि योग्य भूमि है।
- उत्तर प्रदेश में पिछले आठ वर्षों में ट्रैक्टर स्वामित्व में 62% की वृद्धि हुई है, जो कृषि प्रथाओं और ग्रामीण समृद्धि में बड़े बदलाव का प्रतीक है।
- मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के तहत मंडी परिषद ने 79,796 किसानों को 134.76 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

2023-24 में बढ़कर 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। उत्तर प्रदेश ने पहली बार 400 लाख टन फल और सब्जी का उत्पादन कर देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2016-17 में तिलहन की उत्पादकता मात्र 12.40 लाख मीट्रिक टन थी, जो 2023-24

में 128 प्रतिशत बढ़कर 28.31 लाख मीट्रिक टन हो गई है।

कृषि उद्योग में सुधार के प्रयास अकेले नहीं हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य संगठनों के सहयोग की आवश्यकता है जो इस प्रयास में सहयोग देने को तैयार हैं। व्यापार में आसानी और उज्ज्वल भविष्य के वादे के साथ, कई संगठन सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

इसी क्रम में, कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए विश्व बैंक के सहयोग से कृषि विकास और ग्रामीण उद्यमिता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (यूपी एग्रीस) शुरू किया गया। इसका सीधा लाभ पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 07 जिलों को मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सपने को साकार करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।

14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की गई। इससे 63 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 58.07 लाख किसानों को 47,555.09 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 76,189 से अधिक सौर पंप आवंटित किए गए हैं। यह सौर ऊर्जा को विकसित करने और आत्मनिर्भर

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- कौशाम्बी में 'फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र', चंदौली में 'सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र' स्थापित करने की कार्यवाही
- सहारनपुर में फलों एवं सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, लखनऊ में सजावटी पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण
- लखनऊ में एग्री मॉल की स्थापना प्रगति पर है
- आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना प्रगति पर है
- मंडल मुख्यालयों पर जैविक एवं प्राकृतिक उत्पादों के आउटलेट स्थापित
- सभी जिलों में मनरेगा के अंतर्गत 2-2 हाई-टेक नर्सरियाँ निर्माणाधीन
- हापुड़ और कुशीनगर में 2 'आलू के लिए उत्कृष्टता केंद्र' निर्माणाधीन
- कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा किसानों को प्रभावी परिणाम प्रदान करने के उद्देश्य से पाँच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं
- प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं।
- कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

बिजली उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के विजन को और आगे बढ़ाता है। वर्ष 2016-17 में तिलहन की उत्पादकता केवल 12.40 लाख मीट्रिक टन थी, जो 2023-24 में 128 प्रतिशत बढ़कर 28.31 लाख मीट्रिक टन हो गई है।

वितरण प्रणाली में सुधार के लिए भी कदम उठाए गए हैं, क्योंकि प्रगति केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। 27 नई मंडी स्थलों का आधुनिकीकरण, 185 हाट-पैठों का निर्माण। मंडियों में किसानों के लिए आगमन से पूर्व ई-पास। मंडी व्यापारियों के डिजिटल भुगतान की सुविधा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए जनवरी, 2025 तक प्रदेश की 125 मंडियों में लगभग 06 हजार 99 करोड़ रुपये का डिजिटल व्यापार। ई-मंडी योजना के तहत इस अवधि में 06 हजार 922 ई-लाइसेंस जारी किए गए हैं और ई-मंडियों में 04 करोड़ 18 लाख से अधिक ऑनलाइन पर्चियां जारी की गई हैं। डिजिटलीकरण की दिशा में प्रदेश का कदम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया है और किसान इसके लाभार्थी बनकर उभर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों/कमीशन एजेन्टों के

लिए संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से अब तक 48 हजार 210 कृषक लाभार्थियों को लगभग 98 करोड़ 50 लाख की अनुदान धनराशि वितरित की गयी है। 08 जनपदों में कृषकों की उपज का उचित मूल्य दिलाने की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए 49 करोड़ की लागत से लखनऊ में 08 नई मण्डी/उप मण्डी तथा किसान एग्रीमॉल का निर्माण कार्य पूर्णता की स्थिति में है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2024-25 में लगभग 66 लाख क्विंटल गुणवत्तायुक्त बीज वितरित किए गए। राज्य बीज निगम अपने स्वयं के आउटलेट, निजी डीलरों और विभागीय आउटलेट सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें अपग्रेड किया गया है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024-25 में किसानों को लगभग 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किए गए। लगभग 8 लाख 50 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। पहले राज्य में उर्वरक संकट की स्थिति थी, जिसमें सामग्री की कमी थी और अक्सर उत्पाद समय पर किसानों तक नहीं पहुंच पाते थे। इस संबंध में सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। पूरे राज्य में बुंदेलखंड के सभी क्षेत्रों में 23 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में गो-आधारित प्राकृतिक कृषि की जा रही है। प्रत्येक कृषि मंडी में माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्राम गृह की स्थापना की जाएगी। कैंटीन में रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अमरोहा, वाराणसी एवं सहजनवा में 88 ग्रामीण हाट बाजारों के साथ ही इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सच्चे डिजिटल युग की निशानी के रूप में किसानों के लाभ के लिए एन्ड्रॉयड मोबाइल ऐप यूपी मंडी भाव लांच किया गया है, जिसमें प्रतिदिन कृषि मंडियों के बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अन्तर्गत पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह की जयंती को 'किसान सम्मान दिवस' के रूप में मनाते हुए किसानों को ट्रैक्टर वितरित किये गये।

किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 से पूर्व यूपी डास्प में मात्र 01 योजना संचालित थी। वर्तमान में 05 नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2024-25 में किसान पंजीकरण करते हुए माह दिसम्बर 2024 तक कुल 60.48 लाख किसान कार्ड आई.डी. जारी किए जा चुके हैं। अब तक बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 1551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, जिससे 32.87 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को बचाकर करोड़ों की आबादी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बीज उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 60 हजार महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। लखनऊ में 251 करोड़ की लागत से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर बीज पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसी वर्ष मई माह में मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रयोगशालाओं, आई.सी.आर., कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार खेतों में जाकर सीधे किसानों से मिलकर कृषि चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा, "अभियान का मुख्य लक्ष्य शोध को 'प्रयोगशाला से जमीन तक' ले जाना है।

कृषि वैज्ञानिक न केवल प्रयोगशालाओं में शोध करेंगे, बल्कि खेतों का दौरा करेंगे और किसानों से बातचीत भी करेंगे। इससे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। शोध केंद्रों में किए जा रहे काम जमीन पर साफ दिखाई देने चाहिए।" कृषि किसी भी देश की रीढ़ होती है। अगर किसानों और उनकी उपज के लिए पर्याप्त काम किया जा रहा है, तभी हम भविष्य की ओर देख सकते हैं। सरकार का डबल इंजन कृषि से मिलने वाले समर्थन पर चलता है। अगर हमारे खेत हरे-भरे होंगे, तो हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा।

युवा और महिला

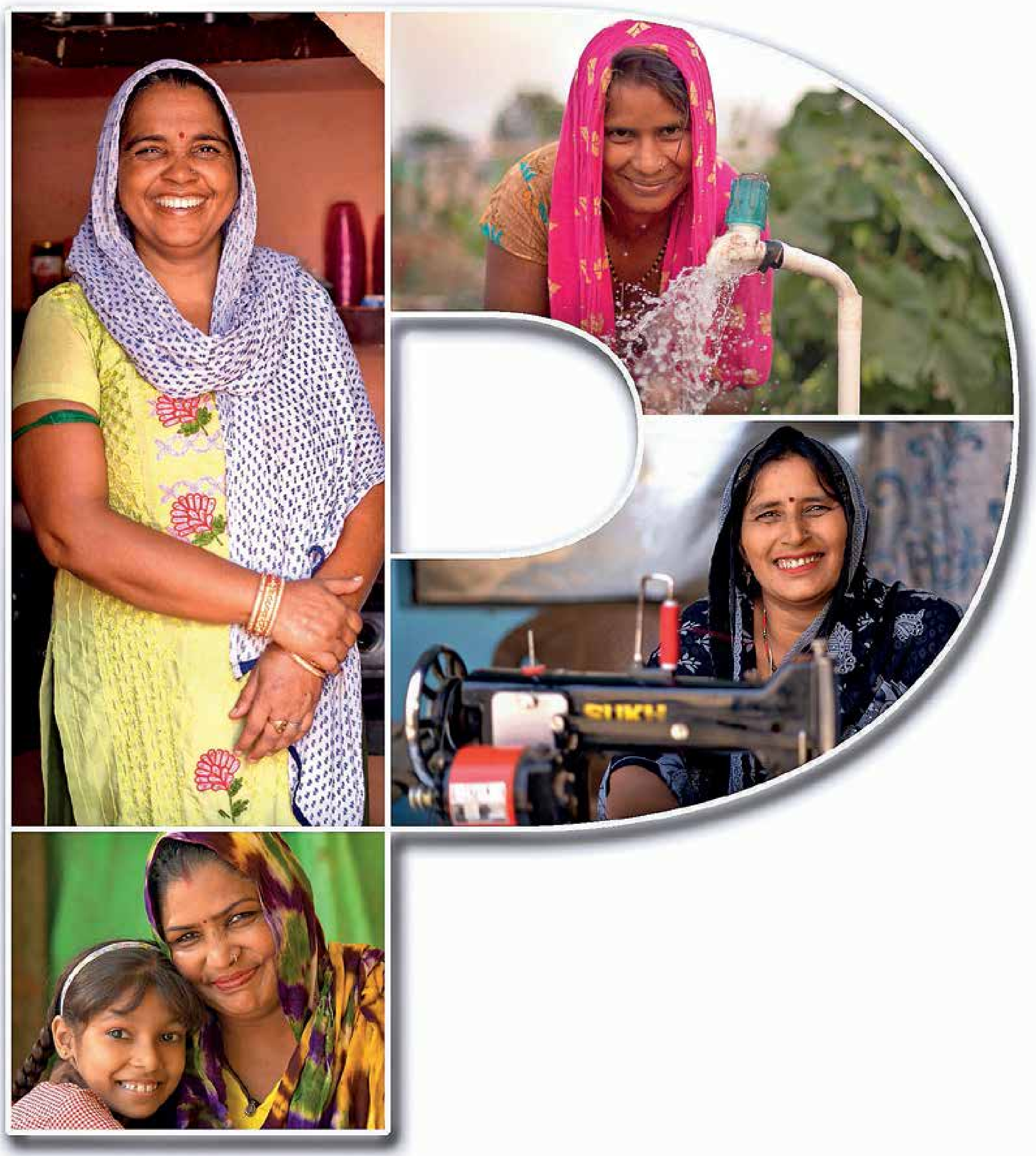

प्रगति की ओर युवा

युवा सशक्तिकरण

जहां भारत में युवाओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, वहीं उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा युवा हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि ऐसी युवा-केंद्रित नीतियां बनाई जाएं, जो शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करें।

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उनके अभिभावक की भूमिका में दिख रही है। सरकार का यह मानना है कि अगर युवाओं को सही सहायता और संसाधन उपलब्ध करवाएं जाएं, तो वे बुलंदियों को छू सकते हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि वे देश के बेहतर भविष्य की नींव हैं और प्रदेश सरकार पिछले आठ वर्षों में सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने वाली कई योजनाओं को सफलता पूर्वक धरातल पर उतारा है, जिस बेहतर भविष्य की रचना कहना तर्कसंगत होगा।

जबकि भारत में दुनिया में युवाओं की सबसे अधिक आबादी है, उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे अधिक युवा हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि युवा केंद्रित नीतियां हों जो शिक्षा, कौशल प्रदान करने और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करें।

पहले, युवाओं को राजनेताओं द्वारा अपनी मर्जी से गुमराह किया जाता था। जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार युवाओं को सार्थक गतिविधियों में शामिल करने और उनके भविष्य को बनाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को सलाह दी "हर यात्रा की एक मंजिल होती है और सफलता तब मिलती है जब हम सही रास्ता चुनते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यूपी में 56 फीसदी आबादी काम में लगी हुई है, जो रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत को रेखांकित करता है। इसके लिए हमें जाति, पंथ, धर्म और क्षेत्र की बाधाओं को पार करना होगा।" मुख्यमंत्री का हमेशा से मानना रहा है कि राज्य में युवाओं के पंखों को उड़ान देने और युवाओं के लाभांश की क्षमता को अधिकतम करने के लिए हर संसाधन मौजूद है।

मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल से पहले फरवरी 2016 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 18 फीसदी थी। वर्तमान में यह 3 फीसदी है। पिछले 8 वर्षों में विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 3.75 लाख से अधिक संविदा नौकरियां दी गईं, जबकि 2 करोड़ से अधिक लोगों को निजी और एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार मिला। वहीं 1.38 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई।

नई आउटसोर्सिंग नीति के माध्यम से कार्मिकों की सुरक्षा और व्यवस्था में पारदर्शिता के मद्देनजर आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया चल रही है। पिछली सरकारें लाखों युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार रही हैं। परीक्षाओं के निष्पक्ष संचालन के लिए यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम लागू किया गया। रोजगार मिशन समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है और अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यूपीपीएससी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। अन्य विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से कई अवसर खुले हैं। उदाहरण के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में निवेश प्रस्तावों से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

- 2,800 से अधिक प्रशिक्षण केंद्रों में 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- 2017-2025 के बीच 14,13,716 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- मिशन ने 5,66,483 युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद की।
- उत्पादन और सेवा क्षेत्रों की 24 प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं के साथ साझेदारी की गई।

- ओडीओपी वित्तपोषण योजना के तहत दिसंबर 2024 तक 17,041 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 72,744 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गई। 2,54,887 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक 28,419 लाभार्थियों को 81,965 लाख रुपये मार्जिन मनी वितरित किया गया तथा 2,27,352 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 29,296 लाभार्थियों को 81,183 लाख रुपये मार्जिन मन वितरित किये गये तथा 12,34,368 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत 3,68,076 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण। 2 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
- मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में 01 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण एवं प्रशिक्षण।

शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाना

इससे मिशन रोजगार के तहत 1,890 व्याख्याकारों, 6,314 सहायक शिक्षकों

और 219 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पूरी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार कौशल प्रशिक्षण और नई नवाचारपूर्ण विचारों को तराशने के महत्व पर जोर दिया है। सरकार ने विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई और कौशल विकास मिशन के माध्यम से 25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया, जिससे 10.20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। राज्य में 50 से अधिक इनक्यूबेटर और 7,200 स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं। स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में 22,319 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए छात्र उद्योग 4.0 के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उन्नत कंप्यूटिंग (रोबोटिक्स) जैसी उभरती तकनीकों में महत्वपूर्ण कौशल सीख रहे हैं।

खेलों के लिए निर्णायक युग

देश ने पिछले कुछ वर्षों में खेलों और एथलेटिक्स में अभूतपूर्व सफलता देखी है। सरकार के निरंतर सहयोग से उत्तर प्रदेश से ही विश्व स्तरीय एथलीट उभरकर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भविष्य की तैयारी में विश्वास रखते हैं, जो एथलीटों के लिए बिल्कुल सही है। इस दिशा में बढ़ाए गए कदम इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार खेलों में नई जान फूंकने के लिए कितनी तैयार है।

- उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति-2020 को मंजूरी। राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी
- अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति
- मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना

हमारा लक्ष्य स्कूल शिक्षा-उन्नत भविष्य
शिक्षक दिवस के अवसर पर
योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
संदीप सिंह
गुलाब देवी

SPORTS AWARDS

- ओलंपिक खेलों (व्यक्तिगत श्रेणी) में स्वर्ण पदक के लिए 6 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 4 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार
- ओलंपिक खेलों (टीम खेलों) में स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार
- एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 75 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया है।
- राष्ट्रमंडल खेलों या विश्व कप से संबंधित प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक के लिए 1.5 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 75 लाख रुपये और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपये का पुरस्कार
- ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपये और राष्ट्रमंडल खेलों तथा एशियाई खेलों में

भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपये का प्रोत्साहन

- मेजर ध्यानचंद डिजिटल हॉकी संग्रहालय का उद्घाटन और एकलव्य क्रीड़ा कोष (एकलव्य खेल निधि) का निर्माण किया गया
- एक जिला-एक खेल योजना के अंतर्गत 'खेलो इंडिया केंद्र' की स्थापना कर प्रदेश के 75 में से 72 जिलों में प्रशिक्षण संचालित
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान का विकास, अब तक 82 स्टेडियम स्थापित
- वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना प्रक्रियाधीन
- वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और सहारनपुर, फतेहपुर,

बलिया और वाराणसी के सिगरा में खेल स्टेडियमों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है

- गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह जल्द ही पूरा हो जाएगा

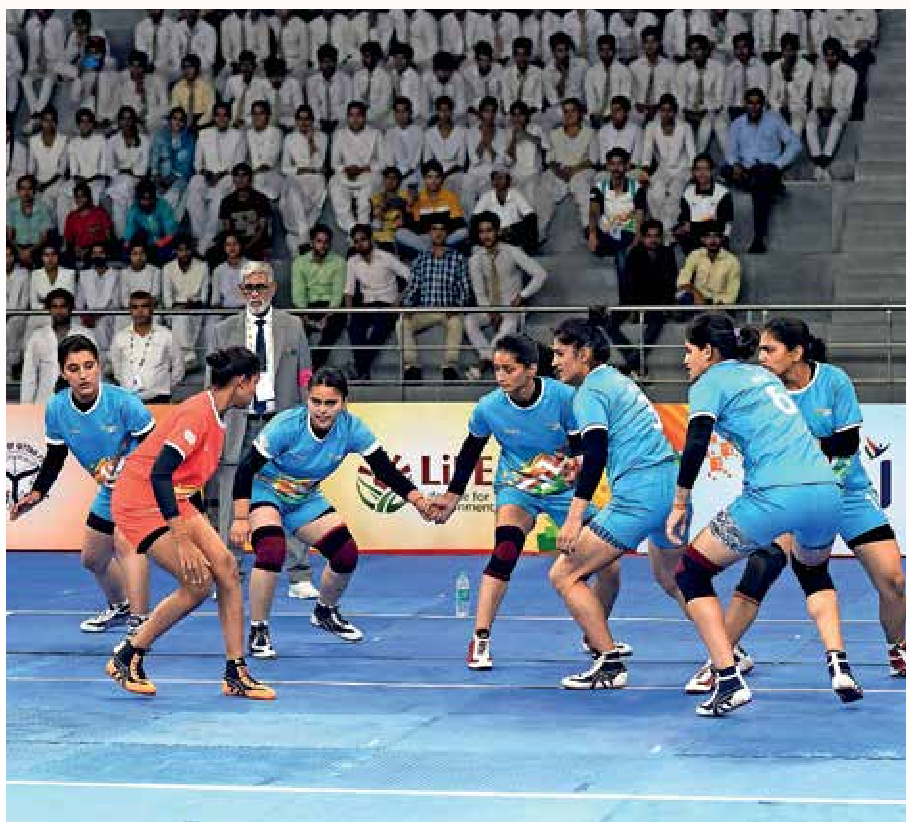

मिशन रोजगार

कुशल कार्यबल का निर्माण

कुशल और सक्षम कार्यबल तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को ठोस कदमों का पूरा साथ मिला है, जिसके चलते राज्य के युवा योग्य और शिक्षित बनकर वैश्विक कार्यबल का हिस्सा बन रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 5 दिसंबर, 2020 को शुरू किया गया मिशन रोजगार, राज्य के युवाओं के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह कार्यक्रम सरकारी नौकरियों, निजी क्षेत्र के अवसरों और कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के एक व्यापक प्रयास के रूप में विकसित हुआ है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, पिछले आठ वर्षों (2017-2025) में मिशन रोजगार की प्रगति का विस्तृत अवलोकन नीचे दिया गया है।

मिशन रोजगार की प्रमुख उपलब्धियां (2017-2025)

सरकारी नौकरियां:

- पिछले आठ वर्षों में 7.5 लाख से 8.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के युवाओं का महत्वपूर्ण सशक्तिकरण हुआ है।
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं:
- **UPPSC :** 1 अप्रैल, 2017 से 20 मार्च, 2025 तक 48,593 उम्मीदवारों का चयन किया गया। सबसे अधिक भर्ती वर्ष 2019-20 रहा, जिसमें 13,893 चयन हुए, जबकि 2024-25 (20 मार्च, 2025 तक) में 1,918 उम्मीदवारों का चयन किया गया।
- **UPSSSC:** 46,032 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिसमें 2022-23 में अधिकतम 11,800 चयन हुए। 2024-25 में, 6,106 युवाओं ने UPSSSC के माध्यम से नौकरी हासिल की।
- **पुलिस भर्ती:** एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में 27,178 महिलाओं सहित 2.16 लाख पुलिसकर्मियों की निष्पक्ष और योग्यता-आधारित भर्ती शामिल है, जिसने राज्य की

कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और उत्तर प्रदेश पुलिस को भारत में सबसे मजबूत पुलिस बलों में से एक के रूप में स्थापित किया है।

- लगभग 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में 3.75 लाख अनुबंध-आधारित नौकरियां शामिल हैं।

निजी क्षेत्र और एमएसएमई से रोजगार सृजन:

- मिशन रोजगार ने निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की 96 लाख इकाइयों के माध्यम से 2 करोड़ रोजगार प्रदान किए हैं, जो देश में सबसे अधिक है और रोजगार के अवसरों को काफी बढ़ा रहा है।
- यह पहल राज्य के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें रोजगार सृजन एक प्रमुख प्रेरक शक्ति है।

वैश्विक रोजगार के अवसर:

- जुलाई 2025 में औपचारिक रूप से शुरू किए गए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का लक्ष्य सालाना 1 लाख घरेलू और 25,000-30,000 विदेशी नौकरियां प्रदान करना है।
- 6,000 से ज्यादा मजदूरों को मुख्य रूप से निर्माण कार्यों के लिए इजराइल भेजा गया है, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन और आवास के साथ 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक की कमाई होती है। इससे अकेले इजराइल से सालाना 1,400 करोड़ रुपये की आय हुई है।
- जर्मनी (नर्स), जापान (देखभालकर्ता) और क्रोएशिया (इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर) जैसे देशों में भी अवसर तलाश जा रहे हैं।
- उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला सरकारी विदेशी भर्ती लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिससे निजी भर्ती एजेंटों पर निर्भर हुए बिना सीधे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरी मिल सकती है।
- 'मिशन रोजगार' के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2017 से पहले 18-19% से घटकर पिछले छह वर्षों में 3-4% हो गई, जो मिशन रोजगार और संबंधित पहलों की सफलता को दर्शाता है।

मिशन रोजगार ने पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश के रोजगार परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इस दौरान 7.5–8.5 लाख सरकारी नौकरियां, 2 करोड़ निजी क्षेत्र/एमएसएमई नौकरियां उपलब्ध कराई गईं और अंतरराष्ट्रीय अवसरों को भी बढ़ावा मिला, जिससे उल्लेखनीय विदेशी प्रेषण प्राप्त हुए। इस पहल का फोकस पारदर्शिता, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर रहा है, जो राज्य के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप है। हांलाकि, प्रति वर्ष 1.25 लाख नौकरियों (देश और विदेश दोनों) का लक्ष्य हासिल करना और इसे बढ़ाकर 2 करोड़ नौकरियों के प्रक्षेपित लक्ष्य तक ले जाना निरंतर प्रयासों, मजबूत अवसंरचना और स्पष्ट रिपोर्टिंग की मांग करता है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पहले ही अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय दे चुकी है।

कौशल विकास और सहायता:

- इस मिशन में राज्य के 36 लाख पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण और करियर परामर्श शामिल हैं।
- विदेशों में रोजगार क्षमता बढ़ाने और संचार संबंधी बाधाओं को दूर

करने के लिए चार से पांच विदेशी भाषा शिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

- यह पहल नौकरी की मांग के सर्वेक्षण, कौशल अंतराल की पहचान, प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास और नियुक्ति के बाद सहायता प्रदान करती है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को उद्यम सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे दूसरों को सूक्ष्म उद्योग शुरू करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

पारदर्शिता और डिजिटलीकरण:

- समूह क, ख और ग के पदों के लिए पारदर्शी और त्वरित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार व देरी को कम करने के लिए ई-अध्ययन पोर्टल शुरू किया गया। ई-अध्ययन पोर्टल और डिजिटल सुधारों के माध्यम से पारदर्शिता पर ध्यान देना सराहनीय है और इसे सरकारी नौकरियों में उम्मीदवारों के निष्पक्ष चयन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- श्रम विभाग ने कारखाना निरीक्षण और ई-ऑफिस प्रणाली जैसे डिजिटल उपकरणों को अपनाया है, जिससे इसे राज्य में शीर्ष ई-ऑफिस के रूप में मान्यता मिली है।
- निर्माण श्रमिकों के लिए आवेदन और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने के लिए यूपीडेस्को द्वारा एक नया डिजिटल पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण

- एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के तहत, महिलाओं को अब सभी खतरनाक उद्योगों की 29 श्रेणियों (पहले 12 तक सीमित, बाद में 16 तक सीमित) में काम करने की अनुमति है, बशर्ते सुरक्षा शर्तें पूरी हों। इस कदम का उद्देश्य समान रोजगार के अवसर प्रदान करना और उत्तर प्रदेश के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना है।
- निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए कल्याणकारी लाभों में वृद्धि की गई है, विवाह सहायता को 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का प्रस्ताव है।

असंगठित क्षेत्र का औपचारीकरण

- 15,000 प्रति माह से कम आय वाले श्रमिकों के लिए एक असंगठित कर्मकार बोर्ड स्थापित करने की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें पहचान पत्र के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 30 लाख श्रमिकों की पहचान की गई है।
- जालौन जिले के एक गांव ने शून्य गरीबी का लक्ष्य हासिल किया है, जो गरीबी उन्मूलन प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की संरचना

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत औपचारिक रूप दिया गया है, एक बहु-स्तरीय संरचना के माध्यम से संचालित होता है:

- **शासी परिषद:** मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में।
- राज्य संचालन समितिः मुख्य सचिव के नेतृत्व में।
- राज्य कार्यकारी समितिः श्रम एवं रोजगार के प्रमुख सचिव द्वारा पर्यवेक्षण।
- **राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू):** निदेशक द्वारा प्रबंधित।

मिशन रोजगार के लिए बजटीय सहायता

वित्त वर्ष 2025 में 200 करोड़ रुपये का आवंटन मिशन को समर्थन प्रदान करता है, साथ ही इसकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए एक प्रस्तावित कॉर्पस फंड भी है। ऐसे में कहना सही होगा कि ये बजटीय प्रावधान मिशन को तेज गति प्रदान कर रहे हैं।

सशक्त महिला लाभार्थी

जनकल्याण एवं सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता सरकारी योजनाओं में झलकती है। 2017 से अब तक लाखों महिलाओं को कल्याणकारी नीतियों का लाभ मिला है, जिससे उनके जीवन के कई पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार का दृढ़ विश्वास रहा है कि प्रगति उन महिलाओं को वंचित नहीं कर सकती जो कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा भी हैं। केंद्रीय योजनाओं के मिशन-मोड कार्यान्वयन के माध्यम से, राज्य ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावशाली पहल की है। "जो समाज महिलाओं की पूजा करता है, वह स्वाभाविक रूप से सक्षम और शक्तिशाली होता है।" मुख्यमंत्री का यह कथन ऐसी नीति नियोजन की प्रेरक शक्ति है जो महिलाओं के जीवन को आकार देती है और भविष्य के लिए लाभ प्रदान करती है।

महिलाओं से जुड़ी योजनाएं किसी क्रांति से कम नहीं हैं

- ऐसा ही एक कार्यक्रम, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंतर्गत 'कन्या जन्मोत्सव' पहल ने लड़कियों के जन्म का जश्न मनाकर और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर एक राष्ट्रीय मिसाल कायम की है। अब तक, राज्य भर में 3,822 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें 35,489 नवजात लड़कियों के जन्म का जश्न मनाया गया।
- नवंबर 2024 तक, उत्तर प्रदेश के लखपति दीदी कार्यक्रम ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस पहल के तहत राज्य में 1.37 लाख से ज्यादा महिलाएं 'लखपति' बन चुकी हैं, यानी अब उनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक है। इस योजना से 13.28 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगले तीन वर्षों में 28.92 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
- अक्टूबर 2017 में शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह

महिला सशक्तिकरण के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता सरकार की योजनाओं में झलकती है। 2017 से अब तक लाखों महिलाओं ने कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठाया है, जिसने उनके जीवन के कई पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

योजना, सामूहिक विवाहों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को लाभ होता है। शुरुआत में, इस योजना में प्रति जोड़े 51,000 रुपये की पेशकश की गई थी। हालांकि, 2025 में एक महत्वपूर्ण संशोधन के बाद यह सहायता बढ़कर 1 लाख रुपये प्रति जोड़ा हो गई, और वार्षिक आय पात्रता 2 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई।

- उत्तर प्रदेश में 22 मई, 2020 को शुरू की गई बीसी सखी योजना ने 50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग संवाददाता (बीसी सखी) के रूप में नियुक्त करके ग्रामीण वित्तीय समावेशन में बदलाव लाई है। ये महिलाएं जमीनी स्तर पर आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक बीसी सखी को छह महीने के लिए 4,000 रुपये का मासिक मानदेय मिलता है, साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उपकरण सहायता भी मिलती है। उनके प्रयासों से प्रभावशाली परिणाम मिले हैं, जिससे सामूहिक रूप से 31,626 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेनदेन संभव हुए हैं।
- महिला सामर्थ्य योजना (जिसे महिला समृद्धि योजना के नाम से भी जाना जाता है) ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इस योजना के तहत, प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को 25,000 रुपये का पर्याप्त प्रारंभिक अनुदान मिलता है। उन्हें 2 लाख रुपये तक के ऋण पर 2% ब्याज सहायता, निःशुल्क कौशल विकास कार्यशालाएं और साझा मशीनरी तक पहुंच का भी लाभ मिलता है। साल 2025 के मध्य तक, इस व्यापक सहयोग से 4,500 स्वयं सहायता समूहों

आंगनबाड़ियों का कायाकल्प

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि। 3.73 लाख महिलाएं लाभान्वित।
- जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने 6,591 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया।
- आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण योजना के अंतर्गत पोषाहार वितरण में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू।
- कुपोषण और पोषण की स्थिति की पहचान के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में चार प्रकार के विकास निगरानी उपकरणों और मोबाइल फोन की उपलब्धता।

युवा एवं महिलाएं

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2021–2025) के अंतर्गत महिला लाभार्थी

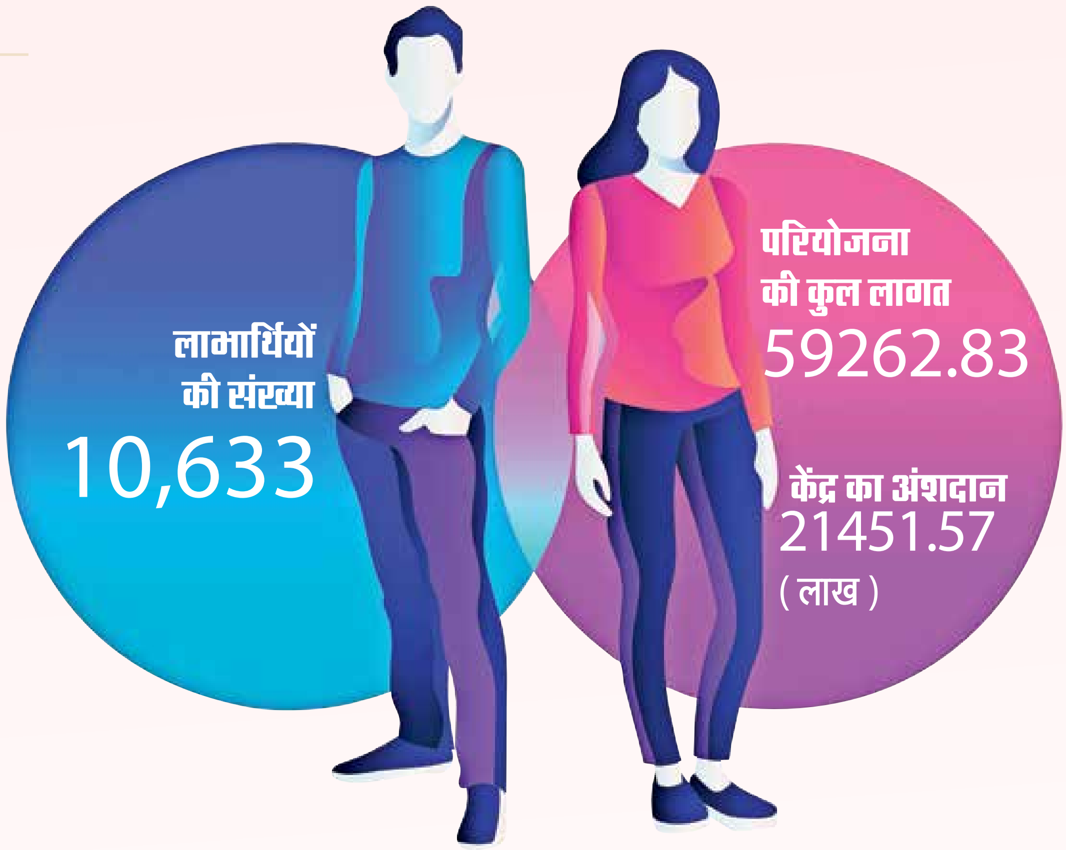

की 1.2 लाख से अधिक महिलाओं ने अपने परिवार की आय में 35% तक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जो इस योजना की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है।

- 2017 में शुरू की गई, रक्षा बंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना ने पिछले आठ वर्षों में लाखों महिलाओं को लाभान्वित किया है।

पिछले आठ वर्षों में, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 22.12 लाख लाभार्थी, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 30.98 लाख लाभार्थी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के अंतर्गत 18,990 लाभार्थी और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत 53,610 लाभार्थी हुए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 95 लाख महिलाएं 873534 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), 57482 ग्राम संगठनों और 3137 संकुल स्तरीय संघों से जुड़ी हैं। आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 2510 उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की गईं। सरकार ने पारिवारिक ढांचे को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से पिछले आठ वर्षों में 60 लाख से ज्यादा माताओं को लाभ हुआ है।

पिछली सरकारों ने महिलाओं में पोषण के महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी की, जिसका सीधा असर संतान पर पड़ता है। पहले की नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में विफल रहीं और कई महिलाएं अदूरदर्शिता के कारण बीमारियों का शिकार हुईं। सरकार ने अपनी नीतियों को घर-घर पहुंचाया है, जिससे जीवन में सुधार हुआ है।

- राज्य में 0 से 5 वर्ष के बच्चों में कम वजन (उम्र के हिसाब से कम वजन) की दर में 7.5 प्रतिशत की गिरावट (NFHS-445)
- गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दर में 5-1 प्रतिशत अंकों की कमी आई।
- निरंतर प्रयासों से पुरुष और महिला लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार। प्रति 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं।
- 70 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पौष्टिक भोजन का वितरण।

- मातृ मृत्यु दर, छात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व गिरावट।
- पूरक पोषण योजना के अंतर्गत 2.12 करोड़ लाभार्थियों (महिलाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं) को पोषण आहार उपलब्ध कराया गया है।
- किशोरियों के लिए योजना के अंतर्गत, राज्य के 8 आकांक्षी जिलों की 2.10 लाख किशोरियों की पहचान की गई है और उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।
- संस्थागत प्रसव 84 प्रतिशत से अधिक हुआ है।

अन्य लाभ

- अब तक वन स्टॉप सेंटरों से 2.03 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।
- 89 स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिंक शौचालयों का निर्माण और 181-महिला हेल्पलाइन योजना के अंतर्गत 7.17 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।
- 7 जिलों (वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर नगर, झांसी, आगरा, गोरखपुर) में माता अहिल्याबाई होल्कर जी के नाम पर श्रमजीवी छात्रावास।
- राज्य में 5 वर्ष की आयु के बच्चों में बौनेपन (आयु के अनुसार कम ऊंचाई) की दर में 6.5 प्रतिशत की कमी (एनएचपीएस-445)

शहरी विकास

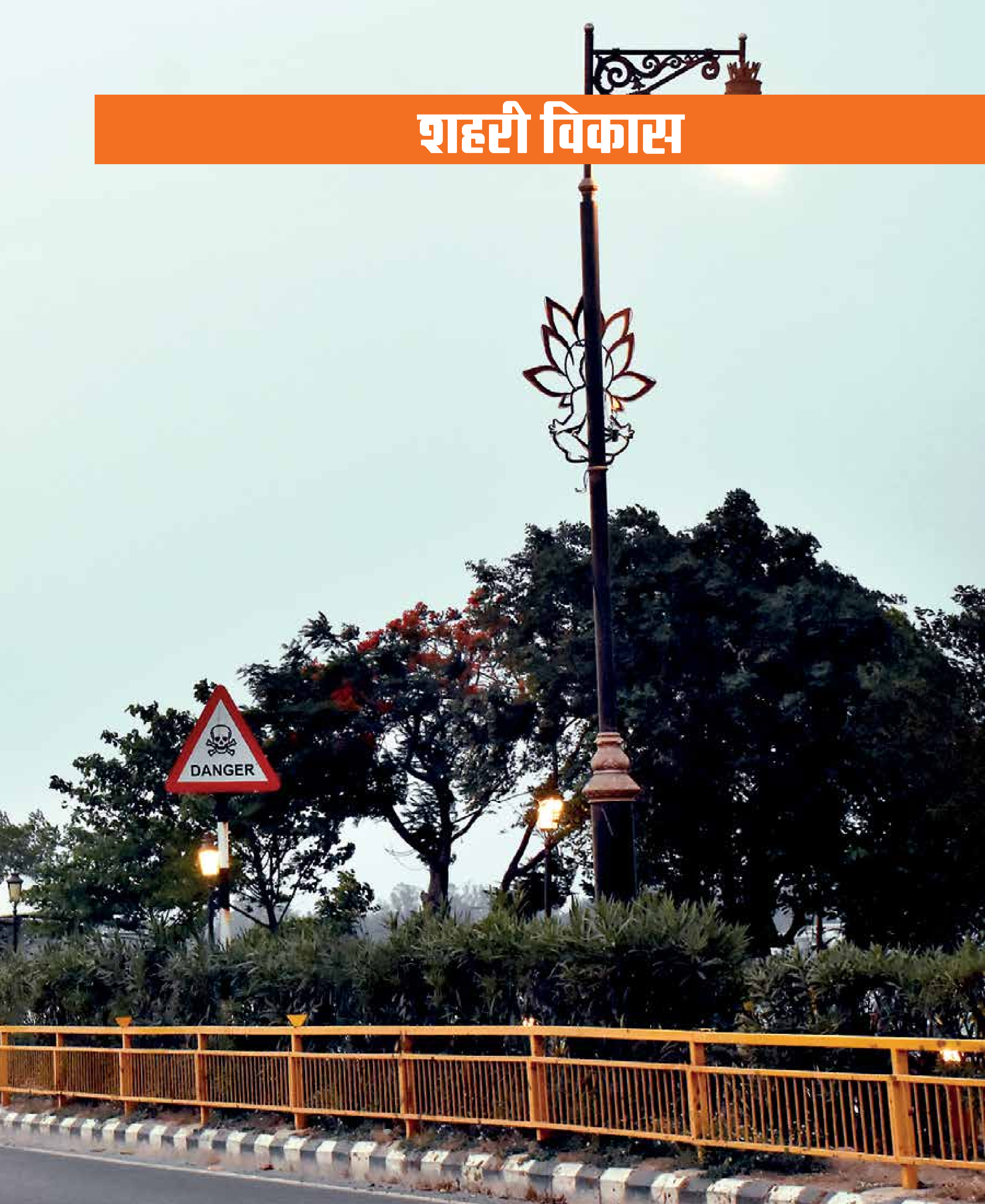

पौधरोपण से पर्यावरण संरक्षण

वन एवं पर्यावरण

पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 200 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान ने राज्य के सामूहिक प्रयासों को एकजुट किया है।

पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 200 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान ने पूरे राज्य में सामूहिक प्रयासों को गति दी है। उत्तर प्रदेश का वृक्षारोपण अभियान राज्य के हरित क्षेत्र को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों और आम जनता दोनों की भागीदारी शामिल है। वर्ष 2024-25 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में 36.81

हरियाली ही नई खुशहाली

- 2025 में पौधरोपण अभियान के तहत यूपी ने एक दिन में 37.21 करोड़ पौधे लगाकर इतिहास रचा।
- अभियान में नदियों किनारे 4.12 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जो 559 वर्ग किमी की है।
- हरित आवरण वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।
- लगाए गए पौधों और पेड़ों की नियमित निगरानी के लिए जियो-टैगिंग के लिए कड़े कदम उठाए गए।
- उत्तर प्रदेश में 948 विरासत वृक्ष हैं जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य के हरित आवरण को 15% तक बढ़ाने के लिए पांच वर्षों (2022-23 से 2026-27 तक) में 175 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है।
- यूपी डॉल्फ़िन (2397) की अधिकतम संख्या के साथ पहले स्थान पर है।
- पलिया से हवाई/उड़ान सेवाएं शुरू। दुधवा टाइगर रिज़र्व में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना

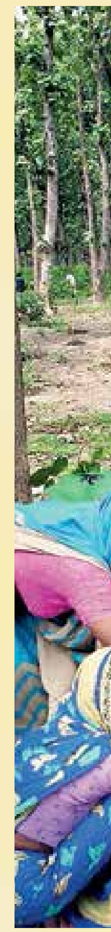

- 223 महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों के जलग्रहण क्षेत्रों में 'आर्द्रभूमि संरक्षण वन' स्थापित किए गए
- 'पवित्र धारा वृक्षारोपण' योजना के अंतर्गत, गंगा, यमुना, सरयू, हिंडन और गोमती के जलग्रहण क्षेत्रों में 3.72 करोड़ पौधे लगाए गए।

करोड़ पौधे लगाए। वर्ष 2025 का अभियान वन भूमि, ग्राम पंचायत और सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेसवे, चार-लेन सड़कें, नहरें, विकास प्राधिकरणों की भूमि तथा मेडिकल और शैक्षिक संस्थानों सहित विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण को शामिल करता है।

हरित क्षेत्र को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभिनव 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में 13 प्रमुख नदियों के किनारे 24,271.66 हेक्टेयर क्षेत्र में 4.12 करोड़ पौधे लगाए गए। इन नदी तटों पर नीम, पीपल और पाकड़ जैसे त्रिवेणी पौधे भी लगाए जाएंगे। अकेले यमुना के किनारे 6,712.44 हेक्टेयर क्षेत्र में 1.09 करोड़ पौधे लगाए गए, गंगा के किनारे 4,356.13 हेक्टेयर क्षेत्र में 77 लाख पौधे लगाए गए। इसके अलावा बेतवा के किनारे 53 लाख, साई के किनारे 34.25 लाख, गोमती के किनारे 33.56 लाख, केन के किनारे 12.22 लाख और हिंडन के किनारे 4.29 लाख पौधे लगाए गए हैं।

2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
25.87 करोड़	30.53 करोड़	35.49 करोड़	36.16 करोड़	36.81 करोड़

...रोड़ से अधिक पौधरोपण की शानदार उपलब्धि

पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल

- **सामाजिक वानिकी:**

  राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में इमारती लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी, चारा, लघु वनोपज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामुदायिक भूमि, नहरों, रेल और सड़क किनारे उपलब्ध भूमि पर पौधरोपण किया जाता है। यह प्रदेश के हरित क्षेत्र के विस्तार में अहम भूमिका निभा रहा है।

- **शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी:**

  इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और सौन्दर्यीकरण के लिए सड़कों और पार्कों के किनारे अनुपयोगी भूमि पर सजावटी और छायादार वृक्ष लगाने की प्रक्रिया सतत जारी है।

- **हरित पट्टी विकास योजना:**

  यह योजना वन निगम से वित्त पोषण के माध्यम से चलाई जा रही है।

अयोध्या: आस्था और प्रगति का नगर

विकास योजना से खिल उठा अयोध्या धाम

अयोध्या तीर्थ नगरी से आगे बढ़कर एक स्मार्ट और वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ शहर बन रहा है। बेहतर परिवहन व्यवस्था, आधुनिक नागरिक सेवाएं, हरित पहलें, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के साथ यह शहर विश्वस्तरीय गंतव्य के रूप में उभर रहा है।

अयोध्या एक समग्र परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है: यह एक तीर्थ नगरी से एक स्मार्ट, टिकाऊ, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हो रहा है। मजबूत परिवहन संपर्क, आधुनिक नागरिक सेवाओं, हरित पट्टियां सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक परियोजनाओं के साथ, यह नगर 2031 तक स्वयं को एक विश्वस्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर देगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

अयोध्या, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन शहर है, जिसका ऐतिहासिक,सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, विशेष रूप से हिंदू धर्म में, क्योंकि यह भगवान राम की जन्मभूमि है। हाल के वर्षों में, अयोध्या ने विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त विकास देखा है, जिसका उद्देश्यइसके बुनियादी ढांचे, पर्यटन क्षमता और समग्र शहरी वातावरण को बेहतर बनाना है। इसमें नए राजमार्गों का निर्माण, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और बढ़ते आगंतुकों की सुविधा के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन शामिल है।

धार्मिक और सांस्कृतिक परियोजनाएं: धार्मिक स्थलों के विकास और नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिनमें भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शामिल है, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। इसने तीर्थयात्रा सर्किट, संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्रों जैसी संबंधित सुविधाओं के विकास को भी बढ़ावा दिया है।

पर्यटन संवर्धन: अपनी समृद्ध विरासत के साथ, अयोध्या को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। बेहतर आवास, निर्देशित पर्यटन और सूचना केंद्र जैसे उन्नत पर्यटक बुनियादी ढांचे का उद्देश्य आगंतुकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है।

शहरी विकास और पर्यावरण: निवासियों और आगंतुकों दोनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छता, जल आपूर्ति और हरित स्थानों में सुधार की पहल की गई है। शहर में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है।

आर्थिक विकास: पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आमद ने स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित किया है और आतिथ्य, खुदरा और सेवाओं में नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। छोटे और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने वाली सरकारी योजनाएं भी शहर के आर्थिक

विकास में योगदान दे रही हैं।

संक्षेप में, अयोध्या का विकास अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के एक संतुलित दृष्टिकोण की विशेषता है। इन प्रयासों का उद्देश्य अयोध्या को एक सुसज्जित, जीवंत शहर में बदलना है जो अपने ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए सतत विकास को बढ़ावा दे।

ग्रीन अयोध्या सतत शहरी विकास के लिए एक दृष्टिकोण: हरित अयोध्या एक परिवर्तनकारी पहल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक शहर अयोध्या में पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ावा देना है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध शहर के रूप में, अयोध्या हरित विकास सिद्धांतों को अपना रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका विकास पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक शहरी नियोजन के साथ संरेखित हो। हरित अयोध्या परियोजना कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:

- **वनरोपण और शहरी हरित स्थान:** वायु गुणवत्ता में सुधार, मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराने और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए वृक्षावरण बढ़ाना और पार्क, उद्यान और हरित पट्टी विकसित करना।
- **स्थायी अवसंरचना:** शहर के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल निर्माण पद्धतियों और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा

स्रोतों को शामिल करना।

- **अपशिष्ट प्रबंधन:** पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पृथक्करण, पुनर्चक्रण और खाद बनाने पर ज़ोर देते हुए प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना।
- **जल संरक्षण:** स्थायी जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार और जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।
- **जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी:** पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक अभियानों और सहभागी कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को शामिल करना।

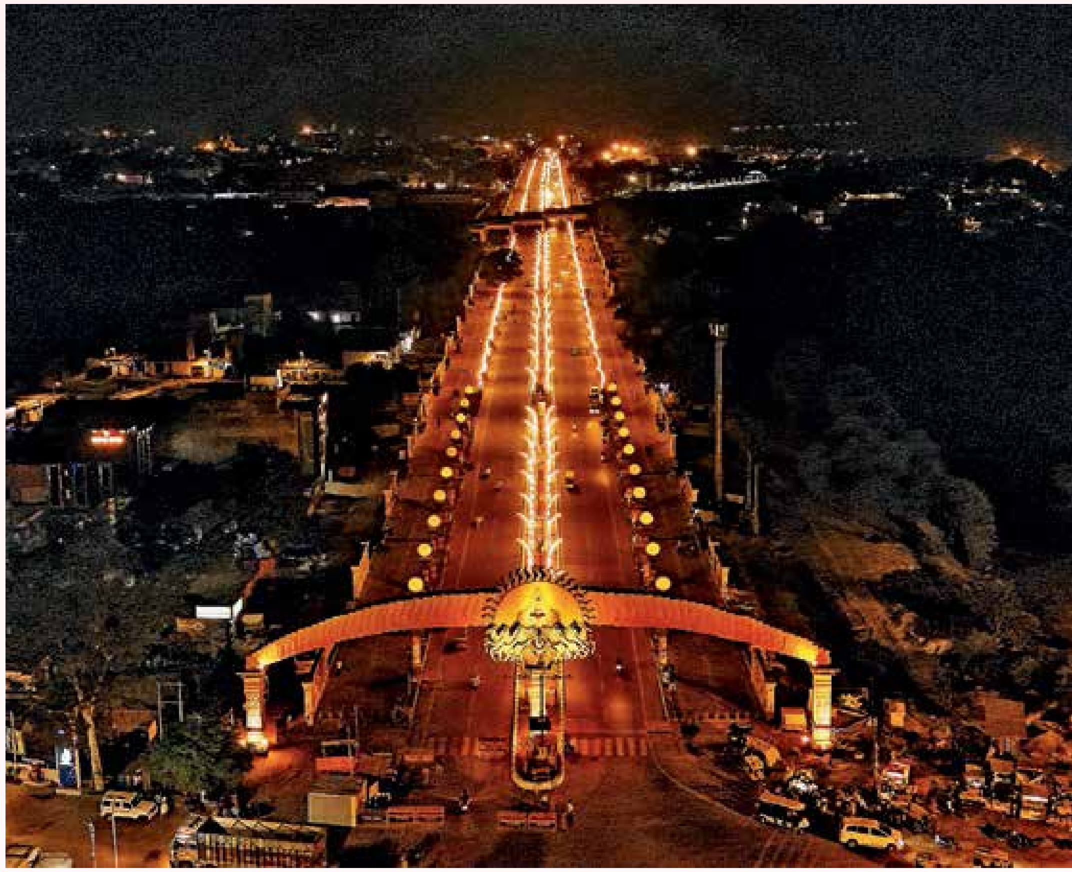

इन तत्वों को एकीकृत करके, ग्रीन अयोध्या का उद्देश्य एक आदर्श शहर बनाना है जो विरासत संरक्षण और पारिस्थितिकी अखंडता के बीच संतुलन बनाए रखे। यह पहल स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसे व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जो एक स्वस्थ, स्वच्छ और अधिक टिकाऊ शहरी पर्यावरण में योगदान देती है। संक्षेप में, ग्रीन अयोध्या केवल एक पर्यावरणीय परियोजना नहीं है, बल्कि शहरी विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जो शहर के ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर

अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण पिछले साल पूरा हुआ

और तीन मंजिला मंदिर का भूतल जनवरी 2024 में भक्तों के लिए खोल दिया गया। चारदीवारी और सभागार सहित पूरे मंदिर परिसर का निर्माण 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। मुख्य देवता, राम लला का अभिषेक समारोह जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था, जबकि "राम दरबार" का अभिषेक 5 जून, 2025 को आयोजित किया गया था।

उद्घाटन और भूतल का निर्माण पूरा होना: मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी, 2024 को मुख्य देवता, राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ हुआ था। उस समय तीन मंजिला मंदिर का भूतल भक्तों के लिए खोल दिया गया था।

प्रथम चरण का निर्माण पूरा होना: मंदिर निर्माण का पहला चरण पिछले साल पूरा हुआ था।

पूर्ण निर्माण समय-सीमा: मंदिर निर्माण समिति के अनुसार, भूतल का उद्घाटन जनवरी 2024 में हुआ था, जबकि चारदीवारी और सभागार सहित पूरा मंदिर परिसर 2025 में पूरा होने की उम्मीद है।

राम दरबार का प्राण-प्रतिष्ठा: "राम दरबार" का प्राण-प्रतिष्ठा मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान राम और उनके परिवार का एक स्वरूप) की स्थापना 5 जून, 2025 को हुई और अनुष्ठान 3 जून से शुरू हुए ।

वर्तमान कार्य: मंदिर के अन्य हिस्सों का निर्माण अभी भी जारी है, जिसमें परिसर के भीतर सप्त मंदिर में ऋषियों की मूर्तियों की स्थापना भी शामिल है। दूसरी मंजिल पर रामायण को कई भाषाओं में प्रदर्शित करने की भी योजना है।

खुशहाल जीवन

ईज ऑफ लिविंग

जनकल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे जैसे बेहतर आवास, स्वच्छ शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन की आसान उपलब्धता आदि ने उत्तर प्रदेश को 'ईज ऑफ लिविंग' इंडेक्स में ऊपर पहुंचने में मदद की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां एक ओर जनता को राहत दी, वहीं दूसरी ओर उन लोगों को कड़ा संदेश भी दिया जो राज्यवासियों का जीवन कठिन बना रहे थे। उन रियल एस्टेट डेवलपर्स पर सख्त कार्रवाई की गई जो फ्लैट्स की डिलीवरी में अनिश्चित समय ले रहे थे। इसके परिणामस्वरूप आवासीय अवसंरचना में सुधार हुआ। सड़कों का निर्माण हो रहा है, नए ढांचे खड़े हो रहे हैं और लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार के विकास मॉडल ईज ऑफ लिविंग की गति में एक अलग ही विशेषता है। पहले की तुलना में यूपी ने लगातार प्रगति दर्ज की है और राज्य के 14 शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शामिल हुए हैं। यह उपलब्धि राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने से संभव हुई है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्य के सभी 75 जिलों की 762 स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – अर्बन 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत इस वर्ष जून में हुई केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की तीसरी बैठक में लगभग 2.35 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई।

हाल ही में जारी हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स में दुनिया के 40 शहरों को आदर्श पर्यटक गंतव्य के रूप में चुना गया। इनमें कानपुर को भी स्थान मिला और 'हैप्पीनेस सिटी' की श्रेणी में शामिल किया गया। मित्रवत लोगों की श्रेणी में कानपुर 9वें स्थान पर रहा, जहां जीवन प्रत्याशा 70.42 और जीवन-यापन लागत 311.38 दर्ज की गई। वहीं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएमआरबी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में लखनऊ को देश का दूसरा सबसे खुशहाल शहर बताया गया, चंडीगढ़ के बाद। पहले की सरकारों में यह कल्पना करना भी मुश्किल था।

पिछले वर्षों में, यूपी सरकार ने जल जीवन मिशन के 'हर घर जल' अभियान के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण निवासियों को स्वच्छ पेयजल

‘हर घर जल’ अभियान के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण निवासियों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान और स्थानीय प्रदूषण को दूर करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कारगर उपाय अपनाए जा रहे हैं, उसका असर अब धरातल पर दिखने लगा है।

की सुविधा सुनिश्चित हुई है। इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और 99% से अधिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जलापूर्ति की सुविधा मौजूद है।

साल 2024 में, नदियों और जलाशयों के पानी की गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में 68.8% का जबरदस्त सुधार दर्ज किया गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) की हालिया रिपोर्ट में सामने आई, जिसने इस प्रगति का श्रेय प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण पर राज्य के सशक्त फोकस को दिया।

UPPCB ने इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय सरकार की लगातार पहल, बेहतर पर्यावरणीय निगरानी और जल शोधन अवसंरचना में उल्लेखनीय विकास को दिया। यह उपलब्धि राज्य के व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम है और नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण उपायों जैसी योजनाओं की सफलता को दर्शाती है।

अप्रैल 2025 तक, राज्य में 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) हैं, जिनमें से 141 संचालित हो रहे हैं। इनमें से 126 पहले ही पर्यावरणीय मानकों को पूरा कर रहे हैं। 6 यूनिट परीक्षण प्रक्रिया में हैं और आने वाले महीनों में 15 और प्लांट शुरू हो जाएंगे।

निर्माण क्षेत्र के कानूनों में बदलाव

- सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण और विकास उपनियम 2025 के अपने मसौदे में बाजार स्ट्रीट्स को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा 2008 के नियमों को बदलना है।
- यह मसौदा, जो अब जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुला है, आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करता है।
- नए प्रावधानों के तहत, बाजार स्ट्रीट्स के लिए न्यूनतम 12 मीटर का अधिकार-क्षेत्र होना चाहिए – या मास्टर प्लान में निर्दिष्ट के अनुसार – और पूरे भूखंड की गहराई में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति होनी चाहिए।
- भूतल और पहली मंजिलें व्यावसायिक उपयोग के लिए आरक्षित होंगी, जबकि आवासीय उपयोग की अनुमति ऊपरी मंजिलों पर और वैकल्पिक रूप से अनुरोध पर निचली मंजिलों पर दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश भवन उपनियम 2025 के मसौदे में मिश्रित-उपयोग विकास के लिए अद्यतन मानदंड भी शामिल हैं, जिसमें पारगमन-उन्मुख विकास (TOD) क्षेत्रों में स्थित भवनों के लिए संशोधित फ्लोर एरिया अनुपात (FAR) शामिल है।
- 2025 के मसौदे में 2008 के उपनियमों में किए गए सभी संशोधन और अधिसूचनाएं शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य शहरी विकास मापदंडों में व्यापक बदलाव लाना है। पहले उपनियम 2000 में पेश किए गए थे और 2008 में तैयार किए गए वर्तमान उपनियमों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

शहरी क्षेत्रों में आ रहा आमूल चूल परिवर्तन

स्मार्ट सिटी परियोजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से शहरी विकास को एक नया आयाम दिया है। स्मार्ट सिटीज मिशन, तकनीक आधारित व स्थायी समाधान प्रस्तुत कर रहा है।

राज्य भर में शहरी परिदृश्य और बुनियादी ढांचे को आकार देने में नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता है, शहरीकरण की आवश्यकता सामाजिक प्रगति का अभिन्न अंग होता है। निरंतर विकसित हो रहे शहरी बुनियादी ढांचे की गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि सरकार की शहरी विकास योजनाओं को तीव्र गति से क्रियान्वित किया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से शहरी विकास को एक नया आयाम दिया है। बेहतर आवास प्रदान करने के लिए झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास, सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना और मौजूदा जल निकासी व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई उपायों में से हैं। दूरदर्शी मुख्यमंत्री ने बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखा है और नीति निर्माताओं को इसे एक मापदंड के रूप में रखने का निर्देश दिया है।

प्राचीन काल से ही, समाज का विकास शहरों के नियोजित विकास के बाद ही हुआ है। भविष्य का राज्य बनने की अपनी खोज में, उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में उन्नत शहरों के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है।

इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल बनाया है जो एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न निदेशालयों की योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसके मूल में एक स्मार्ट डैशबोर्ड है, जो महत्वपूर्ण मापदंडों पर रीयल-टाइम जानकारी प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 17.70 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है और पूरा भी किया है। आवास उपलब्ध कराना केवल एक सरकारी कदम नहीं है। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि हर परिवार के सिर पर छत हो। पिछली सरकारों ने आवास निधि का दुरुपयोग करके जनता को ऐसे लाभों से वंचित रखना बेहतर समझा। उत्तर

प्रदेश में आवास एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक अधिकार है। अयोध्या, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर में नए नगर निगमों के अलावा 125 नए नगर निकायों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 18 सुरक्षित शहर और 17 स्मार्ट शहर हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत, सभी 17 नगर निगमों में 10,300 करोड़ रुपये से अधिक की 757 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

स्वच्छ नगर

किसी शहर की स्वच्छता और सफाई उसे उन्नत राज्य बनाने के लिए जरूरी है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल नीतिगत उपाय किए हैं, बल्कि जनता में अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा भी जगाई है। एक सच्चा विकसित राज्य वह होता है, जहां जनता सरकार के साथ मिलकर काम करती है।

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत लगभग 09 लाख व्यक्तिगत और 69 हजार से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराकर सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कराने में सफलता प्राप्त हुई है।
- राज्य के शहरों को बाढ़ और जलभराव की समस्या से मुक्त कराने के लिए व्यापक स्तर पर शहरी बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी योजना शुरू की गई है।
- स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जिला मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को विकसित करने की योजना है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 (स्वच्छता सर्वेक्षण-2023) की गंगा नगर श्रेणी में नगर निगम वाराणसी को प्रथम और प्रयागराज को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, साथ ही नोएडा को राज्य स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।
- 8,99,634 व्यक्तिगत और 69,381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराकर सभी स्थानीय निकायों को ओडीएफ घोषित कराने में सफलता मिली है।

शहरों के बीच बढ़ी कनेक्टिविटी

एक समय था जब उत्तर प्रदेश खराब सड़कों और अव्यवस्थित कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता था। यह उपहास और मजाक का विषय बन गया था कि उत्तर प्रदेश के शहरों में बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचना एक असंभव कार्य था। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कमान संभाली, तो उन्होंने आलोचना को प्रशंसा में बदलने का फैसला किया।

अब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब लोग शहरी परिवहन अवसंरचना का उल्लेख करते समय उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। इस समय प्रदेश के 14 जिलों में 740 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो सेवा पहले से ही चालू है। गोरखपुर के लिए डीपीआर तैयार है। इसके अलावा ऐसे तमाम कदम उठाए गए हैं, जो आने वाले समय नगर विकास को नए आयाम प्रदान करेंगे।

- कानपुर, मेरठ, मथुरा के बुनियादी ढांचे को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है।
- रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित हो रहा है। इस कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने का अनुमान है।
- मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना (शहरी) के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन से काशी के गिरजाघर तक रोपवे सेवा निर्माणाधीन है।
- दिल्ली और मेरठ के बीच देश की पहली रैपिड रेल सेवा 'नमो भारत' का शुभारंभ।
- उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मेरठ के बीच देश की पहली आरआरटीएस 'नमो भारत' भी संचालित है।

सुरक्षित जल, हरित वायु

ऐसे समय में जब पर्यावरण संरक्षण एक सार्वभौमिक चिंता का विषय है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास की योजना इस प्रकार बनाई है कि शहर भविष्य के लिए हरे-भरे और टिकाऊ बने रहें।

- अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
- अमृत योजना में स्वीकृत 723 परियोजनाओं में से 556 पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत 9.20 लाख घरों में जलापूर्ति और 8.60 लाख घरों में सीवरेज कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।
- पार्कों और खुले स्थानों के माध्यम

स्मार्ट सिटीज

- उत्तर प्रदेश के कुल 17 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है
- राष्ट्रीय स्तर पर पांच चरणों में दस शहरों, अर्थात् आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी, को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2019-20 के बजट सत्र के दौरान शेष सात नगर निगमों, अर्थात् अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, मथुरा-वृंदावन, शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के विस्तार में शामिल करने करने की घोषणा की।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, 10 स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र और इंटेलिजेंट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली कार्यरत हैं।
- स्मार्ट सिटी रैंकिंग में आगरा और वाराणसी देश के शीर्ष 10 शहरों में शामिल हैं।

से शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए 'उपवन योजना' लागू की गई है। उपवन योजना के तहत, राज्य भर के 17 नगर निगमों को अपने अधिकार क्षेत्र में 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपये तक की राशि देने की पूरी छूट दी गई है। यही नहीं वर्ष 2025 के जुलाई माह में प्रदेश भर में 37 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण करके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री की पहल पर राज्य भर में प्रेरणादायक और 'थीम आधारित' वनों की एक श्रृंखला विकसित की जाएगी। इन्हें शौर्य वन, अटल वन, एकलव्य वन, गोपाल वन और त्रिवेणी वन कहा जाएगा। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों और वृक्षारोपण के लिए समर्पित होगा, जिसमें आवश्यकतानुसार अन्य विभागों को भी शामिल किया जायेगा।

- व्यापक जनभागीदारी से, 2017-18 से 2024-25 तक 204.65 करोड़ पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 19.72 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण वितरित कर उन्हें सशक्त बनाया गया।

प्रशासनिक सुधार

- सरकार ने राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया है और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024 लागू किया गया है।
- आकांक्षी शहर योजना को लागू किया गया है। आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकास खंडों के सफल प्रयोग के बाद 100 नगरीय निकायों में भी इस तरह की योजना लागू करने का फैसला लिया है।
- सभी विकास प्राधिकरणों में भव्य कन्वेंशन सेंटर निर्माणाधीन हैं। नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए हैं।
- मलिन बस्तियों के पुनर्वास हेतु मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021 लागू की गई है।
- दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत में 431 छोटी नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं में मूलभूत सुविधाओं के लिए 1025 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध।
- जन शिकायतों के निवारण हेतु 1533 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर।
- जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था। संपत्ति कर/म्यूटेशन हेतु ऑनलाइन व्यवस्था।

POLICE
HEADQUARTERS

कानून - व्यवस्था

अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस

कानून-व्यवस्था

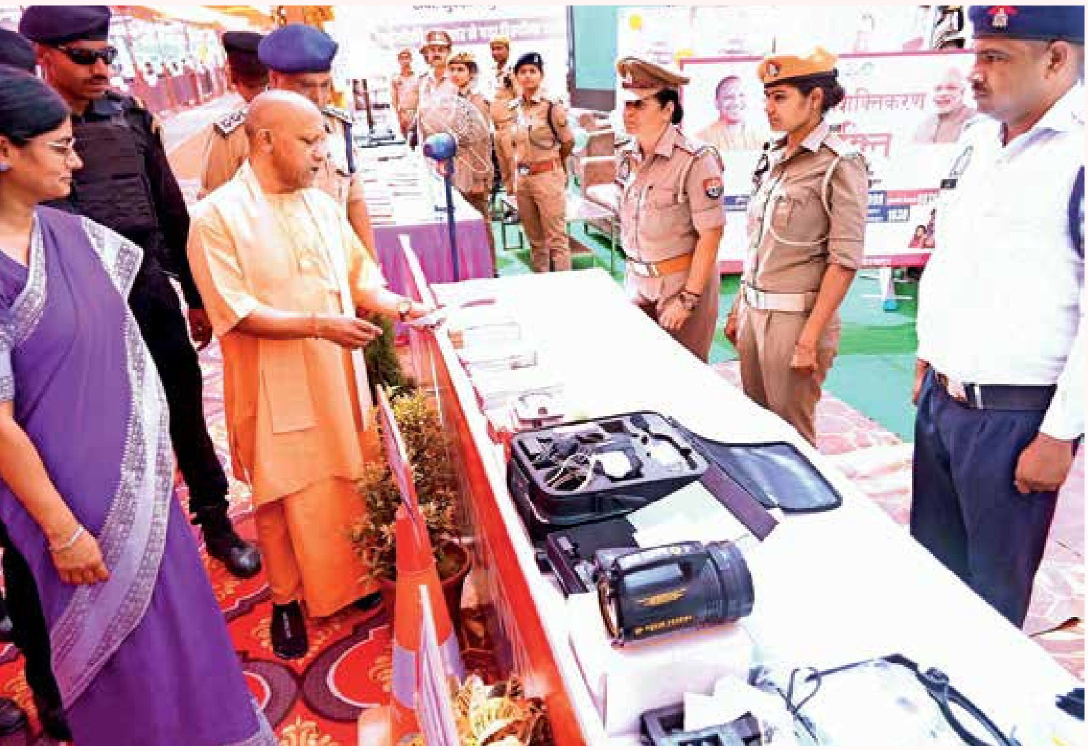

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही कानून-व्यवस्था सुधारने को लेकर गंभीर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और जनता में सुरक्षा एवं विश्वास का माहौल बना है।

यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश माफियावाद, आपराधिक गतिविधियों और इससे निपटने के लिए राजनीतिक शिथिलता के मामले में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। आज, परिदृश्य उलट है और परिणाम राज्य के भीतर और बाहर भी सभी के सामने हैं। सबसे बुनियादी शब्दों में, कानून और व्यवस्था को नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समाज को नियंत्रित करते हैं। यह एक बुनियादी ढांचा देता है जो एक आम आदमी को सही और गलत का विचार देता है। अपने विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की भूमिका है। और पुलिसिंग इसका सबसे बड़ा घटक है। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था समाज की इच्छा को भी दर्शाती है। 2017 से पहले, सड़कें असुरक्षित थीं। वास्तव में, लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युद्ध के मैदान में शूरवीर की तरह सावधानीपूर्वक योजना और अचूक साहस के माध्यम से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा की। समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाले बदलावों को अंजाम देने के लिए दृढ़ निश्चयी और दृढ़ नेता की जरूरत होती है।

योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आते ही यह बात साफ हो गई कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अपराधियों को खुली छूट देने वाली बुराइयों और कुकृत्यों को खत्म करने का समय आ गया है। राज्य अब उन दुष्टों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं रह सकता जो बेखौफ होकर काम करते हैं। दरार पड़ गई और उपाय आकार लेने लगे। लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नामक एक नए सुरक्षा बल का गठन भी किया

गया, जो हो रहे अपराधों की गहन फौरेंसिक जांच करता है। अपराध नियंत्रण का एक पहलू जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, वह है उचित न्यायालय में किसी भी जांच का अनुसरण।

किसी नीति को उसके चरम पर पहुंचाने के लिए किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समर्पित प्रयासों से ई-अभियोजन प्रणाली के प्रयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है जब अपराधियों को सबसे ज्यादा सजा दिलवाई गई । दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में पिछले आठ वर्षों में अब तक 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए तथा 8,118 घायल हुए। इनमें से 28,085 वांछित अपराधियों को जेल भेजा गया। 79,984 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा 130 अपराधियों के विरुद्ध एनएस एक्ट की कार्रवाई की गई। इससे यह पता चलता है कि अपराधियों को सिर्फ पकड़ा ही नहीं गया, बल्कि उनके पैरों पर खड़े होने में सहायक उनकी रीढ़ को भी निशाना बनाया गया है।

गैंगस्टर एक्ट के तहत 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख रुपये से अधिक की चल-अचल अवैध सम्पत्ति जब्त की गई है। वित्तीय कार्रवाई करना अधिक निर्णायक तथा फलदायी साबित हुआ है। प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफियाओं एवं उनके गिरोह के सदस्यों/सहयोगियों में से 1,408 के विरुद्ध कुल 795 अभियोग पंजीकृत कर 617 को गिरफ्तार किया गया, 359 शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई, 18 के विरुद्ध एनएसए, 752 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, माफियाओं एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 4,076 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति जब्त की गई। नवीन अवस्थापना के संदर्भ में 126 नवीन चैकियां, 86 नवीन चौकियां, 04 जल पुलिस चैकियां, 78 महिला पुलिस चैक काउंसलिंग, 75 विद्युत निरोधक थाने, 10 सतर्कता अधिष्ठान शांता,

कानून-व्यवस्था

वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी की संख्या

(2017-2025)

21,023

04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 06 यूपीएसएसएफ, साइबर क्राइम थाने तथा 06 नवीन नारकोटिक्स चैकियां बनाई गई हैं। इससे पता चलता है कि पुलिस संस्था की उपस्थिति बढ़ी है तथा सभी कार्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, यूपी-112 का रिस्पांस समय 7 मिनट 24 सेकेंड से घटकर 05 मिनट 42 सेकेंड हो गया है। एक्स पर प्राप्त शिकायतों का सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान लेकर वर्ष 2017 से अब तक 21 हजार 655 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन विधेयक पारित किया गया, जिससे किसी लड़की को बहला-फुसलाकर उससे शादी करने और उसका अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। किसी भी सुरक्षित समाज की आधारशिला महिलाओं की सुरक्षा होती है। एक सभ्य समाज में, एक महिला को अपराध का लक्ष्य बनने के डर के बिना सड़कों पर स्वतंत्र रूप से आने-जाने में सक्षम होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी थी कि राज्य महिला सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अपराध न हों, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं: महिला पावर लाइन 1090, जीआरजेपी, अग्निशमन सेवा, महिला हेल्पलाइन 181 सेवा का एकीकरण किया गया है। हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन 1090 का गठन किया गया है। हर जिले में महिला थाने के अलावा एक अन्य थाने में महिला एसएचओ की तैनाती की गई है। यूपी ने महिला अपराधों में पहला स्थान हासिल किया है।

ऐसे अपराध न हों, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं:

- महिला पावर लाइन 1090, जी.आर. जे.पी., अग्निशमन सेवा, महिला हेल्पलाइन 181 सेवा का एकीकरण किया गया है।
- हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉयड का गठन।
- महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन 1090 का गठन। हर जिले में महिला थाने के अलावा एक अन्य थाने में महिला एसएचओ की तैनाती।
- महिला एवं बाल अपराध से जुड़े मामलों के निस्तारण में यूपी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है (99.42 प्रतिशत निस्तारण दर)।
- अभी 08 महिला पी.ए.सी. बटालियन हैं, पांच अन्य पी.सी. बटालियन के गठन की प्रक्रिया चल रही है।
- महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के 27,425 मामलों, पॉक्सो एक्ट के तहत 11,254 मामलों और दहेज हत्या के 3,775 मामलों में आरोपियों को सजा दिलाई गई।
- 2 लाख 16 हजार 450 पदों पर पुलिस कर्मियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है। 27,178 से अधिक महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करते हुए 10,378 से अधिक महिला बीट आवंटित की गई हैं।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए 346 महिला पीआईआरवी उपलब्ध हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति 50, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन नष्ट, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन इंगल, ऑपरेशन रक्षा आदि विभिन्न अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।
- 346 महिला पीआरबी की निरंतर उपलब्धता बनी हुई है। महिला रात्रि

कमीश्नरेट प्रणाली वाले शहर

- लखनऊ
- गौतम बुद्ध नगर
- कानपुर नगर
- वाराणसी
- आगरा
- गाजियाबाद
- प्रयागराज

एस्कॉर्ट सुरक्षा के अंतर्गत 3,237 महिलाओं को रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य किसी भी सुनसान स्थान से किसी महिला द्वारा कॉल किए जाने पर पीआरवी द्वारा उनके गंतव्य तक एस्कॉर्ट की सुविधा प्रदान की गई।

- व्यवहार कुशलता एवं तकनीकी कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से 2,15,498 (पीआरवी कार्मिक, संचार अधिकारी एवं अन्य) का प्रशिक्षण हुआ है।
- महिलाओं के साथ-साथ बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगजनों को प्रदेश एवं जनपद गौतमबुद्ध नगर के 17 नगर निगमों में सम्मिलित कर उन्हें सुरक्षित, संरक्षित एवं सशक्त वातावरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही चल रही है।
- सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं, बालिकाओं, बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांगजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से उनकी निगरानी की जा रही है। 1090 का यूपी 112 के साथ एकीकरण, 1090 कॉल सेंटर में 80 नार टर्मिनल की स्थापना, डाटा एनालिटिक्स सेंटर एवं साइबर सेल की सुविधा का प्रावधान।
- 100 पिंक पुलिस बूथ का निर्माण। आशा ज्योति केंद्र परियोजना के अंतर्गत रेस्क्यू वैन, प्रशासनिक वाहन एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था है।

डिजिटल माध्यम से अपराध कम करने का एक रोचक एवं सरल तरीका सामने आया है। राज्य पुलिस के लिए नई तकनीक विकसित करने में होने वाले अनुसंधान एवं विकास ने एक क्रांति ला दी है। अपराध से संबंधित आंकड़ों को संधारित करने में अत्यधिक आसानी हुई है। साथ ही नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, सीसीटीएनएस योजना के तहत यूपीसीओपी ऐप विकसित किया गया है।

ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण सहित 27 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रहरी बीट पुलिसिंग ऐप विकसित किया गया है और इसे सीसीटीएनएस के साथ एकीकृत किया गया है। प्रभावी रूप से, पुलिस अब मोबाइल स्क्रीन टच की दूरी पर है। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर सीसीटीएनएस मॉड्यूल के तहत ऑनलाइन सीसीटीएनएस वेब प्रशिक्षण पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

सीसीटीएनएस के माध्यम से अपराधियों का विवरण खोजने की एक स्वचालित प्रणाली है। क्राइम एनालिटिक्स, क्राइम डेटा पोर्टल, महत्वपूर्ण अपराध निगरानी पोर्टल, फील्ड यूनिट पोर्टल और जांच, पुलिस परेड पोर्टल विकसित किए गए

हैं। जांच अधिकारी ऐप (आईओ ऐप) विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। समय-समय पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधुनिकीकरण के महत्व का उल्लेख किया है।

यह कुछ ऐसा है जो विभिन्न सरकारी विभागों में लागू किया जा रहा है हाईटेक अप्रोच और हाईटेक समाधान है। निजी सुरक्षा एजेंसियों का ऑनलाइन लाइसेंस/नवीनीकरण और निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसएआरए पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन राजस्व संग्रह है। वर्तमान में यूपी-112 4800 पीआरवी वाहनों का संचालन कर रहा है और औसतन 30,000 कॉल करने वालों को रोजाना आपातकालीन सहायता प्रदान कर रहा है, जबकि पहले यह आंकड़ा 18,500 था। पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर 6,278 पीआरवी पर तैनात कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। दुनिया भर की सुरक्षा प्रणालियों से संपर्क करने के बाद ऐसी तकनीकों को लागू किया गया है। सरकार का हमेशा से ही चीजों के प्रति मौलिक दृष्टिकोण रहा है। सीएम का मानना है कि एक बार नींव मजबूत कर दी जाए तो परिणामी ढांचा आने वाले वर्षों तक आकार लेगा। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण क्षमता को दोगुना कर दिया गया है।

यूपी पुलिस में हो रही नियुक्तियों के मद्देनजर प्रशिक्षण क्षमता अब दोगुनी हो गई है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुल्तानपुर, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जालौन की स्थापना की गई है। शहीद गुलाब सिंह लोधी, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर और डॉ. भीम राव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद की क्षमता दोगुनी करने की प्रक्रिया चल रही है।

कई मायनों में यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स एक महत्वपूर्ण संगठन है। फिलहाल एसटीएफ के रडार पर आना सीधे जेल जाने का टिकट है।

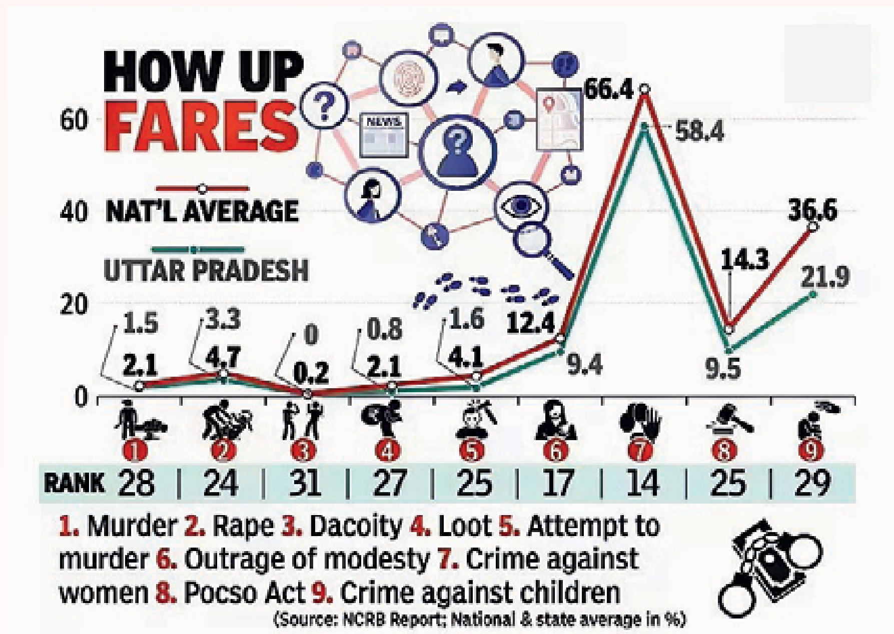

यूपी स्पेशल टास्क फोर्स का तकनीकी उन्नयन किया गया और स्विच-आधारित इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, मिनी साइबर लैब और ऑडियो/वीडियो आधारित विश्लेषणात्मक प्रणाली का उपयोग करके संगठित अपराध और माफिया तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

सड़कों पर चलते हुए, कोई भी आम आदमी यह जानकर राहत महसूस कर सकता है कि राज्य में कोई भी माफिया उसे परेशान नहीं कर सकता। पुलिस ने ऐसा डर पैदा कर दिया है कि गिरोह या संगठित अपराध से जुड़े अधिकांश अपराधी खुद ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं या अपनी गतिविधियाँ बंद कर रहे हैं।

अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, "हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है और मेरी सरकार हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। और मैं फिर से दोहराता हूं, अगर माफिया ने अपना सिर उठाने की हिम्मत की, तो सरकार उसे नष्ट कर देगी।" डकैत प्रभावित क्षेत्रों को डकैत मुक्त बना दिया गया है और संगठित माफिया गिरोहों का सफाया हो गया है। फिरौती और दबाव के लिए अपराधी परिवारों द्वारा किए जाने वाले अपहरणों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। प्रभावी निगरानी के माध्यम से, अपहरण करने वाले

सेल फोन की ट्रैकिंग अपराधियों के लिए अधिक से अधिक कठिन होती जा रही है। खानाबदोश बावरिया आपराधिक गिरोहों का भी सफाया हो रहा है। अवैध हथियार, नशीले पदार्थ, अवैध शराब, वन्यजीव तस्कर और नकली मुद्रा की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान पुलिस के प्रयासों को संक्षेप में प्रस्तुत करना लगभग असंभव है, लेकिन कुछ आंकड़े हमें आधुनिक पुलिसिंग की प्रभावशीलता की एक झलक देते हैं। सरकार ने हमारे सुरक्षा बलों को आवश्यक संसाधन और वातावरण प्रदान करके उनका भरपूर समर्थन किया है। बदले में उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित सड़कें और सुरक्षित घर दिए गए हैं।

- मार्च 2017 से जनवरी 2025 तक एसटीएफ ने 6,987 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 57 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए।
- 964 इनामी अपराधी गिरफ्तार, 423 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1139 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1337.05 करोड़ का ड्रग बरामद।
- 215 अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार, 2253 हथियार बरामद, 559 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार, 94.27 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 599 जघन्य अपराधों को होने से पहले ही रोकने में सफलता मिली।
- विभिन्न परीक्षाओं के दौरान 217 मुकदमे दर्ज किए गए। कुल 733 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए।
- अमर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम लागू किया गया। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों, पेपर लीक करने वालों और सॉल्वर गैंग के सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

कभी-कभी समाज को हर तरफ से खतरा होता है। आतंकवाद निरोधक दस्ते के बुनियादी ढांचे को उन्नत करते हुए गाजियाबाद, अयोध्या, लखनऊ में स्पॉट बनाए गए और 18 फील्ड यूनिट और 11 ऑपरेशन टीमें स्थापित की गईं। एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक, हथियार, साइबर विशेषज्ञ, आधुनिक सॉफ्टवेयर, ऐप टूल, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और नवीनतम सॉफ्टवेयर से लैस किया गया। जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों की पहचान करने में एटीएस सक्रिय रही है। गिरफ्तारी के आदेश से आगे बढ़कर, एटीएस प्रभावी सबूत और सामग्री जुटाने में सक्षम रही है, जिससे अदालतों का काम आसान हो गया है और सटीक सजा भी मिली है।

सच्चा नेता वह होता है जो बाहर की सड़कों पर ध्यान देने से पहले घर के आस-पास के बुरे तत्वों को खत्म करना शुरू कर देता है। यह सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछली सरकारों ने पैसे की अपनी अतृप्त भूख को पूरा करने के लिए राज्य को नए निचले स्तर पर धकेल दिया और इस तरह एक बेईमान और भ्रष्ट ढांचा तैयार किया। सरकार भ्रष्टाचार के मूल विचार के पीछे पड़ गई है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की संचालित इकाइयों के अतिरिक्त आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, बांदा, देवीपाटन, गोंडा, मिर्जापुर, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं प्रयागराज में परिक्षेत्रीय स्तर पर 8 नई इकाइयां स्थापित की गई हैं।

वर्ष 2017 से जनवरी 2025 तक 85 लोक सेवकों को माननीय न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया। एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां जनता के हित सर्वोच्च स्तर पर हों, वहां कोई भी अधिकारी उत्पीड़न से ऊपर नहीं है।

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 18 परिक्षेत्रीय साइबर अपराध थानों की स्थापना की गई है। साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में उन्नत साइबर फौरेंसिक लैब, 18 परिक्षेत्रीय थानों में बेसिक साइबर फौरेंसिक लैब तथा 57 जिला साइबर अपराध थानों की स्थापना की प्रक्रियाधीन है। आधुनिक युग में अपराध नए रूप में विकसित हो गए हैं। स्पैम कॉल से लेकर फिशिंग पेजों तक अपराध की एक नई दुनिया हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई है।

आधुनिक दौर में अपराधों के रूप भी बदल गए हैं। स्पैम कॉल्स से लेकर फ़िशिंग पेज तक, अपराध की एक नई दुनिया हमारे दरवाज़े तक आ चुकी है और हमें इसका

डटकर मुकाबला करना है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था साइबर अपराधों से निपटने के लिए लगातार एक कदम आगे रहकर काम कर रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर सेल को सक्रिय किया गया है। जिला स्तर पर संचालित साइबर सेल का विस्तार थाने स्तर तक किया गया है। वर्तमान में 75 मानव तस्करी निरोधक इकाइयों को घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए थानों में परिवर्तित कर दिया गया है।

कुल 1,09,437 धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाए गए और 1,65,515 लाउडस्पीकरों की आवाज निर्धारित मानक के अनुरूप न पाए जाने पर कम कर दी गई। कोई भी जाँच संभव नहीं होती यदि उससे जुड़े साक्ष्य ठीक से प्रलेखित न हों। इसी उद्देश्य से लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोंडा और मुरादाबाद में फौरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं संचालित हो रही हैं और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना पर कार्य जारी है।

यूपी पुलिस की मॉनिटरिंग देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। माफिया और अपराधियों के लिए कैमरों की निगरानी से बच पाना लगभग असंभव हो गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत 11,30,510 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनके माध्यम से हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, पिकपॉकेटिंग आदि से जुड़े 5,718 अपराधों का खुलासा हुआ और कानूनी कार्रवाई की गई।

विशेषज्ञ बताते हैं कि 2016 की तुलना में हर साल अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। उदाहरण

के तौर पर डकैती में 84.41%, लूट में 77.43%, हत्या में 41.01%, दंगे की घटनाओं में 66.40%, फिरौती के लिए अपहरण में 54.72%, दहेज हत्या में 17.08% और बलात्कार की घटनाओं में 26.15% की कमी दर्ज की गई है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक 51 आरोपियों को फांसी की सजा, 6,287 को आजीवन कारावास, 1,091 को 20 साल से अधिक की सजा, 3,868 को 10 से 19 साल की सजा और 5,788 को 5 साल से कम की सजा दी गई। पहचान किए गए माफिया गैंग्स और संगठित अपराधियों के मामलों में प्रभावी पैरवी से 31 माफियाओं और 14 संगठित अपराधियों को आजीवन कारावास तथा 2 को फांसी की सजा दी गई।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य फौरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। 2017 से अब तक एसटीएफ ने 653 से अधिक जघन्य अपराधों को घटित होने से पहले ही रोक लिया है। एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों और 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। नई संशोधित जेल मैनुअल 2022 लागू की गई है। कैदियों की रिमांड की कार्यवाही राज्य की 74 जेलों और जिला न्यायालयों में संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयों के माध्यम से की जा रही है। जेलों की सुरक्षा के लिए 4800 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी फीड मुख्यालय में स्थापित वीडियो वॉल पर देखी जा सकती है। 24 जेलों में 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित किए गए हैं।

राजकीय महाविद्यालय पडियापार
जैसौली देवरिया (उ.प्र.)
काम दमदार, डबल इंजन सरकार

शिक्षा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
2.86 करोड़+ किसानों को
₹80,000 करोड़+ हस्तांतरित
समय पर वित्तीय मदद, फसल लहलहाई, खुशहाली घर आई
उत्तर प्रदेश
प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से
56 लाख+
आवासों का निर्माण
सुरक्षा, स्वामित्व तथा सम्मानित जीवन का उपहार
काम दमदार
डबल इंजन सरकार

शिक्षा में एक नया अध्याय

शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार

सुधारों, स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीक के उपयोग व स्कूलों के निर्माण, विस्तार और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश ने हर बच्चे तक शिक्षा को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एक वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, “शिक्षा को कभी बाधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा निवेश है।” यह कथन उस दूरदर्शी सोच और व्यापक दृष्टिकोण को प्रकट करता है, जिसके तहत सरकार ने सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री भली-भांति समझते हैं कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है, और वही पीढ़ी तब सशक्त बन सकती है जब उसके पास मजबूत और सुदृढ़ शैक्षिक नींव हो।

केंद्र सरकार की कई नीतियों ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रवेश दर बढ़े और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम हो। प्रधानमंत्री के इन विचारों को सही अर्थों में अमली जामा पहनाने का जिम्मा उठाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले आठ सालों में शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उपलब्धि दर्ज की है, इसमें कोई शक नहीं है पिछले आठ वर्षों में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ा है और आने वाले समय के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करने में एक अद्भुत बदलाव आया है।

सरकार का अनुमान है कि स्कूलों में राज्य की सकल नामांकन दर (जीईआर) वर्तमान 25.6% से बढ़कर 2035 तक 50 प्रतिशत हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में 1.93 करोड़ बच्चे परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

स्कूल चलो अभियान और शारदा (स्कूल हर दिन आएं) कार्यक्रम जैसे अभिनव प्रयासों से 40 लाख अतिरिक्त बच्चों का नामांकन हुआ है और स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

जब शिक्षा की बात आती है, तो यह केवल बच्चे को स्कूल भेजने तक ही सीमित नहीं है। बच्चे और उसके माता-पिता को शिक्षा जारी रखने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षा बीच में न छूटे। सरकार न केवल बच्चों को स्कूल लाने में सफल रही है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण उपायों के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया है कि वे स्कूल में बने रहें।

शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 7.77 लाख बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश दिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 10784 बच्चे अध्ययनरत थे और पिछले 8 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 4 लाख 58 हजार से अधिक हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-

25 तक गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों को 728 करोड़ रुपये से अधिक की शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।

स्कूल किट केवल किताबें और कलम तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक संपूर्ण साजो-सामान है जिसकी एक बच्चे को दैनिक स्कूली शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। राज्य सरकार वर्ष 2021-22 से छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते, मोजे प्रदान करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कर रही है।

वास्तविक अर्थों में, इस तरह के प्रयास सरकार की इसी सोच को दर्शाते हैं। नीति निर्माताओं ने बच्चे के भविष्य के हर छोटे से छोटे पहलू के बारे में सोचा है।

आने वाले वर्षों में, स्कूल के बुनियादी ढांचे के कई पहलू अप्रचलित हो जाएंगे। अगली बड़ी पहल, जो पहले से ही लागू है, कक्षाओं का डिजिटलीकरण है। प्रोजेक्टर से लेकर स्क्रीन तक, कई ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए कक्षाओं को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है।

25,784 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 5588 आईसीटी लैब और 2 लाख 61 हजार से ज्यादा टैबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करके डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2,10,000 शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कमजोर वर्ग की लड़कियों को कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करके 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन किया है।

गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन शुरू हो गया है।

प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों को उन्नत कर

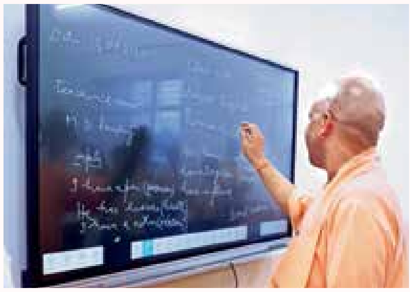

उन्हें ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, असेवित क्षेत्रों में 39 नए हाई स्कूल और 14 नए इंटर कॉलेज बनाए गए हैं।

हिंदी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 18,381 परिषदीय उच्च प्राथमिक कम्पोजिट और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और 880 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं।

2017 से पहले प्रदेश के 93 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित थे, जिन्हें वर्तमान में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया गया है। वर्तमान में 120 विद्यालय संचालित हैं।

पूर्व-प्राथमिक और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 377 परिषदीय विद्यालयों को मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है।

वर्तमान विद्यालय भवनों और सुविधाओं का उन्नयन समय पर किया जाना आवश्यक है। पूर्व की सरकारें रखरखाव की भी परवाह नहीं करती थीं। किसी स्कूल या कॉलेज का शिलान्यास होने पर राजनीतिक फोटो खिंचवाने का मौका मिलता था।

वनटांगिया गांवों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से गोरखपुर और महाराजगंज में 22 प्राथमिक और 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। महराजगंज के शेष 3 वनटांगिया ग्रामों तथा गोण्डा के 2 वनटांगिया ग्रामों में विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार ने 07 नए केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भूमि की व्यवस्था कर दी है।

शिक्षा में क्रांति लाने के अनेक नवीन उपायों के अंतर्गत, सरकार ने विद्यालयों के मानचित्रण हेतु 'पहुँच ', करियर परामर्श हेतु 'पंख', पुस्तकालय हेतु 'प्रज्ञान', निगरानी हेतु 'परख', कौशल प्रशिक्षण हेतु 'प्रवीण', विद्यालयों हेतु 'पहचान', पहचान एवं संसाधन मैपिंग हेतु 'प्रोजेक्ट अलंकार पोर्टल' का विकास करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। पीएम

ई-विद्या चैनल और दीक्षा पोर्टल पर विषयवार वृत्तचित्र वीडियो तथा परिषद की वेबसाइट पर ई-पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं।

सरकार ने पांच नए आवासीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। आज विश्व संस्कृत के महत्व की चर्चा कर रहा है और यह सराहनीय है कि बच्चे संस्कृत का अध्ययन कर उससे जुड़ पा रहे हैं।

इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा रोजगारोन्मुखी शिक्षा हेतु 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं और 18 नए संस्कृत महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है। राज्य में 184 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों के लिए प्रशिक्षण भी संचालित किया जा रहा है। 'राज्य अध्यापक' और 'मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार' के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। गोरखपुर जिले में राज्य के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना और संचालन हो रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, छात्रों को अंधेरे में रखने का एक सुनियोजित राजनीतिक प्रयास किया गया है। उनमें से कई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच

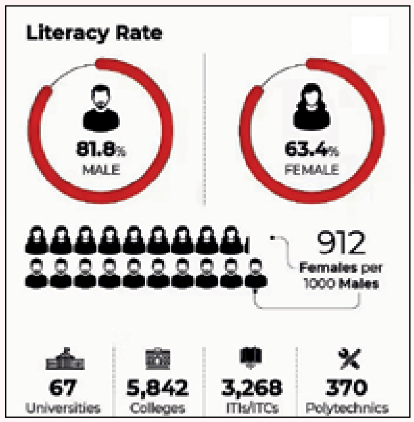

पाने में असमर्थ रहे और जो स्कूल में दाखिला लेने में कामयाब रहे, वे इस अवसर का पूरा लाभ नहीं उठा पाए। पढ़ाई के अनुकूल माहौल के साथ, अधिक से अधिक बच्चे राजकीय महाविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं और अमूल्य कर्मचारी साबित हो रहे हैं।

वर्तमान में, 22 राज्य विश्वविद्यालयों, 44 निजी विश्वविद्यालयों, 171 राजकीय महाविद्यालयों, 331 सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, 1 मानद और 1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा 7,372 स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों में 52.28 लाख छात्र अध्ययन कर रहे हैं। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर का शिलान्यास।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

15 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी किया गया है, साथ ही 8 अन्य निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में आशय पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी सहित प्रमुख संस्थानों को NAAC मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

गोरखपुर को भी NAAC मूल्यांकन में A ग्रेड प्राप्त हुआ है। सरकार ने संस्कृत शिक्षा निदेशालय परिसर में कंटेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना की है। 24 वर्षों के बाद संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि का निर्णय लिया गया है।

स्टार्ट अप नीति के अंतर्गत, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों और AKTU के संस्थानों में 15 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के क्रम में, कॉलेजों ने हिंदी में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करना शुरू कर दिया है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए युग के पाठ्यक्रम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा और ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है।

सरकार ने सरकारी पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट वॉल और पूर्णतः डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है।

राज्य में साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और तारामंडल की स्थापना और जीर्णोद्धार के लिए एक अति आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। व्यापक अर्थ में, शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्यों और संस्कृति के संचरण के माध्यम से व्यक्ति के मन, शरीर और चरित्र के विकास की समग्र प्रक्रिया है। यह केवल औपचारिक कक्षा शिक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, साथियों, समुदायों और वैश्विक नेटवर्क के साथ बातचीत के माध्यम से प्राप्त आजीवन सीखने के अनुभव का भी हिस्सा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना हमारी शिक्षा प्रणाली के गौरव को बनाए रखना है और नवीनतम योजनाओं के साथ, यह प्रक्रिया शुरू हो गई है।

हेल्थकेयर

एक बड़ी जीत

इंसेफेलाइटिस पर लगा अंकुश

उत्तर प्रदेश ने इंसेफेलाइटिस जैसी भयावह बीमारी से निपटने के लिए अपनाए गए व्यावहारिक और ठोस कदमों के जरिए इस रोग पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर राज्य में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) और जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय जीत दर्ज की है। राज्य ने जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु के 96% मामलों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है और प्रशासन का इरादा 100% सफलता दर हासिल करने का है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) वैक्सीन अभियान की शुरुआत की और राज्य प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश इस बीमारी को जड़ से मिटाने के करीब खड़ा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बुनियादी और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अतिरिक्त समर्थन ने जेई के लिए जन जागरूकता अभियान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोरखपुर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पिछले वर्षों की तुलना में एईएस और जेई के मामलों में भारी गिरावट देखी गई।

गोरखपुर चार दशक से इंसेफेलाइटिस की चपेट में था। पूर्वी यूपी में हर साल इस बीमारी से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। 1978 के बाद से, लगभग 25,000 बच्चों की इंसेफेलाइटिस से मृत्यु हो गई, हालांकि, स्वतंत्र आंकड़ों ने 50,000 के आसपास का अंदाजा लगाया, क्योंकि कई बच्चे अस्पताल पहुंचे बिना ही मर जाते हैं। 2017 और 2018 के बीच 920 इंसेफेलाइटिस रोगियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

जापानी इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतें

25	2018	2019	21
9	2020	2021	5
4	2022	2023	3
2	2024	2025	0

संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए 'दस्तक' मिशन की शुरुआत एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) और जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) के खिलाफ की गई। इसके परिणामस्वरूप पूर्वांचल इंसेफेलाइटिस मुक्त हो गया और इस बीमारी से होने वाली मृत्यु दर में 96% तक नियंत्रण पाया गया।

मिशन 'दस्तक' और मिशन 'इंद्रधनुष'

2017 में राज्य प्रशासन ने एईएस और जेई पर बड़े पैमाने पर रोकथाम लगाने में सफलता पाई। इसके तुरंत बाद, उन्होंने 2018 में यूपी के कई जिलों में 'दस्तक' पहल शुरू की, जिसमें स्थानीय लोगों को दवाओं, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता के रखरखाव और उनके आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे बीमारियों से होने वाले नुकसान को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिली। जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम दोनों ही क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से होती है।

इसी तरह, मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण फरवरी 2021 में शुरू हुआ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 19 फरवरी, 2021 को देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए एक गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 को आगे बढ़ाया, जिसमें 2 राउंड शामिल हैं - पहला फरवरी 2021 में और दूसरा मार्च 2021 में। इसे देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पहले से पहचाने गए 250 जिलों और शहरी क्षेत्रों में तेज तरीके से चलाया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का फोकस उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर किया गया,जिनसे कोविड-19 महामारी के दौरान अपने टीके की खुराक लेने से चूक हुई।

सबके लिए उत्तम स्वास्थ्य

सुदृढ़ बुनियादी ढांचा

बार-बार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने "स्वस्थ भारत, सशक्त भारत" के विचार पर जोर दिया है। यही सोच राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी नई नीतियों की आधारशिला बनी है।

उत्तर प्रदेश लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दे रहा है। पिछले 8 वर्षों की बात करें तो कहना होगा कि इस दिशा में व्यापक सकारात्मक बदलाव आए हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं और इसका परिणाम यह है कि प्रदेश में नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही यूपी दूसरे राज्यों के लिए भी चिकित्सा का बेहतर गंतव्य बन गया है।

2017 से पहले, कई कमियां थीं। बंद पड़े मेडिकल कॉलेजों से लेकर अपर्याप्त चिकित्सा कवर तक, कई मुद्दे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को लगातार कमजोर बना रहे थे और इसकी मुख्य वजह राजनैतिक और प्रशासनिक अनदेखी थी। चिकित्सा संस्थानों तक पहुंच नागरिक के मूल अधिकारों में से एक माना जाता है। ऐसे में प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष पहल की और इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाए। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने कमियों की पहचान करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किए और उसके अनुसार नीतियां बनाई गईं।

2017 के बाद इस तरह बदला परिदृश्य

2017 से अब एमबीबीएस की सीटें तीन गुना हो गई हैं और 25000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में इतनी तेजी से वृद्धि केवल लोगों की बेहतरी के प्रति सरकार के समर्पण से ही संभव हो पाई है।

यह वही संरचित योजना थी जिसके परिणामस्वरूप कोविड संकट से कुशलता पूर्वक निपटा गया, जब अन्य देशों की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां ध्वस्त हो गईं। भविष्य के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की योजना के साथ, उत्तर प्रदेश

स्वास्थ्य देखभाल नीतियों की बात आने पर अनुकरणीय राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना है और भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है। राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान" नाम से एक ऐसी ही योजना शुरू की, जिसमें सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर छूटे हुए परिवार शामिल हैं।

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 5.21 करोड़ लाभार्थी कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- प्रदेश भर में कुल 9 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 49.23 लाख से अधिक परिवार कवर किए गए हैं।
- पिछले 9 वर्षों में, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2,37,125 जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए 3,280.95 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारक 40.79 ब्लॉक परिवार शामिल हैं।

- मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत यूपी भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लगभग 11.65 लाख परिवार और सूचना विभाग से मान्यता प्राप्त पत्रकार शामिल हैं।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में 5834 अस्पताल (2949 सरकारी, 2885 निजी) सूचीबद्ध हैं। अब तक 53 लाख 93 हजार लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
- मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में अब तक 13.50 करोड़ मरीजों का इलाज हुआ है।

पिछले आठ वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं, क्योंकि पहुंच अलग-थलग नहीं है, बल्कि उपकरणों से सहायता प्राप्त है। इस संबंध में एडवांस लाइफ सपोर्ट सर्विस की 250, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की 2270 तथा 108 सेवा के अंतर्गत 2200 एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं। पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाओं ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं सहित 13 करोड़ 26 लाख से अधिक मरीजों की सेवा की है।

पिछले आठ वर्षों में 108 एम्बुलेंस सेवा ने आपात स्थिति में 3.57 करोड़ (3,57,24,745) से अधिक लोगों की मदद की है। सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि औसत प्रतिक्रिया समय 2014 में 28.12 मिनट से घटकर 2025 में सिर्फ 7.25 मिनट रह गया है।

एएलएस एम्बुलेंस सेवा से 7.14 लाख (7,14,552) से अधिक गंभीर रोगियों को लाभ मिला है और हाल ही में मुख्यमंत्री ने बेड़े में 125 नई एएलएस एम्बुलेंस जोड़ी हैं। इसके प्रतिक्रिया समय में भी बड़ी प्रगति हुई है, जो 2014 में 30 मिनट से बढ़कर 2025 तक 6.31 मिनट हो गया है।

आभा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के अंतर्गत 13.18 करोड़ से

अधिक खाते बनाकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) एक अद्वितीय 14-अंकीय संख्या है जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के रूप में कार्य करती है।

हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के तहत 81,615 से अधिक रजिस्ट्री दर्ज करके उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। राज्य में कुल 63,407 स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री दर्ज करके भी राज्य देश में पहले स्थान पर है। आभा आधारित ओपीडी पंजीकरण उत्तर प्रदेश 1.31 करोड़ से अधिक ओपीडी पंजीकृत करके देश में पहले स्थान पर है। फिलहाल, 5.76 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए गए हैं। 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत, देश में सबसे अधिक 35 माइक्रोसाइट संचालित करके राज्य में 4.4 लाख से अधिक रिकॉर्ड दर्ज करके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।

राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम

एक चिकित्सा चमत्कार राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किया गया। हर महीने की 15 तारीख को टीबी, कालाजार, फाइलेरिया और कुष्ठ रोग के लिए सभी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर 'एकीकृत निक्षय दिवस' मनाया जा रहा है।

- टीबी की त्वरित एवं सुविधाजनक जांच के लिए प्रदेश भर में 926 एनएटी मशीनें उपलब्ध
- प्रदेश में 8 नई टीबी कल्चर लैब स्थापित, वर्तमान में प्रदेश में 14 टीवी कल्चर लैब क्रियाशील
- क्षय रोग पोषण योजना - 01 नवंबर 2024 से योजना के तहत मरीजों को दी जाने वाली राशि में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि
- अब तक करीब 28.27 लाख टीबी मरीजों के खातों में करीब 818 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं
- वर्ष 2024 में 6.81 लाख टीबी मरीजों की पहचान एवं उपचार -

देश में सर्वाधिक है

- वर्तमान में प्रदेश में 50 हजार निक्षय मित्रों द्वारा 3.46 लाख मरीजों को 3.17 लाख पोषण किट वितरित किए जा चुके हैं

फाइलेरिया नियंत्रण

पिछले कुछ वर्षों में, कई सफल एमडीए अभियान चलाए गए हैं और वर्तमान में, राज्य के 41 जिले इस योजना के अंतर्गत आते हैं। 361 विकासखंड फाइलेरिया से प्रभावित हैं।

फरवरी 2025 में, राज्य के 14 जिलों के 45 प्रखंडों में 91 प्रतिशत कवरेज के साथ एमडीए अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

डेंगू नियंत्रण

29 जिलों में 36 प्रयोगशालाओं के मुकाबले जांच सुविधाओं का विस्तार हुआ है, राज्य के सभी 75 जिलों में 86 प्रयोगशालाएं और 3 शीर्ष प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं

मृत्यु दरः मृत्यु दर में 93 प्रतिशत की कमी (2017 में 0.91 प्रतिशत से 2024 में 0.06 प्रतिशत तक, जैसा कि लक्ष्य था)। यह अभूतपूर्व सुधार है।

मलेरिया नियंत्रण

मलेरिया के कुल मामलों में पिछले आठ वर्षों में 58 प्रतिशत की कमी आई है। परीक्षण सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मलेरिया परीक्षणों की संख्या में 210 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ABER में 218 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (वादे के अनुसार 2.01 प्रतिशत से 6.12 प्रतिशत)। वर्ष 2017 से सरकार ने शून्य मृत्यु दर को बनाए रखा है।

चिकित्सा शिक्षा

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक नया अध्याय लिख रहा है। चिकित्सा सीटों का विस्तार हुआ है, नए कॉलेज खोले गए हैं और अधिक उन्नत चिकित्सा भविष्य की तैयारी के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया गया है।

यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है - यह समर्पित डॉक्टरों, नर्सों और विशेषज्ञों की एक पीढ़ी को पोषित करने के बारे में है जो यूपी के हर कोने की सेवा करेंगे। यह एक ऐसे भविष्य के लिए बीज बोने के बारे में है जहां कोई भी मरीज बिना इलाज के न रहे और हर क्षेत्र में एक गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर हो।

सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वास्थ्य सेवा मॉडल जीवन बचा रहा है, करियर बना रहा है और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहा है।

- 44 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 36 निजी मेडिकल कॉलेज सहित 30 मेडिकल कॉलेज चालू हैं।
- बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, औरैया, चंदौली, गोंडा, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी जिलों के स्वायत्त मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण शुरू हो गया है। साथ ही महाराजगंज, शामली और संभल के मेडिकल कॉलेजों में भी पीपीपी मोड के तहत शिक्षण शुरू हो गया है।
- 16 असेवित जिलों में मेडिकल

कॉलेजों की स्थापना के लिए पीपीपी मोड नीति।

- लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और गोरखपुर और रायबरेली में एम्स संचालित हैं।
- वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 5250 और निजी क्षेत्र में 6550 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से 2500 नई एंबुलेंस खरीदने का ऑर्डर दिया है। यकीनन यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एंबुलेंस खरीद का रिकॉर्ड बल्क ऑर्डर था। यह फैसला राज्य की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

पीपीपी मोड के तहत तीन नए मेडिकल कॉलेजों में 350 सीटें उपलब्ध हैं।

- प्रदेश में स्वीकृत 31 नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
- एसजीपीजीआई में एक मधुमेह केंद्र की स्थापना की गई है, इसके साथ ही 500 बेड वाले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- एसजीपीजीआई में ही 8 नए विभाग शुरू किए गए हैं। आईआईटी कानपुर के अंतर्गत 500 बेड वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है।
- सरकारी क्षेत्र में एमडी/एमएस/डिप्लोमा सीटों की संख्या 900 से बढ़कर 1871 हो गई है। निजी क्षेत्र में कुल पीजी सीटें 2100 हैं।
- वर्तमान में कुल 305 सुपर स्पेशियलिटी सीटें उपलब्ध हैं।
- कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में कैंसर के लिए उन्नत आणविक निदान और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई।
- सरकार मिशन निरामया के तहत नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। मेंटर मेंटी मॉडल का क्रियान्वयन।
- नर्सिंग में 7000 और पैरामेडिकल में 2000 सीटों की वृद्धि हुई है।
- 35 से अधिक बंद पड़े एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से शुरू किया गया।

वर्तमान में यूपी में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और

1585 होम्योपैथिक अस्पताल, 08 आयुर्वेदिक कॉलेज और उनसे संबद्ध अस्पताल, 02 यूनानी कॉलेज और उनसे संबद्ध अस्पताल और 09 होम्योपैथिक कॉलेज और उनसे संबद्ध अस्पताल हैं।

राज्य में 80 मेडिकल कॉलेज, 44 सरकारी और 36 निजी, संचालित होने के अलावा पिछले आठ वर्षों में सरकारी और निजी अस्पतालों के बढ़ते नेटवर्क ने उत्तर प्रदेश को चिकित्सा केंद्र में एक बहुत ही विशिष्ट स्थान पर पहुंचा दिया है।

2017 से पहले, यूपी को खराब स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के लिए भारत के बीमारू (बिहार, एमपी, राजस्थान और यूपी) राज्यों के रूप में माना जाता था। हालांकि, उत्तर प्रदेश ने इतिहास की गलतियों को सुधारा और एक नया भविष्य लिखा।

इस साल मई में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य भर में अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए नई स्वास्थ्य नीति शुरू करेगी। नई नीति के तहत नगर निगमों और 57 जिला मुख्यालयों में 200 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे।

नई आगामी नीति को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों का खाका माना जाएगा। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सरकार का लक्ष्य न केवल शहरी केंद्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट, आपातकालीन सेवाओं की सुदृढ़ता, नई स्वास्थ्य नीतियों का क्रियान्वयन और डिजिटल हेल्थ सुविधाओं का विस्तार ये सब आठ वर्षों की बड़ी उपलब्धियां हैं। इन प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, किफायती और आधुनिक हुई हैं, जिससे प्रदेश एक स्वस्थ और सशक्त समाज की ओर अग्रसर है।

पहले उत्तर प्रदेश के निवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पहले देश के दूसरे राज्यों की यात्रा करते थे, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने यूपी को उत्तम स्वास्थ्य का केंद्र बना दिया है। यूपी अब निवासियों की जरूरतों को पूरा करते हुए चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन गया है।

ऊर्जा

जगमगाता उत्तर प्रदेश

ऊर्जा और विद्युतीकरण

विभिन्न ऊर्जा पहलों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन और संरक्षण क्षमता कई गुना बढ़ी है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक अधिक और बेहतर दक्षता के साथ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित हुई है।

बिजली आपूर्ति के मामले में जिस सरकार के पास उचित संसाधन प्रबंधन होता है, वह भविष्य की बेहतर देखभाल कर पाती है। जब आप किसी घर में रोशनी करते हैं, तो आप केवल वर्तमान को रोशन नहीं करते हैं, बल्कि आने वाली रोशनी के लिए सुरक्षित भविष्य का मार्ग संवारते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की चिंता करना अब पुरानी बात हो गई है।

सबसे लंबे समय तक, राज्य ने सही अर्थों में एक अंधकारमय युग देखा। खराब नियोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण राज्यके अधिकांश क्षेत्र बिजली रहित रहे। 2017 में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री ने विकास के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को फिर से परिभाषित करने का वादा किया।

8 साल में सरकार अपने लक्ष्य से आगे निकल गई। वर्ष 2024-2025 में दिसंबर तक औसत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे 36 मिनट और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे थी।

जहां वर्ष 2017 तक कुल 1,28,494 गांव में बिजली उपलब्ध थी वहीं दिसंबर 2023 तक 2,94,818 गांव तक बिजली पहुंचा दी गई थी। वर्ष 2012-17 की अवधि में करीब 8.44 लाख बिजली कनेक्शन की तुलना में वर्ष 2017 से अब तक 165 लाख बिजली कनेक्शन जारी किये गये हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली वितरण के बारे में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में यूपी ने 'सबको बिजली-निर्बाध बिजली' का लक्ष्य हासिल किया है। अब यूपी के हर गांव और मजरे में बिजली पहुंच रही है, जिससे बिना किसी भेदभाव के समान रूप से वितरित किया जा रहा है।

आंकड़ों में वृद्धि से पता चलता है कि बिजली और आपूर्ति से संबंधित सरकारी कार्यों के हर स्तर को पुनर्गठित किया गया है। किसी भी तरह की कोई गलती न हो, इसके लिए नए निर्देश जारी किए गए। बिजली वितरण में समस्याओं की पहचान करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। ग्रामीण परिवारों को बिजली आपूर्ति के संकट से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में अब तक 33/11

केवी के 749 नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना हो चुकी है और 1528 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि हुई है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि बिजली आपूर्ति जादू की छड़ी घुमाना नहीं है। वास्तव में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन से लेकर वितरण तक पूरी बिजली व्यवस्था का विस्तार और सुधार करना जरूरी है। इसमें नए बिजली संयंत्रों के निर्माण, स्थिर आपूर्ति तंत्र को बेहतर बनाने के लिए उन्नत करना और नए उद्योगों को लागू करना शामिल है। यह कहना सही होगा कि इस दिशा में यूपी ने पिछले 8 वर्षों में मील का पत्थर स्थापित किया है।

अ‍ाज के दौर में प्रदेश सोलर सिटी की बात कर रहा है और इसे धरातल पर उतार भी रहा है। अयोध्या के अलावा सोलर सिटी और सोलर एक्सप्रेस-वे को भी आपूर्ति सुधार के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा, प्रदेश के 16 नगर निगमों और शहरों को भी सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से ऊर्जा की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सौर ऊर्जा संसाधनों को अपनाना, सार्वजनिक परिवहन में सौर ऊर्जा की पहुंच को बढ़ावा देना शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने दिसंबर 2024-2025 तक 7140 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता और संयुक्त उद्यम में 1980 विद्युत ताप विद्युत उत्पादन क्षमता और 37,056 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किया है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि सरकार का मुख्य फोकस है। इससे राज्य की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी और दीर्घकालिक ऊर्जा लक्ष्य की पहल होगी। सरकार ने पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना को बढ़ावा देने के लिए अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में जनपद जालौन में 500 सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार के एक अन्य उद्यम में सरकार तहसील गरौठा, जिले में 200 इकाइयों का सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है।

विद्युत निगम ने 2x800 पावर प्लांट ओबरा डी ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। कानपुर में 3X660 पंपों की घाटमपुर तापीय परियोजना की पहली इकाई पूरी हो चुकी है और दूसरी और तीसरी इकाई का उत्पादन जल्द शुरू।

भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा '24x7 पावर

फॉर ऑल' (एफएफई) कार्यक्रम लागू किया गया है जिसका उद्देश्य सभी असंबद्ध घरों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करना है, ताकि सभी घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रमिकों को एक निश्चित समय सीमा के साथ 24x7 गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

इस व्यवस्था के तहत कृषि उद्यमियों को भी लागत प्रभावी तरीके से आवश्यकतानुसार आपूर्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री विद्युत क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता और गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। सभी बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2017 से 24,800 करोड़ रुपये की लागत से 193 विद्युत उप-केंद्रों और संबंधित उपकरणों को सक्रिय किया गया है। 1000 से अधिक आबादी वाले 19031 गांवों/बस्तियों में खुले तारों के स्थान पर 51941 किलोमीटर से अधिक एबी केबल लगाई गई। स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 'पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना' लागू की गई है। यह देखा गया कि अक्सर कुछ घरों के लिए आरक्षित बिजली अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती थी।

मीटर प्रणाली के पुनरुद्धार से गड़बड़ी खत्म हो गई और आम लोगों के बजाय केवल कुछ वीआईपी क्षेत्रों को ही बिजली मिल पा रही थी। सरकार ने 33/11 केवी बिजली सबस्टेशनों पर 627 कैपेसिटर बैंक लगाए हैं। डार्क जोन में निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगी रोक हटने से 1 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 14 लाख से अधिक निजी नलकूपों के बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे के भीतर बदलने की व्यवस्था भी है। यह किसानों और ग्रामीण आजीविका से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। 09 हजार 926 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाने तथा 28 हजार 602 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पूरा हो चुका है। किसानों के हित में 1 लाख 88 हजार निजी नलकूपों को जोड़ा गया।

सिंचाई सुविधा के लिए 3,99,899 निजी नलकूपों को जोड़ा गया है। किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए लगभग 2695 ग्रामीण फीडरों को अलग किया गया। समग्र विकास को देखने वाली सरकार किसानों का विकास जमीनी स्तर से शुरू करती है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और विशेष रूप से सिंचाई के लिए सुचारू और परेशानी मुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने से उन्हें नया जीवन मिला है।

रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए वर्ष 2025-26 में 3000 सूर्यमित्रों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक कुल 1,87,873 निजी नलकूप कनेक्शन जारी किए गए।

कृषि फीडरों के पृथक्करण की योजना के तहत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष

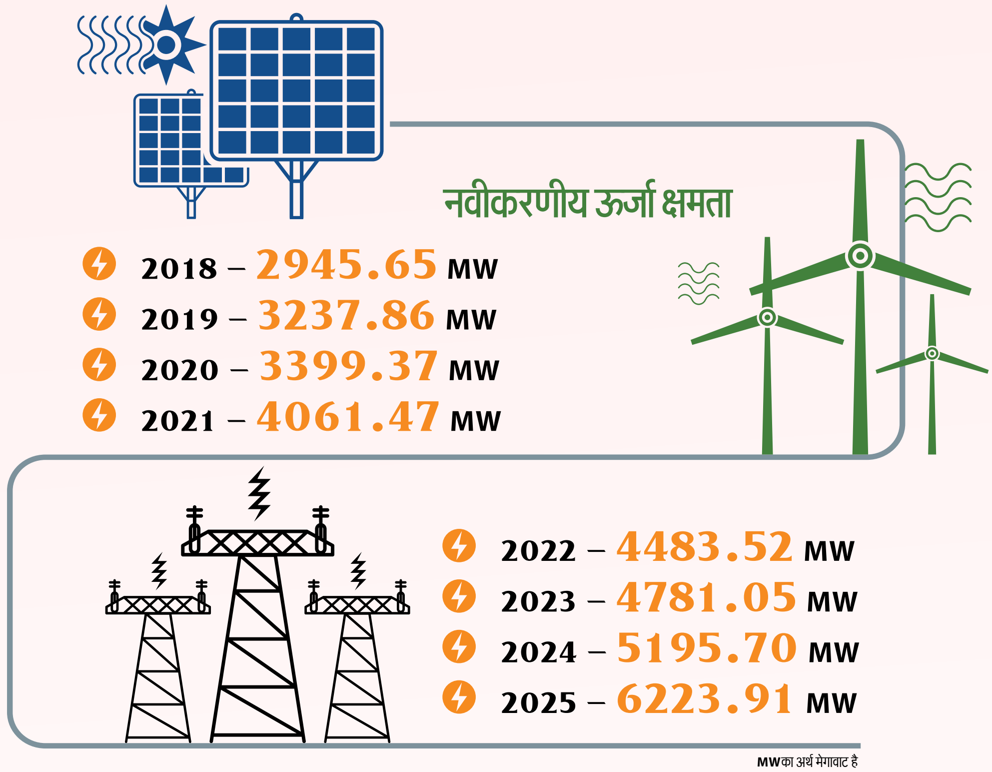

उत्तर प्रदेश में किसानों को सुचारू विद्युत आपूर्ति की सुविधा मिल रही है। 33/11 केवी सबस्टेशनों पर कैपेसिटर बैंक लगाए गए, निजी नलकूपों में छूट दी गई और ट्रांसफार्मरों की संख्या व क्षमता बढ़ाई गई। इससे सिंचाई सुविधा और ग्रामीण विकास को मजबूती मिली है।

3,817 कृषि फीडरों का निर्माण किया गया है। सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत 22000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। निजी पूंजी निवेश से 2653 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं और 508 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है।

वर्ष 2017 तक कुल 288 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित थीं, जो पिछले 8 वर्षों में 10 गुना बढ़ गई हैं। सरकार के डबल इंजन विकास मॉडल ने वर्तमान को बढ़ाते हुए भविष्य की ओर देखने की अनुमति दी है। सौर ऊर्जा भविष्य है और इसे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सरकार ने 2025-26 तक 2.65 लाख यूनिट तथा 2026-27 तक 8 लाख यूनिट रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट तथा जालौन में सोलर पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है। सौभाग्य योजना के तहत 53,354 से अधिक सोलर पावर पैक प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।

सरकार ने कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट, बायो कोल, बायो डीजल/बायो इथेनॉल की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए हैं।

गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन के लिए 'झटपट पोर्टल' भी है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत कंप्रेस्ड बायो-गैस, बायो-कोल, बायो-डीजल/बायो-इथेनॉल से संबंधित 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल के कार्यकाल में आम जनता की बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया, टिकाऊ भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए और रिकॉर्ड समय में उन्हें हासिल किया गया।

रोशन होता उत्तर प्रदेश

- उत्तर प्रदेश 24 घंटे विद्युत अपूर्ति कराने वाला प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो रहा है। शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह वास्तविकता की शक्ल ले रहा है।
- 2017-18 से अब तक 1,21,324 'माजरा' विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन और अन्य ग्रामीण परिवारों को 10 मासिक किश्तों में 50 रुपये में कनेक्शन प्रदान किए गए। इस योजना के तहत 62.18 लाख इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए।
- 2016-17 में ट्रांसमिशन सिस्टम की कुल क्षमता 16,348 मेगावाट थी, जो 2022-23 में 28,900 मेगावाट तक बढ़ा दी गई। लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इसे 31,500 मेगावाट तक बढ़ाया जाए।
- भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-2 परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में 4000 मेगावाट क्षमता वाले सौर पार्क के विकास का लक्ष्य है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 33,556 मिलियन यूनिट थी, जो 2022-23 में बढ़कर 39,746 मिलियन यूनिट हो गई।
- गर्मियों में निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2000 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
- निजी नलकूप उपभोक्ताओं को किफायती दर पर बिजली आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
- उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी-2022 के तहत अगले पांच वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। 2017 में राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाएँ 288 मेगावाट थीं, जो अब लगभग 2600 मेगावाट हो गई हैं।
- अब तक राज्य में 328 मेगावाट सौर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
- अयोध्या और वाराणसी शहरों को मॉडल सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्ट्रीट लाइटिंग की सुविधा के लिए अब तक लगभग 3.35 लाख सौर स्ट्रीट लाइट प्लांट स्थापित किए गए हैं।
- पीएम कुसुम घटक C-1 के अंतर्गत निजी ऑन-ग्रिड पंपों के सौरिकरण के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है।
- उत्तर प्रदेश राज्य बायो-एनर्जी पॉलिसी-2022 को लागू करने के लिए 60 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।

राजस्व

बेहतर होती वित्तीय स्थिति

राज्य की जीडीपी और अर्थव्यवस्था

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसके लिए देश स्वर्णिम मार्ग अग्रसर है। प्रधानमंत्री का विजन साकार हुआ है और उत्तर प्रदेश वित्तीय क्षेत्र में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने की राह पर है।

देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने को प्राथमिकता दी। बेहतर आर्थिक हालात का असर शासन के हर क्षेत्र पर सकारात्मक रूप से दिखता है। आय बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, उत्पादन और रोजगार में इजाफा होता है और समग्र प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।

सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में शामिल है। राज्य अब उस दौर से निकल चुका है जब भ्रष्टाचार और कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति ने विकास की रफ्तार रोक दी थी। सरकार का एकमात्र लक्ष्य विकास है, जिसे मुख्यमंत्री लगातार पूरा कर रहे हैं। राज्य सरकार की सोच सुरक्षा, विकास और सुशासन पर केंद्रित है, साथ ही वित्तीय अनुशासन भी बजट का अहम हिस्सा है। यही कारण है कि वित्तीय अनुशासन के साथ विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सका है।

भारत की जीडीपी में 9.2% हिस्सेदारी के साथ यूपी देश में दूसरे स्थान पर है।

वर्ष 2023-24 में जहां भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.6% रही, वहीं उत्तर प्रदेश ने 11.6% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 91,399.80 करोड़ रुपये है, जो राज्य की जीएसडीपी का 2.97% है और यह पूरी तरह FRBM की तय सीमा के भीतर है।

देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संसाधन होने के बावजूद, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 1950 से 2017 तक केवल 12.75 लाख करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाया था। पिछले आठ वर्षों में, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) दोगुने से भी अधिक होकर 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। 2025-26 में 30.77 लाख करोड़ रुपये का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का लक्ष्य रखा गया है। ये आँकड़े हमें एक दिलचस्प कहानी बताते हैं कि कैसे मजबूत मुख्यमंत्री राज्य की सूरत बदल सकते हैं और वर्षों की गलतियों को सुधार सकते हैं।

8 वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी

2018-19: ₹15.80 लाख करोड़

2019-20: ₹17.94 लाख करोड़

2020-21: ₹17.29 लाख करोड़
(कोविड के दौरान)

2021-22: ₹19.46 लाख करोड़

2022-23: ₹22.58 लाख करोड़

2023-24: ₹25.48 लाख करोड़

2024-25: ₹27.51 लाख करोड़
(अनुमानित)

2025-26: ₹30.80 लाख करोड़
(प्रस्तावित)

नीति आयोग की रिपोर्ट

- राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में, उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया था।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 से 2022-23 की अवधि में राज्य के समेकित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 8.9 अंकों की वृद्धि हुई है। इस अवधि में व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो कुल व्यय का 14.8 प्रतिशत और 19.3 प्रतिशत के बीच रहा।
- इस दौरान, यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा।
- राजस्व बचत और प्राथमिक बचत की वजह से जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य का कर्ज घटा है।

2024-25 में राज्यों के बजट पर आरबीआई की अध्ययन रिपोर्ट

- देश के सभी राज्यों की स्वयं की कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी वर्ष 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 में क्रमशः 9.9 प्रतिशत,10.5 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत रही। देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
- उक्त वर्षों में, सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 और 12.1 प्रतिशत था, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 और 8.91 था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गिरवी के रूप में सभी राज्यों की स्वयं की कर प्राप्तियों का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 और 7.2 था, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 और 10 प्रतिशत था।

राजस्व अधिशेष राज्य (रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश)

- उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति में है। कर चोरी पर रोक लगी है। राजस्व रिसाव समाप्त कर दिया गया है। डिजिटल व्यवस्था अपनाने से पारदर्शिता बढ़ी है। यह पूर्ण रूप से राज्य में बेहतर कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
- पिछले 8 वर्षों में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है। राज्य में डीजल और पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम हैं, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष वाले राज्य के रूप में समृद्धि की नई सीढ़ियां चढ़ते हुए नए प्रतिमान गढ़ रहा है।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य1,56,981.89 करोड़ रुपये तय किया गया है।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,307.56 करोड़ रुपये तय किया गया है।

स्टांप एवं पंजीकरण

- स्टांप एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 35,651.93 करोड़ रुपये तय किया गया है।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,504.73 करोड़ रुपये तय किया गया है।

प्राप्तियां

- कुल प्राप्तियां अनुमानित 7,21,333.82 करोड़ रुपये
- इसमें राजस्व प्राप्तियां 6,06,802.40 करोड़ और पूंजी प्राप्तियां 1,14,531.42 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की कर राजस्व की हिस्सेदारी 4,88,902.84 करोड़ है। इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2,70,086 करोड़ रुपये और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 2,18,816.84 करोड़ रुपये शामिल है।

व्यय

- कुल व्यय अनुमानित 7,36,437.71 करोड़ रुपये है।
- इसमें 5,32,655.33 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर और 2,03,782.38 करोड़ रुपये पूंजी खाते पर व्यय किया जाएगा।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने पर 15,103.89 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

- लोक लेखा से शुद्ध प्राप्तियां 5,500 करोड़ अनुमानित हैं।

लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- लेन-देन का शुद्ध परिणाम 9,603.89 करोड़ रुपये अनुमानित है।

अंतिम शेष

- प्रारंभिक शेष 38,189.66 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए अंतिम शेष 28,585.77 करोड़ रुपये अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 74,147.07 करोड़ अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ अनुमानित है, जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% है।

डिजिटल लेनदेन

- ► डिजिटल क्रांति के इस युग में उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उत्तर प्रदेश डिजिटल क्रांति का सर्वोत्तम उदाहरण बनकर उभरा है।
- ► 2017-18 में 122.84 करोड़ डिजिटल लेनदेन था, जबकि 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 1024.41 करोड़ डिजिटल लेनदेन किया गया।
- ► डिजिटल लेनदेन अपनाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आधे से ज्यादा लेनदेन UPI के जरिए किए गए। UPI QR कोड सार्वजनिक स्थानों पर दिखना आम बात है।
- ► इसका कारण डिजिटल बैंकिंग की आसान पहुंच, गांवों में इंटरनेट, वित्तीय जागरूकता और पर्याप्त संख्या में उपकरण हैं। डिजिटल लेनदेन के बारे में घर-घर जागरूकता फैली है और जनता ने इस तरीके को अपनाया है।
- ► बैंकों की 20416 शाखाओं, 4,00,932 बैंक मित्रों और बैंकिंग सेवा सखियों, 18,747 एटीएम और 4,40,095 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से

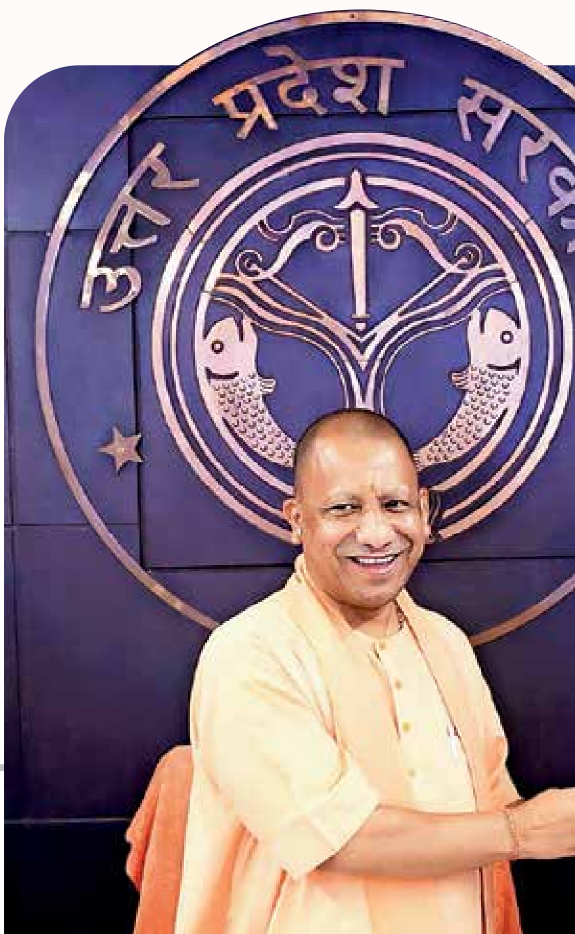

बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर)

- उत्तर प्रदेश डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी तक सीधे धन पहुंचाने में देश में अग्रणी है।
- 11 विभागों की 113 केंद्रीय योजनाओं और 94 राज्य क्षेत्र की योजनाओं सहित 207 योजनाओं का धन अंतरण डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है।
- वर्ष 2024-25 में, 09.08 करोड़ से अधिक लोगों को डीबीटी के माध्यम से 11111637 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- डीबीटी लेनदेन से 10 हजार करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है।

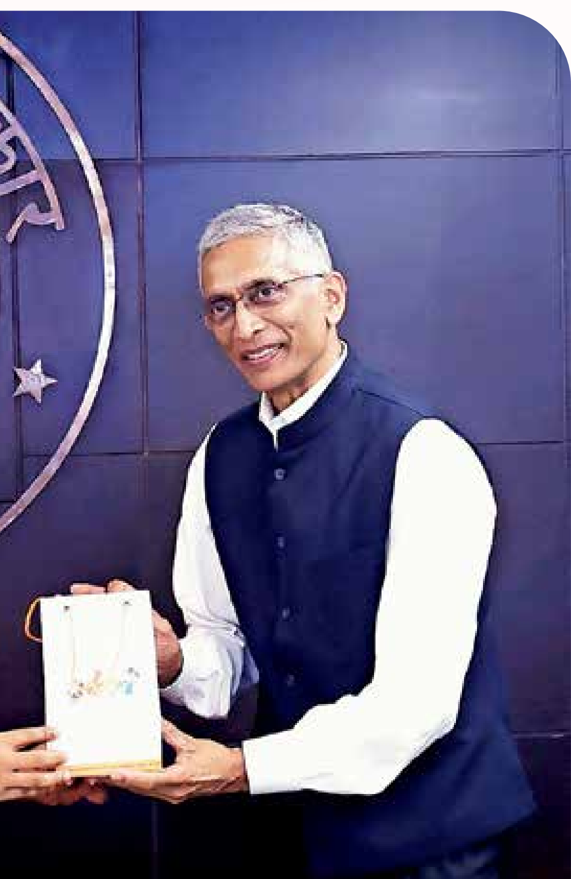

- FD1 - अप्रैल 2000 से जून 2017 तक 3303 करोड़ रुपये जबकि अप्रैल 2017 से सितंबर 2024 तक यह 14008 करोड़ रुपये था।

वित्तीय समावेशन

बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह निवेश और ऋण प्रदान करके अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश इस मामले में अग्रणी राज्य है।

- 2016-17 में बैंकों का कारोबार 12.75 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 28.66 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- उम्मीद है कि यह 2016-17 में केवल 46% से बढ़कर 2024 में 61% हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसे 67% से 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2024-2025 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत, दूसरी तिमाही तक बैंकों के माध्यम से 2.50 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
- धन आकर्षित करने में 16.2% हिस्सेदारी के साथ प्रदेश देश में शीर्ष पर है।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना वित्तपोषण हेतु धन जुटाने में उत्तर प्रदेश 16.2% हिस्सेदारी के साथ देश में शीर्ष पर है। (आरबीआई बुलेटिन, अगस्त 2023)

आयकर रिटर्न

- वर्ष 2020-21 में, उत्तर प्रदेश राज्य से कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 26,735 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 में बढ़कर 34,719 करोड़ रुपये, 2022-23 में 37,983 करोड़ रुपये और 2023-24 में 48,333 करोड़ रुपये हो गया।
- दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- उत्तर प्रदेश में 2022-23 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 71.65 होगी।
- डीमैट खाताधारकों की संख्या - कुल संख्या (31-03-2017 तक) 18,35,856
- कुल संख्या (24-02-2025 तक) - 2,20,31,883
- महिला खाताधारक (24-02-2025 तक) 28,68,571

आम जनता, विशेषकर महिलाएं, पूंजी बाजार में उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। यह राज्य के बदले हुए आर्थिक परिवेश का परिणाम है। आर्थिक विकास सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है क्योंकि इसका लक्ष्य समानता है।

अकेले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उत्तर प्रदेश की कुल 132 कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनकी बाजार पूंजी 3,61,162 करोड़ रुपये से अधिक है। महिला श्रम शक्ति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। 2017-18 में यह 13.5% थी जबकि 2022-23 में यह 31.2% हो जाएगी।

बेरोजगारी दर - वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (वार्षिक पीएलआईएस) के अनुसार, वर्तमान में 2023-24 में घटकर 3.0% होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश के जिले

सकल जिला उत्पाद में अग्रणी

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों ने अनुकरणीय प्रगति दिखाई है और व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में कार्य करते हुए सामूहिक रूप से राज्य की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि लोगों को आय सृजन के प्रति स्वायत्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साथ ही सरकार से हर संभव सहायता प्राप्त करनी चाहिए। इससे लोगों में स्वामित्व की भावना जागृत होगी और वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बनेंगे। एक कल्याणकारी राज्य इस सपने को साकार करने में सहायक होगा। परिणामस्वरूप, कई जिले अपने-अपने क्षेत्र विशेष के व्यवसायों में आगे बढ़े हैं। ओडीओपी इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि जिले अपने विशिष्ट उत्पाद लेकर आए हैं और उनका उत्पादन व निर्यात उस जिले को एक अलग स्तर पर ला रहा है।

उत्तर प्रदेश के सकल जिला उत्पाद के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य के जिले आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर सबसे अग्रणी है, जिसने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के दम पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद लखनऊ प्रशासनिक, सेवा क्षेत्र और रियल एस्टेट के कारण प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जबकि गाजियाबाद ने औद्योगिक और निर्माण क्षेत्र में विशेष प्रगति की है।

इन जिलों की उपलब्धियां दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक और कारोबारी हब बनने की दिशा में कई क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की औद्योगिक नीतियां, बुनियादी ढांचे का विस्तार और ओडीओपी जैसी योजनाएं इन जिलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही हैं।

राज्य में तीव्र विकास की दृष्टि और वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, सुनियोजित और अनुकूल योजनाओं, विकासात्मक पहलों और आवश्यकतानुसार, अर्थव्यवस्था के

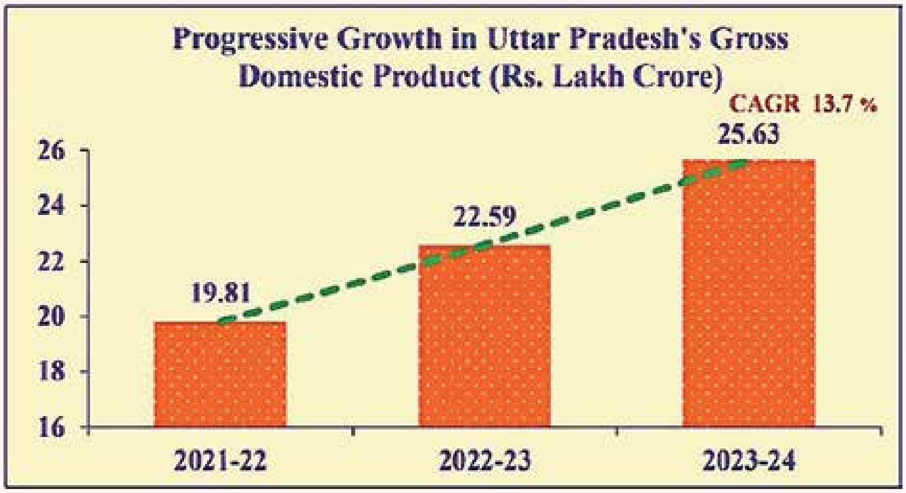

सभी क्षेत्रों में नई नीतियों के निर्माण के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2023-24 में, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर) में पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। इसकी तुलना में, भारत की जीडीपी 2023-24 में 9.2% बढ़ने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 19.81 लाख करोड़ रुपये था। पिछले तीन वर्षों में, यह 13.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 25.63 लाख करोड़ रुपये के त्वरित अनुमान तक पहुंच गया है। राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 13.5% विस्तारित हुई।

क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र 15.1% की वृद्धि दर के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र 13.2% और द्वितीयक क्षेत्र 10.3% रहा। द्वितीयक क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र ने 17.3% की वृद्धि दिखाई, जबकि तृतीयक क्षेत्र में, अन्य सेवा क्षेत्र में 15.9% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) में सबसे अधिक योगदान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र से 25.8% आया। इसके बाद रियल एस्टेट, आवासों के स्वामित्व और पेशेवर सेवा क्षेत्र से 14.7%, निर्माण क्षेत्र से 13.1% और विनिर्माण क्षेत्र से 10.2% का योगदान रहा।

गौतम बुद्ध नगर की सकल जिला घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी, उसके बाद लखनऊ और गाजियाबाद का स्थान था। यह सरकार द्वारा क्षेत्रों को औद्योगिक और विनिर्माण केंद्रों के रूप में विकसित करने के प्रत्यक्ष प्रयास का परिणाम है। पर्यटन क्षेत्रों में आतिथ्य से लेकर कुशल शिल्पकला तक प्रत्येक क्षेत्र मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने और राज्य को ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के करीब ले जाने में योगदान दे रहा है।

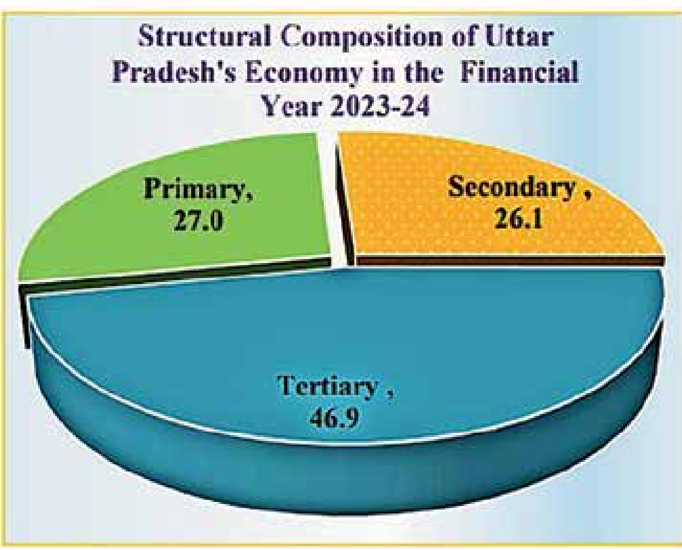

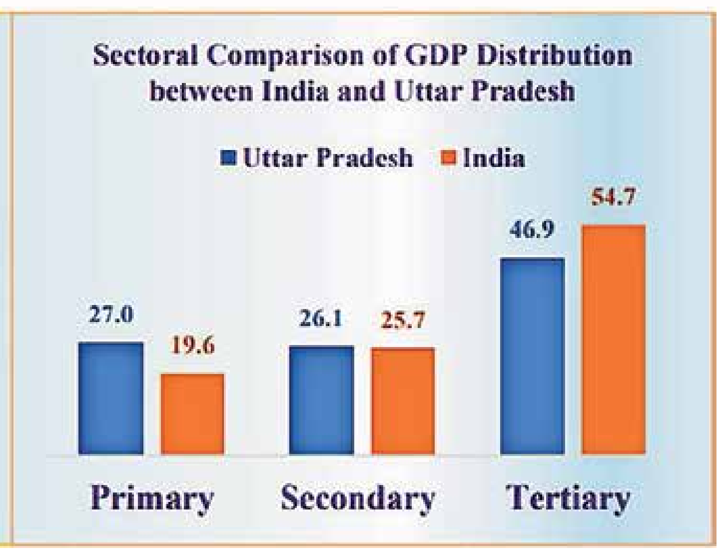

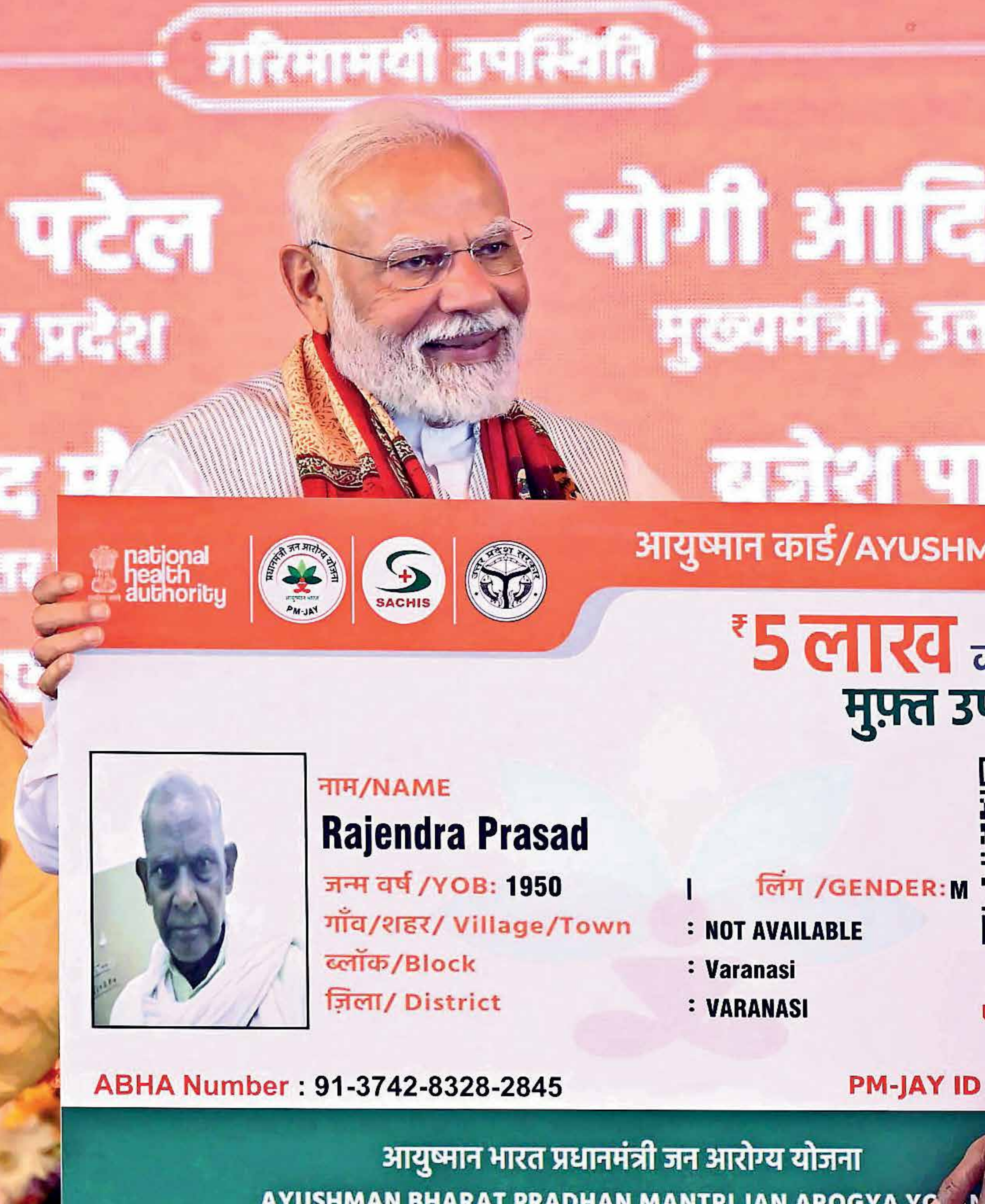
गरिमामयी उपस्थिति
पटेल
national health authority
PM-JAY
SACHIS
आयुष्मान कार्ड/
₹5 लाख
नाम/NAME
Rajendra Prasad
जन्म वर्ष /YOB: 1950
लिंग /GENDER: M
गाँव/शहर/ Village/Town : NOT AVAILABLE
ब्लॉक/Block : Varanasi
ज़िला/ District : VARANASI
ABHA Number : 91-3742-8328-2845
PM-JAY ID
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

सामाजिक सुरक्षा

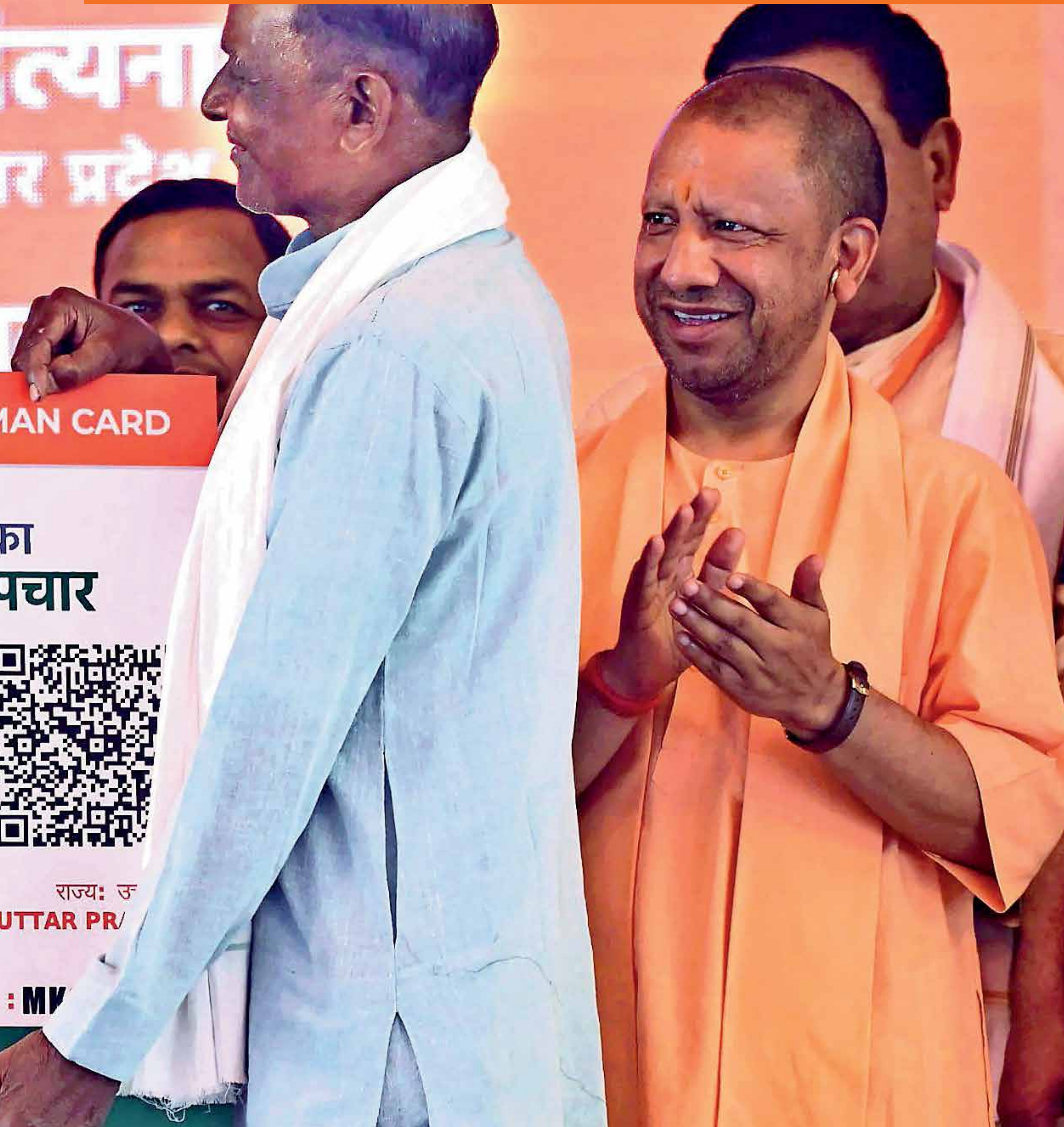

इन योजनाओं ने बदली तस्वीर

- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सभी जिलों में लागू की गई है और 3 वर्षों में 743 से अधिक युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 4,76,207 से अधिक जोड़ों का विवाह हुआ। इसके लिए प्रति जोड़े अनुदान राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
- निराश्रित महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत 1,06,17,640 लाख लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की गई है।
- महामारी के दौरान निराश्रित बच्चों और किशोरों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया गया।

डीबीटी

- **2017–नवंबर 2021:**
  2.75 लाख करोड़ रुपये
- **2021–22:**
  146 योजनाओं के अंतर्गत
  75,984.01 करोड़ रुपये
- **2024–25:**
  207 योजनाओं के अंतर्गत 9.08 करोड़ लाभार्थियों को **1,11,637 करोड़ रुपये**

गन्ना किसान (2017-2024):

2.85 लाख करोड़ रुपये

पीएम-किसान (अक्टूबर 2023 तक):

2.62 करोड़ किसानों को 60,845 करोड़ रुपये

योजनाएं और विभाग

- 2021-22: 146 योजनाएं, 27 विभाग
- 2024-25: 207 योजनाएं, 11 विभाग (113 केंद्रीय, 95 राज्य)
- 2025: 190 योजनाएं, 31 विभाग

डिजिटल लेनदेन

- 2017-18: 122.84 करोड़ रुपये
- 2024 (8 महीने): 1,024.41 करोड़ रुपये, मुख्यत: यूपीआई के माध्यम से

जन जन से सरोकार

सामाजिक कल्याण

गरीबी के चक्र से लोगों को बाहर निकालने से लेकर भोजन के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने तक, सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां शुरू की हैं, जिन्होंने नागरिकों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। ये योजनाएं और नीतियां समाज के हर वर्ग को शामिल करती हैं,ताकि प्रगति की राह में कोई भी पीछे न रह जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विश्वास के अपने सिद्धांतों को ही राज्य की नीतियों का एक अचूक आधार बनाया। मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सामाजिक कल्याण, शासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा, सरकार की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही विशिष्ट पहचान बन गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और विरासत के बीच एक नया सामंजस्य पैदा हुआ है।

लोगों को गरीबी के घेरे से बाहर निकालने में मदद करने से लेकर भोजन के बुनियादी अधिकार को सुनिश्चित

करने तक, सरकार ने कई कल्याणकारी नीतियां शुरू की हैं जिन्होंने नागरिकों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। इन योजनाओं और नीतियों में समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है ताकि कोई भी प्रगति और विकास से वंचित न रहे।

मिशनः जीरो पावर्टी (गरीबी उन्मूलन)

उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ नहीं किया। अदूरदर्शी नीतियों के कारण जनता को

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- सहकारिता के माध्यम से समृद्धि
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से 9,866.70 करोड़ का अल्पकालिक ऋण वितरित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहकारी बैंकों द्वारा 226.83 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण वितरित किया गया।
- सहकारी समितियों द्वारा 38.17 लाख मीट्रिक टन उर्वरक और 36,282 क्विंटल बीजों का वितरण किया गया।
- सहकारी बैंकों की 13 नई शाखाएं स्थापित की गईं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का विकास बहु-सेवा केंद्रों के रूप में किया गया।
- उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा मोबाइल एटीएम वैन का संचालन किया गया।

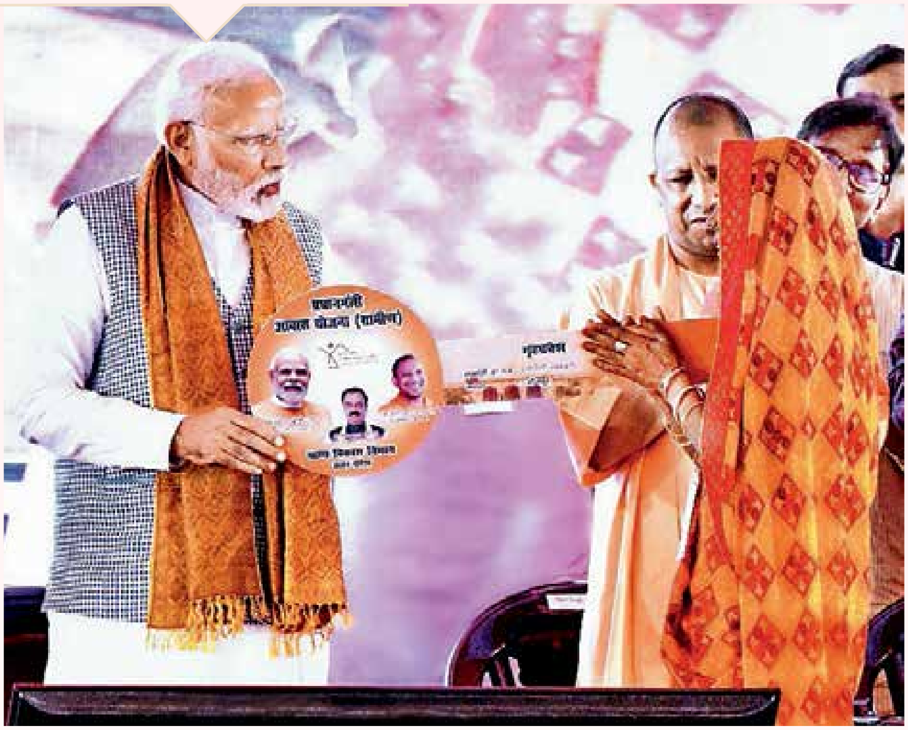

लगातार नुकसान उठाना पड़ता रहा। 2017 में, योगी आदित्यनाथ ने एक निश्चित सोच एवं दृष्टि के साथ राज्य का शासन संभाला और इस पर जोर दिया कि गरीबी दुश्मन है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने उचित शोध और लाभार्थियों की पहचान के बाद, आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए।

पिछले 8 वर्षों में राज्य सरकार 6 करोड़ से अधिक लोगों (देश में 24.82 करोड़) को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफल रही है।

गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2024 को एक शून्य गरीबी कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें कहा गया था कि राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह योजना डॉ. भीमराव अम्बेडकर को सामाजिक उत्थान में उनके अमूल्य योगदान के लिए समर्पित की गई है।

सरकार की योजना इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की है, जिससे उन्हें कम से कम 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय हो सकती है। इस योजना के तहत अब तक 13.57 लाख परिवारों की पहचान की गई है जिनके लाभ के लिए उन्हें सरकार की 17 योजनाओं के साथ संयोजन किया गया।

प्रमुख योजनाओं के संयोजन में राशन कार्ड, आवास, स्कूलों में प्रवेश, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, जल जीवन मिशन, शौचालय आदि शामिल हैं।

श्रमिकों का उत्थान

आधुनिक समाज में सबसे बड़े अन्यायों में से एक यह तथ्य है कि किसी को कुछ घंटों तक काम करने की आवश्यकता होती है लेकिन उन्हें उस अनुपात में भुगतान नहीं किया जाता है। योगी के शासन में, श्रम कार्य को समाज की आधारशिला माना जाता है और सही मजदूरी और उचित लाभ प्रदान करने के लिए उपाय किए जाते हैं।

सेवामित्र पोर्टल पर 52,064 कुशल कामगारों का पंजीकरण किया गया है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 6,92,564 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है।

कोविड अवधि के दौरान निराश्रित हुए पंजीकृत श्रमिकों और बच्चों के बच्चों की व्यवस्थित शिक्षा के लिए प्रत्येक मंडल में

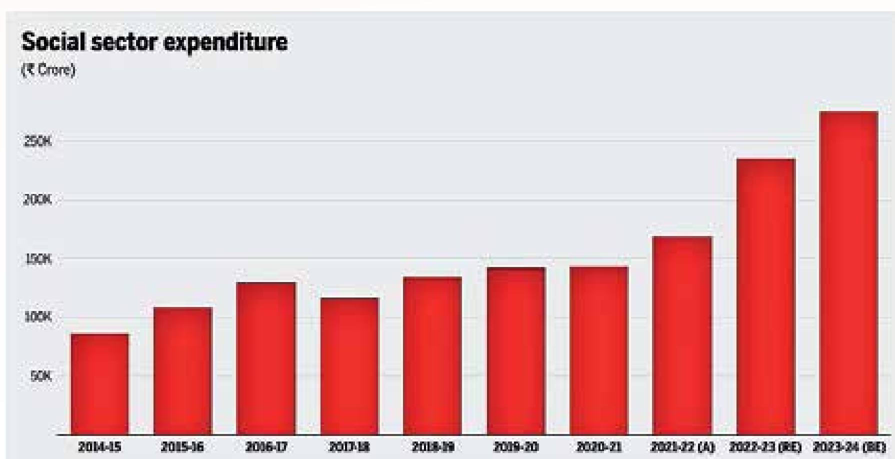

पूरी तरह से सुसज्जित अटल आवासीय विद्यालय संचालित हैं।कार्य संबंधी अन्य उपायः

- अटल पेंशन योजना से 93 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 9.52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए।
- कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपये की सहायता। स्थायी विकलांगता पर 3 लाख रुपये। आंशिक विकलांगता पर 2 लाख रुपये।
- पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का लाभ, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये का लाभ।
- विकलांगता के मामले में 2 लाख से 4 लाख रुपये का लाभ अंतिम संस्कार के लिए 25,000।
- कार्यस्थल पर एक अपंजीकृत कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के मामले में एक लाख रुपये।
- मातृत्व एवं बालिका सहायता योजना के तहत 6,22,974 लाभार्थी हैं।
- निर्माण श्रमिक मृत्यु और विकलांगता सहायता योजना के तहत 41,453 लाभार्थी हैं।
- एक पंजीकृत कर्मचारी की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत एक लाख रुपये देने का प्रावधान है। जाति के भीतर विवाह के मामले में 55,000 रुपये। एक पंजीकृत कर्मचारी की कुल 02 लड़कियों के लिए अंतर-जातीय विवाह के मामले में 61,000 रुपये।
- निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत, सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उपचार व्यय की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है।
- राज्य के 12 जिलों में आवासीय विद्यालय योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में 100 लड़कों और 100 लड़कियों को प्रवेश देने का प्रावधान है।

वंचित वर्ग के लिए सहानुभूति

मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवीनतम 2025-26 का बजट प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित है और 'वंचितों को प्राथमिकता' विषय का अनुसरण करता है।

योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा, इसमें कृषि से लेकर कल्याण, आस्था से लेकर आजीविका और शिक्षा से लेकर आत्मनिर्भरता तक सब कुछ शामिल है, जिससे विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव सुनिश्चित होती है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सभी जिलों में लागू की गई है और 03 वर्षों में 743 से अधिक युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण किया है।

मुख्यमंत्री के समूहिक विवाह के तहत 4,76,207 से अधिक जोड़ों ने शादी की। सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में बेसहारा महिलाओं, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन के तहत 1,06,17,640 लाख लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दी गई है। कोविड अवधि या उससे पहले के दौरान बेसहारा बच्चों और किशोरों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया गया है।

वित्तीय लाभः

- प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 32,49,854 छात्रों को कुल 708.49 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति।

- पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत, 89,31,203 छात्रों को 9, 662.25 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति।
- 2017-18 से 2023-24 तक, लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़े वर्गों के 63,55,798 छात्रों को 1,297.09 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 1,20,25,019 छात्रों को 5,788.14 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।

2015-16 से 2019-21 के बीच, उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाए। (नीति आयोग रिपोर्ट 'नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स - प्रोग्रेस रिव्यू 2023')

- प्री मैट्रिक सामान्य श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के तहत 8,58,750 छात्रों को 221.95 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।
- पोस्ट मैट्रिक सामान्य श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के तहत 48,13,347 छात्रों को 5,499.86 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।
- विवाह अनुदान योजना के तहत 4,75,567 लाभार्थियों को 951.13 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
- 2023 में 24960 तीर्थयात्रियों को हज यात्रा के लिए भेजा गया है। उनकी सहायता के लिए 30 हज सेवकों को भी भेजा गया था।
- एन. सी. ई. आर. टी. पाठ्यक्रम सहायता प्राप्त मदरसों में लागू किया गया।
- 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को 1, 000 रुपए प्रति माह रखरखाव अनुदान।
- कुष्ठ रोग पेंशन योजना में अनुदान राशि 2500 से 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
- दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के साथ कृत्रिम अंग प्रदान करने का प्रावधान।
- दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कारों की श्रेणियां 3 से बढ़ाकर 12 कर दी गई हैं और पुरस्कार राशि 5000 रुपये से बढ़ा कर 25000 रुपये कर दिए गए हैं।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 1,08,883 परिवारों को वित्तीय सहायता।

किन्नर कल्याण और सामाजिक समावेश की अवधारणा

अलग-थलग पड़े और उपेक्षित किन्नर समुदाय के प्रति सहानुभूति और जुनून दिखाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए कदम उठाये हैं। सरकार का लक्ष्य एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है,जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर प्राप्त हों। सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है।

2021 में, ट्रांसजेंडरों के लिए एक समर्पित कल्याण नीति लागू की गई थी। उसी वर्ष, योजनाओं की देखभाल करने के लिए उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था।

पहला 'गरिमा गृह' गोरखपुर में स्थापित किया गया है, जो ट्रांसजेंडरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में कार्य करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास सुविधाएं प्रदान करता है। अब तक 1,067 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत आसानी से लाभ उठा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, 248 ट्रांसजेंडर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, जिससे उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल होने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है।

- ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा उपलब्ध है।
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम-2019 पारित।

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2020 जारी किए गए।
- राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन और जिला स्तर पर कल्याण समितियों और ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन।
- राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

सभी के लिए भोजन

उत्तर प्रदेश में कोई भी बुनियादी जरूरतों से वंचित नहीं रहेगा या भूख से नहीं मरेगा। मुख्यमंत्री का यह बयान खाद्य संबंधी नीतियों की सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति रहा है।

पिछले आठ वर्षों में राज्य के 15 करोड़ गरीब लोगों को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल/साबुत चना, 1 किलो आयोडीन युक्त नमक, 1 किलो रिफाइंड तेल का मुफ्त वितरण किया गया है। इसके अलावा, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए प्रति माह 1 किलो चीनी का मुफ्त वितरण।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। होली और दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वितरण किया जाता है।

बेघर और कचरा इकट्ठा करने वालों के लिए भी राशन कार्ड की सुविधा बढ़ा दी गई है। डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था है। सामान्य सेवा केंद्र के रूप में उचित मूल्य की दुकानों का उन्नयन।

रबी विपणन वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक 233.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। किसानों को 43,424 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

फसल खरीद

- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक 456.86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और 88, 746 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
- बाजरे की खरीद खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 से शुरू हुई। 75, 434 किसानों से 3,98,475.89 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया और कुल 98, 193.59 लाख रुपये का भुगतान हुआ।
- पहली बार ज्वार की खरीद 2023-24 में की गई थी। 2787 किसानों से 13340 मीट्रिक टन ज्वार खरीदा गया और 422.76 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
- खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक 27,818 किसानों से 1,18,769 मीट्रिक टन मक्के की खरीद की गई। 22, 05. 21 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

केंद्र सरकार की एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना मई, 2020 से राज्य में लागू की गई थी, जिसमें अब तक अन्य राज्यों के 71,917 कार्ड धारकों और यूपी के 67,94,000 लाख कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्रदान किया गया है।

क्षेत्रीय संतुलन

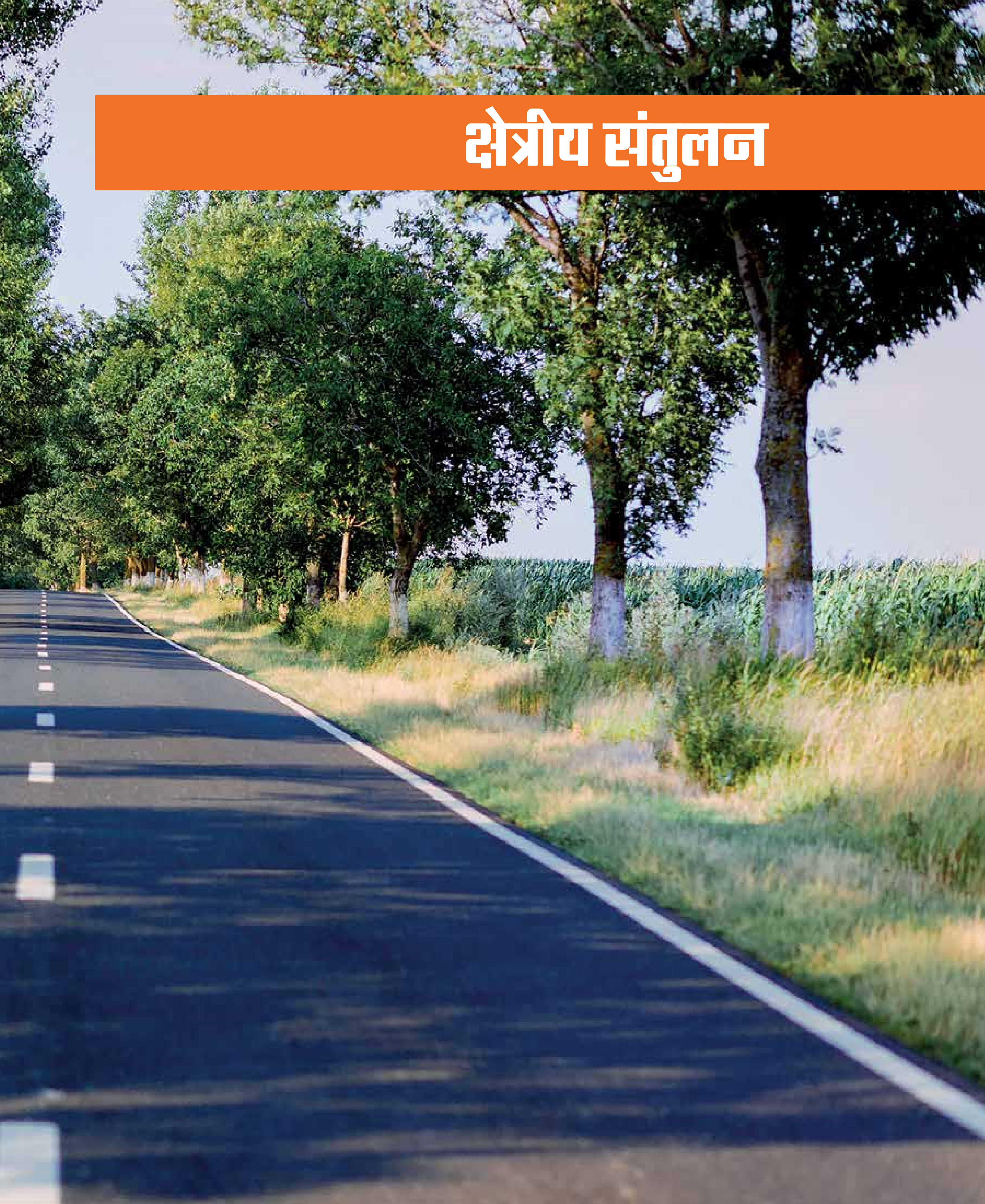

जिलों की नई उड़ान

आकांक्षी जिला

उत्तर प्रदेश के आठ जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए हैं: बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। यह कार्यक्रम, जिसे नीति आयोग ने जनवरी 2018 में शुरू किया था, इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुधारना है।

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष जून में अब तक 108 आकांक्षी विकास खंडों में निरीक्षण किए गए, जिनमें 272 स्कूल, 301 आंगनवाड़ी केंद्र, 232 स्वास्थ्य इकाइयां, 229 ग्राम पंचायत सचिवालय और 275 अन्य संस्थान शामिल थे।

वर्तमान में, 497 किसान उत्पादक संगठन सक्रिय हैं, और 6,595 बीसी (बैंकिंग सखियां) वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि 'ब्लॉक विकास रणनीति' के अंतर्गत 106 ब्लॉकों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं।

मुख्यमंत्री लगातार विकास प्रगति के सटीक आकलन के लिए डेटा संग्रह प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। निरीक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों का गहन विश्लेषण करके योजनाओं की गहन निगरानी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं:

- **फोकस क्षेत्र:** यह कार्यक्रम इन जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है।
- **प्रदर्शन मापन:** जिलों को 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) में उनकी प्रगति के आधार पर मासिक रूप से रैंकिंग दी जाती है।
- **राज्य की भूमिका:** यह कार्यक्रम विकास पहलों को आगे बढ़ाने और प्रत्येक जिले की विशेषताओं का लाभ उठाने में राज्यों की भूमिका पर जोर देता है।
- **अभिसरण और सहयोग:** यह कार्यक्रम जिलों के बीच अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।
- **विशिष्ट उदाहरण:** फतेहपुर जिले ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए राष्ट्रीय मानक को उल्लेखनीय रूप से पार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के सभी आठ आकांक्षी

जिलों ने अटल पेंशन योजना में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है।

उत्तर प्रदेश ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसके कई ब्लॉकों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। नीति आयोग ने राज्य के इस प्रदर्शन की सराहना की है, जिसने उत्तर प्रदेश के सफल मॉडल पर आधारित एबीपी पहल शुरू की थी।

उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:

राष्ट्रीय मान्यता:

- राज्य के ब्लॉकों द्वारा की गई प्रगति के लिए नीति आयोग ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है।

शीर्ष रैंकिंग:

- उत्तर प्रदेश के कई ब्लॉकों ने एबीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिनमें ज़ोन 2 में हरैया (बस्ती) और विरनो (गाजीपुर) और समग्र रैंकिंग में जमुनहा (श्रावस्ती) शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धात्मक भावना:

- यह कार्यक्रम ब्लॉकों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देता है और उन्हें प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सामाजिक-आर्थिक विषयों पर ध्यान:

- एबीपी का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक-आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करके जीवन स्तर में सुधार और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण:

- कार्यक्रम का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर केंद्रित विकास प्रयासों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण करना है।

वित्तीय प्रोत्साहन:

- नीति आयोग शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को आर्थिक पुरस्कार प्रदान करता है, जिससे उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलती है।

जनवरी 2023 में शुरू किया गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, भारत के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में शासन और सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की भागीदारी और सफलता समावेशी विकास और सतत विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि 106 आंगनवाड़ी केंद्रों पर वजन मापने वाली मशीनें चालू कर दी गईं और पात्र बच्चों का नामांकन मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत किया गया।

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने महोबा जिले में हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री, नर्सरी सोलर पैनल, जैविक कृषि उपकरण, कृषि मशीनरी, बायोगैस संयंत्र की पेशकश करने वाले बहुउद्देशीय ग्रामीण मार्ट की स्थापना और झोपड़ियों, सेल्फी पॉइंट और रेस्टोरेंट के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "आशियाना बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड" की सराहना की है।

मुख्यमंत्री ने बलिया के बांसडीह में छह हेक्टेयर में नींबू की जैविक खेती और निर्यात की प्रशंसा की और बाराबंकी के पूरेदलाई में प्रतिभा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय स्तर पर संचालित ब्यूटी पार्लर के माध्यम से 15,000 रुपये की आय अर्जित करने की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने फतेहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित कैंसर जांच केंद्र को तकनीकी नवाचार का एक आदर्श बताया और इसे अन्य जिलों में भी अपनाने की सिफारिश की।

जनजातियों का उत्थान

मुसहर और वनटांगिया

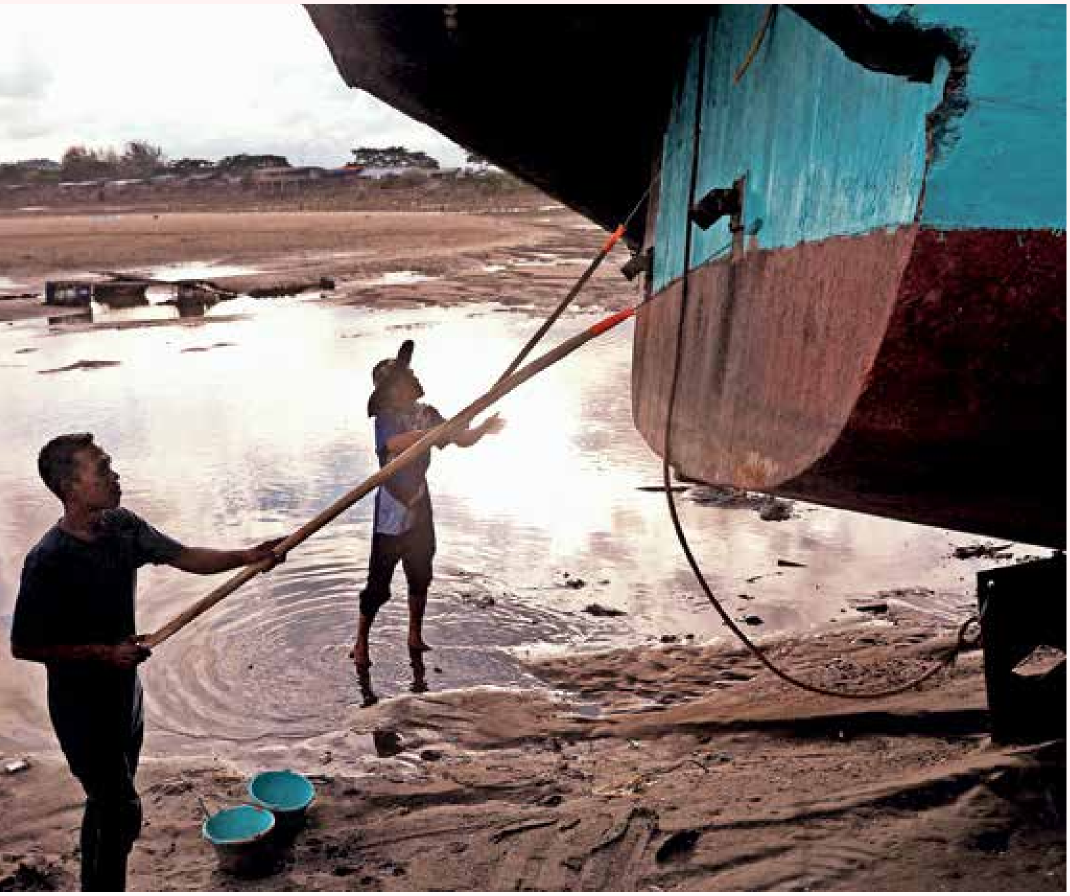

प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार सत्ता में आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुसहर और वनटांगिया समुदाय के उत्थान को एक मिशन के रूप में लिया।

राज्य का दृष्टिकोण बदलना यहां के नेतृत्व के लिए प्राथमिकता रहा है। एक अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से नए सामाजिक प्रयोगों को लागू करना भी इसकी सूची में मुख्य तौर पर शामिल रहा है। चूहे खाने वाले समुदाय के रूप में जाने जाने वाले मुसहर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में रहते हैं और दशकों से सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित हैं, लेकिन पिछले 8 सालों में मुसहरों के लिए चीजें बेहतर होने लगीं। वर्तमान यूपी सरकार अधिकारों से वंचित समुदायों के लिए एक नया सामाजिक आधार बनाने की कोशिश कर रही है जो पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं में शामिल नहीं था।

परंपरागत रूप से, मुसहर मधुमक्खी पालक (शहद संग्राहक) और स्थानीय बिक्री के लिए पत्ती की प्लेट बनाते हैं। यह समुदाय खेती, श्रम मजदूरी, मछली पकड़ने, वानिकी, रिक्शा और गाड़ी खींचने, ईंट-भट्ठों में श्रम, रेशम उत्पादन और सुअर पालन में लगा है। मुसहर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। वे मुख्य रूप से गोरखपुर, वाराणसी, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली में हैं। कुशीनगर में मुसहरों की आबादी सबसे ज्यादा है। जिले की लगभग 138 ग्राम सभाओं में 159 बस्तियों में 10,414 मुसहर परिवार हैं। जिले के कम से कम 10 ब्लॉकों में मुसहर आबादी का दबदबा है। दुदही ब्लॉक की 36 ग्राम सभा और खड्डा ब्लॉक की 30 ग्राम सभा में अधिकांश मुसहर रहते हैं।

1871 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें 'अछूत' और एक आपराधिक जनजाति के तौर पर घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से ही यह समुदाय कई दशकों तक गरीबी, उत्पीड़न और भेदभाव झेलता रहा। पूर्ववर्ती सरकारों में, हालांकि उन्हें 1950 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदायों में शामिल किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी लाभ उन्हें कभी नहीं मिले। वे स्वच्छ पेयजल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और स्वरोजगार योजनाओं और लाभों जैसी सबसे बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ही रहे।

वर्तमान यूपी सरकार और उसके नेतृत्व ने मुसहरों की दुर्दशा से अवगत होकर उनको शिक्षा, स्वच्छ पानी, आवास, स्वच्छता, चिकित्सा-स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार आदि के साथ मुख्यधारा में लाने के लिए समानता आधारित लाभ देने की पहल की है। केवल 8 वर्षों के छोटे से समय में समुदाय में एक बड़ा बदलाव आया है जिससे उन्हें अभाव से तो मुक्ति मिली ही है, बल्कि पुनर्वास प्राप्त करने में भी मदद मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसहर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए व्यापक और ठोस कदम उठाए हैं। दशकों तक उपेक्षित इस समुदाय को अब सरकारी योजनाओं और कल्याण पहलों के माध्यम से सशक्त बनाने का मार्ग मिल गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं

- लगभग 10,000 परिवारों को अंत्योदय कार्ड (सबसिडीयुक्त खाद्य योजना के लिए) और 1,000 से अधिक परिवारों को राशन कार्ड प्रदान किए गए।
- 10 मुसहर प्रधान विकास खंडों में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लगभग 7,894 मकान बनाए गए।
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गांव में अब 100 से अधिक परिवारों को मकान प्रदान किए गए हैं।
- मनरेगा योजना के तहत 10,320 मुसहरों को जॉब कार्ड प्रदान किए गए।
- राज्य सरकार पेंशन लाभार्थियों की पहचान भी कर रही है; 1,297 से अधिक लोग वरिष्ठ नागरिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और 180 लोग विकलांग पेंशन ले रहे हैं।
- गोरखपुर, गोण्डा और महाराजगंज जिलों, बहराइच और लखीमपुर खीरी में फैले वनटांगिया गांवों को अब राजस्व गांव का दर्जा दिया गया है।
- गोरखपुर के टिंकोनिया नम्बर 3, जंगल रामगढ़, आमबाग, राजही टोला, चिलबिलवा, रामगढ़ सरकार और आजादनगर क्षेत्र के वनटांगियों को पीने योग्य पानी, स्वास्थ्य सुविधाएँ और आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
- वनटांगियों के बीच नक्सलियों के पैर जमाने की कोशिशों को प्रभावी ढंग से रोका गया।

समृद्धि की ओर गांव

ग्रामीण विकास

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सड़क और पुलों का नया नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों और ई-वे मार्गों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश सरकार कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ किसानों के कल्याण पर जोर दिया। इस बजट का उद्देश्य 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की नींव रखना और राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक 2.57 लाख घरों का निर्माण पूरा किया गया। इस योजना के लिए 1,140 करोड़ का प्रावधान किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों को मौजूदा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे जैसे परियोजनाओं के प्रारंभिक

महोबा, बागपत, झांसी और ललितपुर को राज्य के उन जिलों की शीर्ष सूची में शामिल किया गया है, जहां ग्रामीण घरों को अधिकतम नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है, ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। राज्य के अन्य जिले भी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने के लिए तेजी से काम कर रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस सूची में मिर्जापुर, चित्रकूट और बांदा जिले भी शामिल हैं। 10 जिलों में ग्रामीण घरों के 60% तक घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया गया है। वहीं, आठ जिलों ने ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं के प्रमुख बिंदु

सभी के लिए छत

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत 55 लाख घरों का निर्माण/मंजूरी।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2.57 लाख घरों का निर्माण।

समृद्ध गांव

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4,007 किमी सड़क का निर्माण।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य, अब तक 9,289 अमृत सरोवर बनाए गए।
- 64 संकटग्रस्त नदियों का पुनरुद्धार। मनरेगा के तहत 164.80 करोड़ मानव दिवस सृजित।
- मनरेगा के तहत 100 दिन पूर्ण रोजगार प्रदान करने में यूपी देश में शीर्ष पर।
- 72,69,755 ग्रामीण परिवारों को 6,93,663 स्व-सहायता समूहों द्वारा कवर किया गया।
- 600 उत्पादक समूह (Producer Groups) और 32 उत्पादक उद्यम (Producer Enterprises FPO) का गठन।
- कृषि आजीविका संवर्धन के तहत 3,78,061 महिला किसान परिवारों को अपनाया गया।
- विकास खंड की 2 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को 'ग्राम चौपाल' का आयोजन।
- एफडीआर तकनीक के साथ 202 मार्गों पर कार्य प्रगति पर। उत्तर प्रदेश एफडीआर तकनीक के उपयोग में अग्रणी राज्य।

सड़क और पुल

- गड्ढामुक्त 60,397 किमी मार्ग, 6,925 किमी सड़क का नवीनीकरण, और 7,268 किमी मार्ग पर विशेष मरम्मत कार्य।
- 125 पुलों और 60 अंतर-राज्य प्रवेश द्वारों का निर्माण।
- 2,941 किमी नई सड़क का निर्माण और 2,242 किमी मार्ग का चौड़ीकरण/मजबूतीकरण।
- 70 नए राज्य मार्गों की घोषणा।
- 57 नए मुख्य जिला मार्ग।
- 26 तहसील मुख्यालयों को 2-लेन सड़क से जोड़ा गया।
- 151 विकास खंड मुख्यालयों को 2-लेन सड़क से जोड़ने और चौड़ीकरण के लिए 2,199 करोड़ मंजूर।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के निवास/गांव तक मेजर ध्यांचंद पथ विकसित करने के लिए नवोन्मेषी योजना।
- 21 खिलाड़ियों के निवास/गांव की सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य पूरे।
- 46 शहीदों के नाम पर जय हिंद वीर पथ योजना और 44 सड़कें घर/गांव तक बनाई गईं।

चरणों के लिए 235 करोड़ आवंटित किए गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए। सड़कों के निर्माण के लिए 21,159.62 करोड़ और रख-रखाव के लिए 6,209.5 करोड़ का बजट रखा गया। रोड ओवरब्रिज (ROBs) के लिए 1,700 करोड़ और अन्य पुलों के लिए 1,850 करोड़ का प्रावधान किया गया।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार, यातायात की सुविधा और विकास की गति में तेजी आएगी। इससे किसानों और ग्रामीण व्यवसायियों को अपने उत्पाद शहरों और बाजारों तक जल्दी और सस्ते में पहुंचाने में मदद मिलेगी, जिससे आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।

डिजिटाइजेशन

डिजिटलीकरण को बढ़ावा

डिजिटल क्रांति को मिल रहा निरंतर विस्तार

राज्य के रणनीतिक क्षेत्रों, विभागों और सेवाओं में विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण हिस्सों में डिजिटलीकरण कार्यकुशलता की नई सुबह ला रहा है।

वर्ष 2017 में राज्य सचिवालय से डिजिटलीकरण अभियान शुरू करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलिंग और कागजी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल मोड में बदल दिया। ई-ऑफिस प्रणाली के तहत, भौतिक फाइलों को तेजी से डिजिटल फाइलों में बदला गया, जिससे समय और कागज की बर्बादी रुकी और फाइल निपटान की गति बढ़ी।

जनहित गारंटी अधिनियम 2011

जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत मार्च 2017 से पहले केवल 145 सेवाएं सूचीबद्ध थीं, जिनमें से 55 सेवाएं ही आम जनता को ऑनलाइन उपलब्ध थीं। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया कि अधिनियम के अंतर्गत सभी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जाए। साथ ही, ई-डिस्ट्रिक्ट, निवेश मित्र पोर्टल और 'दर्पण' डैशबोर्ड को प्राथमिकता पर एकीकृत किया गया। परिणामस्वरूप, वर्तमान में जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 37 विभागों की 454 सुविधाएं जनता को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं।

डिजिटल गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस के लिए तकनीक को सक्रिय रूप से अपनाने से यूपी प्रशासन ने विभिन्न डिजिटलीकृत योजनाओं और नीतियों के जरिए राज्य के नागरिकों तक पहुंच बनाई। 'ई-कैबिनेट' की नई अवधारणा के तहत, महामारी के दौरान राज्य सरकार ने पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया और सत्र टैबलेट्स के माध्यम से संचालित हुआ। 'ई-ऑफिस' पहल से इसके कई विभाग पूरी तरह ऑनलाइन कार्यरत हो गए हैं।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटलीकरण

निवेश मित्र पोर्टल विभिन्न ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रदान करता है और पारंपरिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन इंसेंटिव्स मॉनिटरिंग सिस्टम (OIMS) भी लागू किया गया है। इस पोर्टल की सफलता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अब तक 12 लाख से अधिक ऑनलाइन NOC संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराए गए हैं।

ई-साथी पोर्टल

इस पोर्टल के जरिए, यूपी सरकार ने

आम नागरिक को सुविधा दी है कि वह अपने रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं के लिए आवेदन कर सके। आवेदन निपटान के बाद, नागरिक इसी पोर्टल से प्रमाणपत्र/निपटान पत्र डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए नागरिक का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।

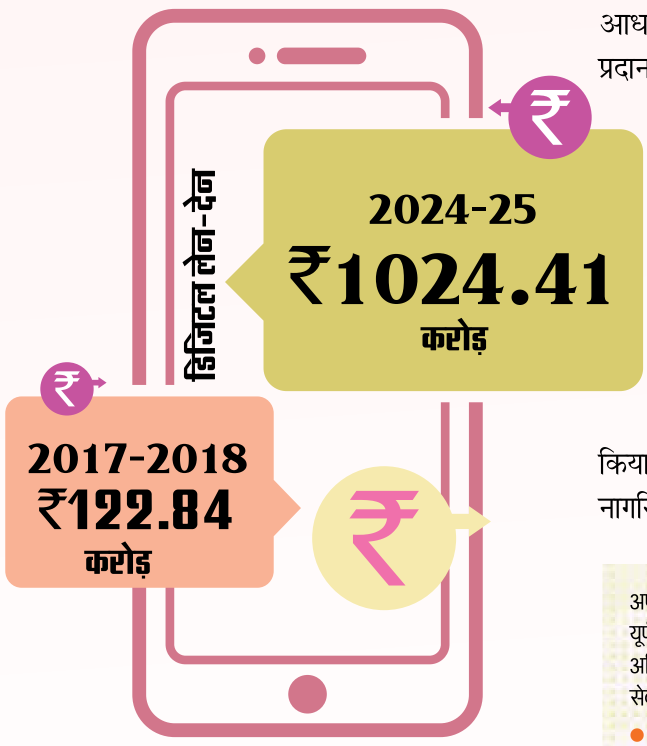

सीएम डैशबोर्ड

योगी आदित्यनाथ सरकार सभी विभागों के प्रदर्शन और 75 जिलों में सरकारी योजनाओं व नीतियों के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मुख्यमंत्री डैशबोर्ड स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के जन शिकायत अनुभाग के अंतर्गत एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो सीएम डैशबोर्ड की भी निगरानी करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के पास लगभग 92 विभाग हैं। 75 जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख कर रहे प्रशासन की उत्पादकता और दक्षता का आकलन किया जाएगा। साथ ही, हितधारकों के प्रदर्शन और उनके द्वारा प्रस्तुत डाटा की गुणवत्ता और सटीकता का अलग से मूल्यांकन होगा। मासिक आधार पर दो सूचकांकों के जरिए रैंकिंग प्रदान की जाएगी।

नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि राज्य में नागरिक सेवाओं का और अधिक डिजिटलीकरण किया जा सके। इस MoU का उद्देश्य सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन करना है। NUDM के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में गवर्नेंस के ऑनलाइन वितरण के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए नागरिक संपत्ति कर आकलन और भुगतान, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन, नगर निगम शिकायत निवारण, ट्रेड लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाणपत्र, जल और सीवरेज शुल्क, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र आदि सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

यूपी भूलेख

यूपी राजस्व परिषद ने राज्य के भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर उन्हें एक वेब पोर्टल के जरिए नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया है। इस प्रक्रिया में राज्य के NIC को शामिल किया गया, जिससे भूमि स्वामित्व से संबंधित विवरण, जैसे 'खतौनी' (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स), पारदर्शी रूप से सभी को उपलब्ध हो सके। इस पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि भूमि अभिलेख सत्यापित करने के लिए किसी नागरिक को तहसीलदार या पटवारी के पास न जाना पड़े।

अपने डिजिटल मिशन के तहत यूपी सरकार द्वारा जनहित गारंटी अधिनियम के तहत डिजिटलीकृत सेवाओं में शामिल हैं :

- कृषि
- पशुपालन
- पिछड़ा कल्याण
- बुनियादी शिक्षा
- वाणिज्यिक कर
- सहकारिता
- डेयरी विकास
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
- उत्पाद शुल्क
- वित्त
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
- उपभोक्ता संरक्षण
- वजन और माप
- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि
- प्रशासन
- भूविज्ञान और खनन
- उच्च शिक्षा
- पुलिस
- बागवानी
- आवास और शहरी नियोजन
- आईआईडीसी ग्रेटर नोएडा
- आईआईडीसी नोएडा
- आईआईडीसी पिकअप
- यूपीएसआईडीसी
- आईआईडीसी यमुना
- एक्सप्रेस-वे
- आईआईडीसी इन्वेस्ट यूपी
- आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
- सूचना विभाग (फिल्म बंधु)
- खादी एवं ग्रामोद्योग श्रम
- कारखाना निदेशालय
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- चिकित्सा शिक्षा
- नामामि गंगे (भूजल)
- पंचायती राज
- बिजली
- लोक निर्माण विभाग
- राजस्व
- ग्रामीण विकास
- माध्यमिक शिक्षा
- सामाजिक कल्याण
- चीनी उद्योग और गन्ना विकास
- तकनीकी शिक्षा
- परिवहन
- शहरी विकास
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास
- महिला एवं बाल विकास

पर्यटन

विश्व का स्वागत करता यूपी

पर्यटन विकास

यहाँ आने वाले पर्यटक सांस्कृतिक विविधताओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और बड़ी संख्या में पुनः यहाँ आने लगे। आज उत्तर प्रदेश सभी प्रकार की रुचियों को पूरा करने वाला एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन गया है।

यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति, परंपरा, धर्म और इतिहास का सुंदर संगम है। वाराणसी के पवित्र घाटों से लेकर प्रयागराज की अद्वितीय दिव्यता तक उत्तर प्रदेश के पास पर्यटन गंतव्यों की समृद्ध थाती है।

पिछले आठ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहितकारी नीतियों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश सुरक्षित हो और लोगों के भ्रमण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करे। अनेक दृष्टियों से यह राज्य अनेक पर्यटकों का दूसरा घर बन चुका है।

पर्यटन उद्योग में सबसे रोचक विकास धार्मिक पर्यटन के प्रोत्साहन से हुआ है। महाकुम्भ इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दर्ज होने वाला आयोजन है, जिसने यह साबित कर दिया कि सरकार इस स्तर के विराट आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में पूरी तरह सक्षम है।

उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य है जहां सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक कुल 66 करोड़ पर्यटक यहां आए, जिनमें 14,01,127 विदेशी पर्यटक शामिल थे। महाकुम्भ 2025 में देश और विदेश से आए 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया।

सरकार ने मंदिर क्षेत्र प्रबंधन में समन्वय और सुव्यवस्थित करने के लिए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद, श्री चित्रकूट

उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

वर्ष	संख्या
2017	23.40 करोड़
2018	28.50 करोड़
2019	39.06 करोड़
2020	8.65 करोड़ (कोविड)
2021	9.30 करोड़ (कोविड)
2022	31.85 करोड़
2023	48.01 करोड़
2024	64.90 करोड़

यूपी ईको-टूरिज्म

- दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने स्थानीय थारू समुदाय को पर्यटन अनुभव से जोड़ने की योजना शुरू की है।
- इस पहल के तहत पर्यटकों को थारू जनजाति का विशिष्ट भोजन, जीवनशैली और हस्तशिल्प दिखाया जाएगा, जिससे स्थानीय समुदाय की आय में वृद्धि होगी।
- लखीमपुर खीरी जिले के नौ गांवों में रहने वाली थारू जनजाति सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल में जीवन जीती आई है और अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक समृद्धि में बदलने के लिए तैयार है।
- इको-टूरिज्म बोर्ड थारू जनजाति के पारंपरिक व्यंजनों, हस्तशिल्प और जीवनशैली को पर्यटन अनुभव का हिस्सा बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।
- थारू समुदाय अब सीधे रिसॉर्ट्स और होटलों तक अपने पारंपरिक व्यंजन जैसे धिकरी, खड़िया और कपुआ (चावल के आटे से बने) उपलब्ध करा रहा है।
- थारू व्यंजनों के अलावा, मूनज घास, कांस, जूट और कपास से बने स्थानीय हस्तशिल्प थारू शिल्पग्रामों, स्थानीय स्टॉलों और आवासीय स्थलों पर भी उपलब्ध रहेंगे।
- इको-टूरिज्म बोर्ड थारू समुदाय की समृद्ध नृत्य और संगीत परंपराओं को भी उजागर कर रहा है, जिसमें सखिया, देवली, धमार, झुमरा और होली गीतों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन शामिल है।
- इको-टूरिज्म बोर्ड थारू समुदाय को नए होमस्टे शुरू करने और मौजूदा होमस्टे को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
- दुधवा टाइगर रिजर्व, जो भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है, केवल वन्यजीवों का स्वर्ग नहीं है, बल्कि थारू संस्कृति और ज्ञान को अनुभव करने का भी केंद्र है।

धाम तीर्थ तथा नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है।

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ ही प्रतिष्ठित श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ। मंदिर निर्माण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए पहले वादों में से एक था। यह मंदिर आज अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं।

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सरकार ने प्रति श्रद्धालु 1 लाख रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की है। सिंधी समुदाय के सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रियों को भी वित्तीय वर्ष 2019-20 से 20 हजार रुपये से अधिक प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जा रहा है।

हाथरस जिले के 'लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज', अयोध्या जिले के 'मकर संक्रांति मेला' और 'बसंत पंचमी मेला', बुलंदशहर जिले के 'कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला अनूपशहर' और वाराणसी जिले के देव दीपावली मेले का प्रांतीयकरण किया गया है।

सरकार ने गोरखपुर में गोरखा रेजिमेंट सेंटर, शहीद स्मारक और संग्रहालय के साथ-साथ कौशाम्बी में संग्रहालयों का निर्माण कार्य शुरू किया है। बाराबंकी में पद्मश्री बाबू केडी सिंह के पैतृक घर को स्टेडियम में परिवर्तित किया जा रहा है। ये संग्रहालय हमें इतिहास की झलक दिखाते हुए एक नए भविष्य का निर्माण करते हैं।

आगरा और मथुरा जिलों में हेलीपोर्ट

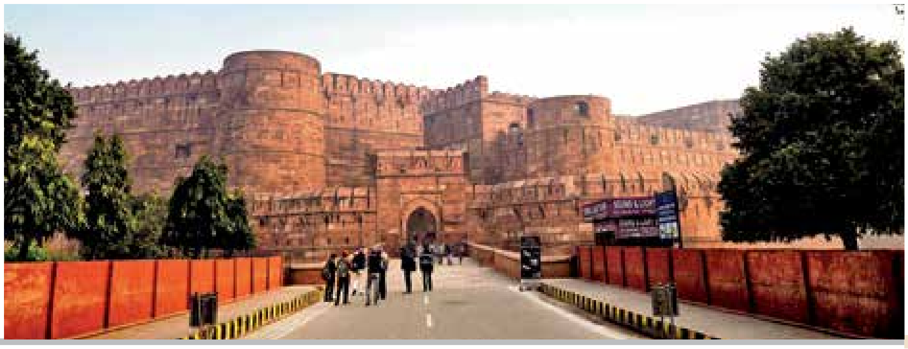

के संचालन का उद्घाटन हुआ। वहीं, लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट सेवा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

सरकार कुशीनगर जिले में बुद्ध थीम पार्क परियोजना पर काम कर रही है। पर्यटन के लिए प्राचीन और विरासत भवनों का पीपीपी मॉडल पर दत्तक पुनः उपयोग के तहत विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप योजना भी शुरू की गई है।

राज्य में सांस्कृतिक पुनर्जागरण

- वृद्ध एवं निर्धन कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के 400 से अधिक वृद्ध एवं निर्धन कलाकारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है।
- भातखंडे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय को मानद संगीत विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त।
- दीपोत्सव अयोध्या में 25,12,585 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
- बलरामपुर जिले में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, लखनऊ में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का

काल्याणकारी नीति

- योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) और होमस्टे नीति 2025 शुरू की है।
- इस नीति का उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती आवास प्रदान करना है, साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- नए ढांचे के तहत, बी एंड बी और ग्रामीण होमस्टे इकाइयों के सभी मालिकों को नीति लागू होने के एक वर्ष के भीतर अपनी संपत्तियों का पंजीकरण कराना होगा। यह पहल उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती है और पंजीकृत संचालकों के लिए कई लाभ लेकर आती है।
- पर्यटन मेलों, उत्सवों, ट्रैवल मार्ट या रोड शो में भाग लेने वाली पंजीकृत इकाइयाँ वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने पर 1 लाख रुपये तक और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने पर 3 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- इस नीति का उद्देश्य सेवा मानकों में सुधार और आवास विकल्पों में विविधता लाना है।
- इस पहल का उद्देश्य आगंतुकों को अधिक आनंददायक, किफायती और यादगार प्रवास प्रदान करना है।

निर्माण और गोरखपुर व मेरठ संग्रहालय का सुदृढ़ीकरण।

► आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय की स्थापना।

► पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर आगरा में सांस्कृतिक परिसर का लोकार्पण।

► सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चारदीवारी का निर्माण।फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज और ककरऊ कोठी में महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊँची अश्वारोही कांस्य प्रतिमा की स्थापना।

► उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान-2024 से प्रदेश का नाम रोशन करने वाले महापुरुषों को सम्मानित करने का प्रावधान।

► भातखंडे सम विश्वविद्यालय को संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

संस्कृति और पर्यटन के सम्मिश्रण के प्रति समर्पित दृष्टिकोण का एक उदाहरण सर्किट का विचार है। ये नियोजित मार्ग हैं जिन पर एक पर्यटक कई स्थानों की यात्रा कर सकता है जो किसी विशेष विषय पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये उपाय तभी संभव हैं जब नेतृत्वकर्ता का इस क्षेत्र के प्रति समग्र दृष्टिकोण हो।

सरकार ने रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, कृष्ण/ब्रज सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, जैन सर्किट और वन्य जीवन एवं इको टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

पर्यटन अवसंरचना

- उत्तर प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने दो प्रमुख संपत्तियों, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) स्थित राही टूरिस्ट गेस्ट हाउस और इटावा स्थित सुमेर सिंह फोर्ट गेस्ट हाउस को आलीशान, विश्वस्तरीय पर्यटन आवासों में बदलने की पहल शुरू की है।
- इस विकास कार्य को और सुगम बनाने के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- पहले कम उपयोग में आने वाले इन गेस्ट हाउसों का विकास और संचालन अब सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा, जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र में रणनीतिक निवेश और पुनरुद्धार के एक नए युग का संकेत है।
- इन संपत्तियों के पुनर्विकास से क्षेत्र में इको-पर्यटन को भी उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- इटावा लायन सफारी और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का घर है, जो घड़ियाल, डॉल्फ़िन और प्रवासी पक्षियों का एक समृद्ध आवास है, जो प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण हैं।
- शिकोहाबाद, जो पटना पक्षी अभयारण्य और आगरा में सूर सरोवर के पास स्थित है, एक इको-पर्यटन स्थल है जो अपनी समृद्ध पक्षी जैव विविधता और शांत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है।
- उत्तर प्रदेश सरकार का यह दूरदर्शी कदम न केवल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का समर्थन करता है, बल्कि निजी निवेश, रोजगार सृजन और स्थानीय समुदायों के आर्थिक उत्थान को भी प्रोत्साहित करता है।

दिव्यता, भक्ति और विकास की त्रिवेणी

महाकुम्भ के आयोजन के पीछे की सफलता का मूल मंत्र है निरंतर परिश्रम व बेहतर प्रबंधन, साथ ही, हर परिस्थिति में कार्य को पूरा करने की दृढ़ इच्छाशक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में लगातार सकारात्मक कदम उठाते रहे हैं।

महाकुम्भ 2025

महाकुम्भ के सफल आयोजन के पीछे दृढ़ इच्छाशक्ति और बेहतर प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने धार्मिक और आध्यात्मिक महाउत्सव को सफल बनाया। इस आयोजन ने अपनी भव्यता और दिव्यता की अमिट छाप छोड़ी है।

महाकुम्भ के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया हैरान है कि त्रिवेणी संगम पर नदी के किनारे इतने सारे करोड़ों लोग कैसे एकत्र हुए। इन करोड़ों लोगों को न तो कोई औपचारिक निमंत्रण मिला था और न ही आने के समय के बारे में कोई पूर्व सूचना। लोग बस महाकुम्भ के लिए निकल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए।

प्रयागराज में 2025 का महाकुम्भ महज एक धार्मिक समागम से कहीं बढ़कर था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड इतिहास का हिस्सा बनने के लिए एक साथ आया हो। साल बीत जाएंगे, दुनिया घूमेगी, आकाशगंगाएं विकसित होंगी, लेकिन महाकुम्भ को कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड के ताने-बाने में खुद को उकेरने में कामयाब रहा है।

महाकुम्भ के आयोजन के पीछे सफलता का मंत्र अथक प्रबंधन और चीजों को अंजाम तक पहुंचाने की दृढ़ इच्छाशक्ति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, खासकर पर्यटन के संदर्भ में। विचार स्पष्ट था – महाकुम्भ को अविस्मरणीय अनुभव बनाएं। संगम पर टेंट बनाने वालों से लेकर दिन-रात गश्त लगाने वाले उच्च पदस्थ अधिकारियों तक – प्रशासन और समाज के हर कार्यरत सदस्य ने इसे संभव बनाने में हाथ मिलाया। और नतीजा हमारे सामने है।

विशेषज्ञों का दावा है कि महाकुम्भ ने प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को 200% से 300% तक प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ाया। 45-दिवसीय महाकुम्भ के दौरान, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने शहर का भ्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप अनाज, सब्जियां, गद्दे, फर्नीचर, टेंट और अन्य कारोबारियों को 30 से 40 गुना मुनाफा हुआ।

केवल प्रयागराज ही नहीं, बल्कि 100-200 किलोमीटर के दायरे में स्थित शहर और कस्बे भी श्रद्धालुओं के आगमनआमद से लाभान्वित हुए। हॉस्पिटैलिटी, परिवहन और खुदरा जैसे क्षेत्रों में खपत में तेजी देखी गई।

महाकुम्भ 2025 इस बार 144 वर्षों के बाद हुआ। इन छह हफ्तों में श्रद्धालुओं के आगमन ने 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इस एक आयोजन के परिणामस्वरूप यूपी की जीडीपी में 1% की वृद्धि हुई, जिससे 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। सफलता ऐसी थी कि सभी क्षेत्रों के लोग आजीविका कमाने में सक्षम थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक ऐसा ही उदाहरण दिया। "मैं एक नाविक के परिवार की सफलता की कहानी बता रहा हूं। उनके पास 130 नावें हैं। 45 दिनों (महाकुम्भ) में, उन्होंने 30 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। इसका मतलब है कि प्रत्येक नाव ने 23 लाख रुपये कमाए हैं। दैनिक आधार पर, उन्होंने प्रत्येक नाव से 50,000 से 52,000 रुपये कमाए।" जबकि आंकड़े एक कहानी बताते हैं, समझने के लिए एक बड़ा संदेश है।

महाकुम्भ कई मायने में जीवंत यादें दे गया। विश्व ने महाकुम्भ की पवित्रता की अनुभूति की, हालांकि यह सही है कि इसे बदनाम करने की भी कोशिश की गई। लेकिन इस तरह के प्रयास विफल रहे, क्योंकि आंकड़े खुद ही सब कुछ बयां कर देते हैं। जीवन के भव्यतम आयोजनों में से एक महाकुम्भ ने आगंतुकों और मेजबानों दोनों के जीवन को

बदल दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि महाकुम्भ इस दुनिया के भीतर अलग ही दुनिया थी। प्रयागराज शहर न केवल जीवंत हो उठा, बल्कि इसने जीवन को पनपने के लिए जगह भी बनाई। यह संतों और भक्तों का घर बन गया।

पवित्र नदी का नजारा और लोगों की भीड़ का मंत्रोच्चार और गोते लगाने का आनंद लेना, युगों-युगों तक याद रहने वाला नजारा है। इस ज्वलन्त स्वप्न को साकार करने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसा कि कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताया गया है। आंकड़े बताते हैं कि महाकुम्भ की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई गई थी। महाकुम्भ सरकार के समग्र दर्शन को दर्शाता है। 'डबल इंजन' विजन में, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटता और विकास सभी को शामिल करता है।

- 1.6 लाख टेंट, 100 डॉर्मेट्रीज (प्रत्येक 250 बेड वाली), विशिष्ट अतिथियों व न्यायाधीशों के लिए 108 यूनिट्स की कॉलोनी का निर्माण।
- 400 किमी लंबा अस्थायी सड़क नेटवर्क और नदियों-नालों पर 30 पॉन्टून पुल।
- 1,250 किमी लंबी पानी की पाइपलाइन, 85 बोरवेल से जल आपूर्ति।
- 200 वॉटर वेंडिंग मशीनें।
- 96 पावर सब-स्टेशन, 366 किमी केबल और 67,000 स्ट्रीट लाइटें महाकुम्भ को रोशन करने हेतु।
- 2,750 सीसीटीवी कैमरे, 80 डिस्प्ले स्क्रीन, 3 व्यूइंग सेंटर (एलईडी वॉल्स सहित) और 50-सीटर कंट्रोल रूम।
- सुरक्षा हेतु एंटी-ड्रोन सिस्टम।
- 37,611 पुलिसकर्मी (18,479 सिविल पुलिस, 1,378 महिला पुलिस, 1,405 ट्रैफिक पुलिस, 1,158 सशस्त्र पुलिस, 146 घुड़सवार पुलिस, 340 जल पुलिस)।

- 1.5 लाख शौचालय, 25,000 डस्टबिन, 15,000 सफाईकर्मी, गंगा सेवा दूत और 160 से अधिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स, जिससे यह सबसे स्वच्छ महाकुम्भ बना।

इसी तरह, सीएम ने सुनिश्चित किया कि एक भी विवरण छूट न जाए और महाकुम्भ हर संभव जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो। डेढ़ महीने के समागम के दौरान प्रदान की गई विविध सुविधाओं के कई उदाहरण हैं। महाकुम्भ नगर में जल निगम द्वारा वॉटर एटीएम लगाए गए थे। निगम की ओर से सभी 25 सेक्टरों में कुल 233 वॉटर एटीएम लगाए गए। इनके जरिए श्रद्धालुओं को 24 घंटे शुद्ध पानी की आपूर्ति की गई।

उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुम्भ नगर में ओपीडी बनाई गई, जिसमें लाखों मरीज आए। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों की ओपीडी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अमृत स्नान पर्व पर रही। ओपीडी 24 घंटे उपलब्ध रही, जिसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जांच की सुविधा थी। अस्पताल की सेंट्रल पैथोलॉजी में दो लाख से ज्यादा ब्लड टेस्ट किए गए।

महाकुम्भ में डिजिटल खोया-पाया केंद्रों ने हजारों श्रद्धालुओं को फिर से मिलाया। महाकुम्भ में अब तक 20 हजार से ज्यादा लोग जो खो गए थे या बिछड़ गए थे, उन्हें

उनके परिजनों से मिलाया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं।

महाकुम्भ की तस्वीरें और आंतरिक भक्ति ने लोगों को बड़ी संख्या में इस समागम में आने के लिए प्रेरित किया। इसका एक उदाहरण यह भी है कि दो फरवरी को प्रयागराज एयरपोर्ट पर कुल 9516 यात्रियों ने सफर किया। इसमें 4945 यात्री विभिन्न उड़ानों से पहुंचे, जबकि 4571 यात्री एयरपोर्ट से रवाना हुए। कुल 31 विमान उतरे, जबकि 31 विमान दूसरे शहरों के लिए उड़े। एक फरवरी को पूर्व प्रयागराज एयरपोर्ट पर 10599 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। इस दौरान 64 अनुसूचित उड़ानें संचालित हुईं। इसके अलावा 23 गैर अनुसूचित उड़ानें संचालित हुईं। प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए यह अभूतपूर्व आंकड़े हैं और देश-दुनिया में महाकुम्भ के उत्साह का एक जीता जागता संकेत है।

यह महज डुबकी लगाने की बात नहीं थी; यह किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनने की बात थी जो अनूठी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता द्वारा महाकुम्भ की प्रशंसा करना एक सुनहरा अवसर था। राज्य ने प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किया है और महाकुम्भ उनके दिल के करीब था। "प्रयागराज में भव्य महाकुम्भ में आस्था, भक्ति और प्रेम का संगम सभी को अभिभूत कर रहा है। पवित्र संगम पर स्नान करने के बाद मुझे मां गंगा की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं असीम शांति और संतुष्टि में डूबा हुआ हूं और मैंने सभी देशवासियों की खुशी, समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना की।"

प्रधानमंत्री के अलावा, कई प्रतिष्ठित नेताओं और हस्तियों ने महाकुम्भ का दौरा किया। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई मुख्यमंत्रियों जैसे भजन लाल शर्मा, नायब सिंह सैनी, एन. बीरेन सिंह और भूपेंद्र पटेल तक। ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने महाकुम्भ की कई तस्वीरें साझा करते हुए लोगों से इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने का आग्रह किया। वहीं, कैटरीना कैफ और रवीना टंडन जैसी फिल्मी सितारों ने भी

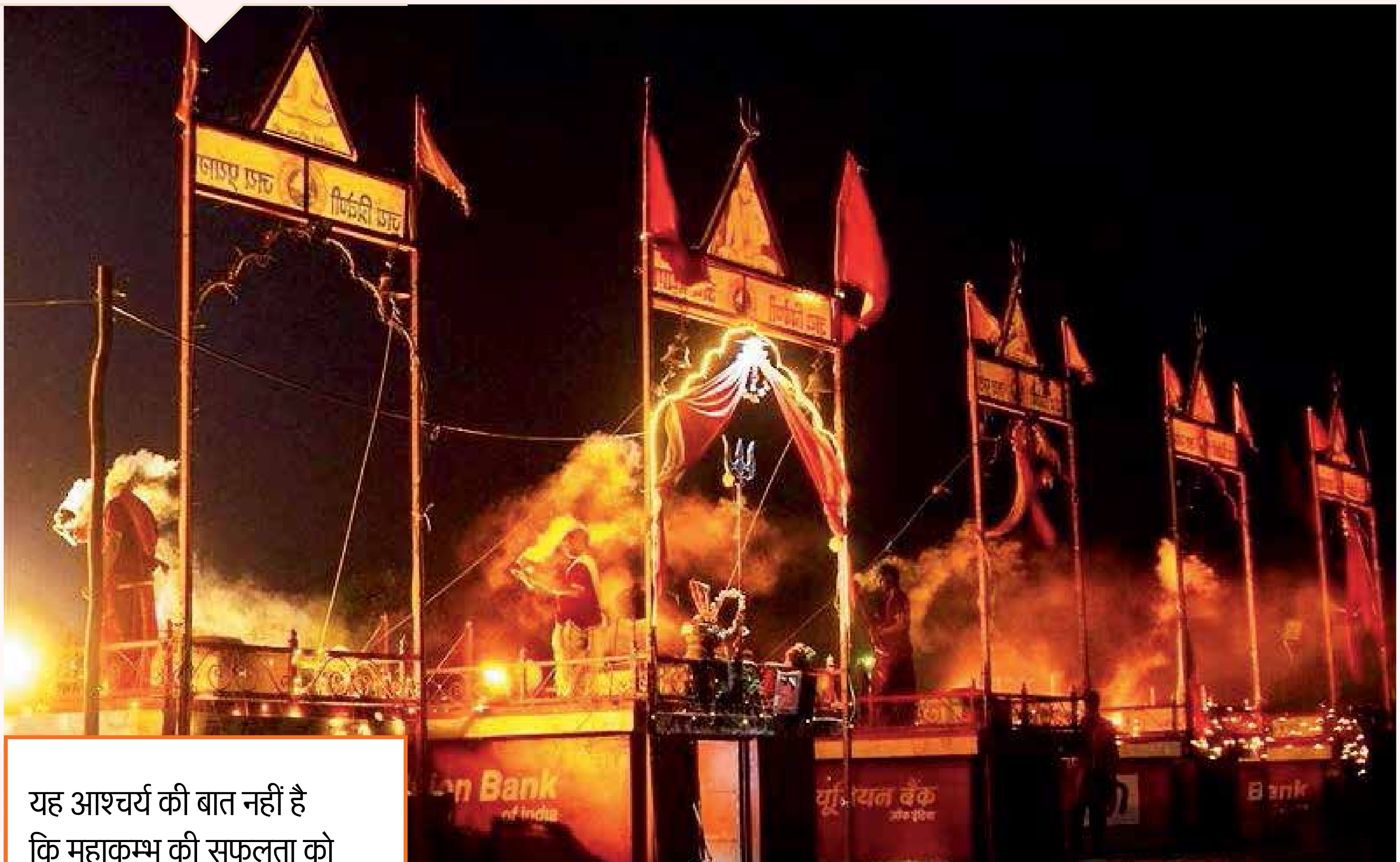

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि महाकुम्भ की सफलता को इतिहास के पन्नों में विभिन्न रूपों में दर्ज किया गया है। गंगा सफाई का एक विश्व रिकॉर्ड भी बना, जब 360 लोगों ने एक साथ चार अलग-अलग स्थानों पर यह अभियान चलाया।

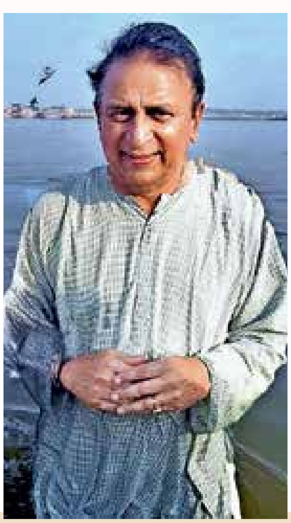

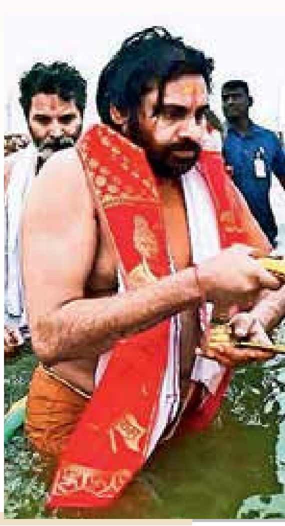

दैवीय आस्था का अनुभव करते हुए पवित्र जल में डुबकी लगाई। वे सभी प्रबंधन और सुविधाओं की प्रशंसा कर रहे थे, जिसने सभी आयु समूहों के लोगों को सकारात्मक संदेश दिया।

ब्रिटिश यात्रा लेखकों के एक समूह ने भी प्रयागराज के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लोकाचार का पता लगाने के लिए महाकुम्भ का दौरा किया। दक्षिण कोरिया, जापान, स्पेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों ने भी उत्सव में भाग लिया। संगम पर डेरा डालने वाले विभिन्न मंदिर ट्रस्टों और भक्त समूहों ने भी प्रशासन की बहुत प्रशंसा की क्योंकि उनकी श्रद्धा का सम्मान किया गया।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष श्रीमहंत रवींद्र

पुरी ने महाकुम्भ में भाग लेने वाले 13 अखाड़ों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म की संस्कृति के प्रति समर्पित हैं। यही वजह है कि महाकुम्भ के आरंभ और समापन पर लोग संगम पर स्नान करने आए। उन्होंने सादगी से स्नान किया। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए वे मेला क्षेत्र में नहीं गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुम्भ के आयोजन में बेहतरीन काम किया है।"

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महाकुम्भ की सफलता को इतिहास की किताबों में अलग-अलग तरीकों से दर्ज किया गया है। 4 अलग-अलग जगहों पर 360 लोगों ने गंगा सफाई का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन सकारात्मक प्रयासों ने महाकुम्भ को विशेष पर्व बना दिया।

हाथ से पेंटिंग करके - 10,102 लोगों ने रिकॉर्ड बनाया। 12 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और विविधता में एकता, जनभागीदारी और सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया। सफाई में - 19000 लोगों का रिकॉर्ड बना, जो पहले के 10,000 लोगों के आंकड़े को पार कर गया। प्रयागराज में आयोजित 2019 कुम्भ में, 10,000 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ सफाई अभियान में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आस्था एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज है और ऐसा नेता होना जो इसे समझता हो, किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। महाकुम्भ ने समुदाय, एकजुटता की भावना को बढ़ावा दिया और लोगों को एक उच्च शक्ति की छत्रछाया में एक साथ बांधा। थोड़े समय के लिए, सभी को एक दिव्य आत्मा से जुड़ा हुआ महसूस हुआ और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरकार दयालु है। यह हर इंसान का सम्मान करता है और यह सुनिश्चित करती है कि उनकी आशाएं, इच्छाएं और आकांक्षाएं हर संभव प्रयास के माध्यम से पूरी हों।

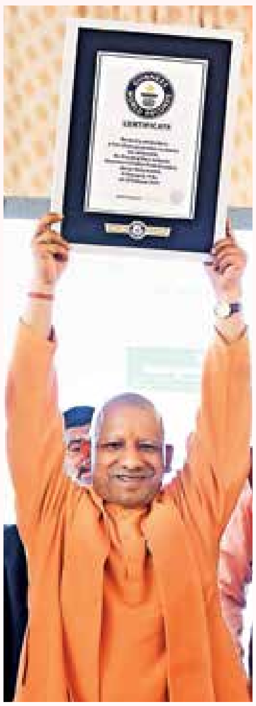

महाकुम्भ 2025

योगी सरकार ने महाकुम्भ 2025 की तैयारियों और भव्य व्यवस्थाओं के लिए 2500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। आवंटित बजट संगम नगरी में विभिन्न क्षेत्रों में मेगा-विकास परियोजनाओं के निर्माण के राज्य सरकार के उद्देश्य में महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार ने 2023 में जिले के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार करके प्रयागराज के समावेशी विकास के लिए 40 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।

दिव्यता की अनुभूति

अध्यात्मिक पर्यटन

काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, विश्व की प्राचीनतम व भगवान शिव की पवित्र नगरी को नया आयाम प्रदान कर रहा है।

राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में आशाजनक संकेतों और रुझानों को मूर्त परिणामों में बदलने के लिए रणनीतिक और सक्रिय रूप से काम कर रही है। जैसे-जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है, यह यात्रा, आवास, भोजन और स्मृति चिन्हों पर खर्च के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और स्थानीय व्यवसायों के विकास में भी योगदान देगा। साथ ही, यह परिवहन, आतिथ्य, होमस्टे और टूर गाइडिंग सहित संबंधित क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा करेगा।

डब्ल्यूटीटीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के लिए भारत के पर्यटन के आंकड़े 2019 के महामारी-पूर्व मानकों को पहले ही पार कर चुके हैं। 2030 के लिए परिषद के पूर्वानुमान भी उतने ही उत्साहजनक हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पर्यटन परिदृश्य में एक अद्वितीय और बेजोड़ स्थान रखता है - भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जैसे पवित्र स्थलों का घर होने के नाते; राधा और कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी बृजभूमि; तीर्थराज प्रयागराज; भगवान शिव की शाश्वत नगरी काशी; और कुशीनगर, सारनाथ और कपिलवस्तु जैसे प्रमुख बौद्ध स्थल यहां हैं। जैसे-जैसे यहां राष्ट्रीय पर्यटन बढ़ता है, उत्तर प्रदेश स्वाभाविक रूप से इस गति से लाभान्वित होता है, और यह प्रवृत्ति आधिकारिक आंकड़ों में भी दिखाई देती है।

योगी सरकार पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा पर केंद्रित विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से उच्च पर्यटन क्षमता वाले स्थलों पर। यह विकास कार्य चरणबद्ध और मिशन-मोड दृष्टिकोण से किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

डब्ल्यूटीटीसी का अनुमान है कि 2025 भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ वर्ष हो सकता है, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 22 लाख करोड़ रुपए का योगदान करने और 4.8 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता है। 2030 तक, यह योगदान बढ़कर 42 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद है और रोजगार 64 मिलियन

से अधिक होगा। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र, विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्षमता को भी उजागर करते हैं। राज्य सरकार इसे पूरी तरह से पहचानती है और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आकर्षणों के विकास को प्राथमिकता देती है।

जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक ही कहा है, "धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास न केवल भक्ति की भावना को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "रामायण, कृष्ण एवं बौद्ध सर्किट के विकास जैसी सरकारी पहलों ने राज्य में पर्यटन विकास को उल्लेखनीय रूप से गति दी है। दोहरी इंजन वाली सरकार ने प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में सड़कों, परिवहन,आवास और सुरक्षा में सुधार के लिए ठोस उपाय लागू किए हैं।" पर्यटन में बढ़ती रुचि और सरकारी नीतियों के व्यावहारिक क्रियान्वयन के कारण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जबकि पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय विशेषताओं को नई पहचान और बाजार में पहुँच मिल रही है। पर्यटन का विस्तार स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए नए रास्ते तलाशने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है।

निःसंदेह, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध दूरदर्शी नेतृत्व के कारण पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। योगी सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर विशेष ध्यान देते हुए एक व्यापक पर्यटन विकास योजना लागू कर रही है। इसके तहत, प्रमुख तीर्थ

पर्यटन संबंधी पहल

- पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थलों पर शोध करने में रुचि रखने वाले संस्थानों के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की है।
- पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें पर्यटन से संबंधित उद्यमों के लिए विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन शामिल हैं। कम-ज्ञात स्थलों पर शोध के लिए अनुदान इसी नीति का हिस्सा है।
- इस पहल का उद्देश्य राज्य में पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करना है। पर्यटन, आतिथ्य और प्रबंधन से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे शोध की गुणवत्ता और व्यावहारिकता दोनों सुनिश्चित हो सकें।
- पिछले दो वर्षों में दस शोध परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और इस वर्ष भी नई शोध परियोजनाओं को समर्थन देने की तैयारी चल रही है।

स्थलों को जोड़ने वाले 272 मार्गों का विकास 4,560 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों का उन्नयन किया जा रहा है ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीपोर्ट सेवाएँ पहले ही शुरू की जा चुकी हैं, और जल्द ही इस सुविधा को अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक विस्तारित करने की योजना है। अयोध्या में, अयोध्या शोध संस्थान का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान का निर्माणा कार्य पूरा हो चुका है। कुशीनगर में बुद्ध थीम पार्क, सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र, और नैमिष तीर्थ एवं शुक्र तीर्थ के पुनरुद्धार जैसी प्रमुख परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। विरासत संरक्षण प्रयासों में गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली और प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर का विकास शामिल है, जहाँ भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान निषादराज गुह्य से ऐतिहासिक मुलाकात की थी। सरकार उत्तर प्रदेश के वनगमन मार्ग, जिस मार्ग से भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ यात्रा की थी, के सभी प्रमुख स्थानों का भी सक्रिय रूप से विकास कर रही है। विशेष रूप से, तुलसीदास के रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में वर्णित देशी पौधे इस मार्ग पर लगाए जाएंगे, जिससे प्रामाणिकता और पारिस्थितिकी मूल्य में वृद्धि होगी।

पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत चित्रकूट, बरसाना और अष्टभुजा-काली खोह में रोपवे परियोजना शुरू की गई हैं, और प्रयागराज और काशी में भी इसी तरह की परियोजनाओं की योजना है।

योगी सरकार के तहत शुरू किया गया अयोध्या में दीपोत्सव एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रम बन गया है, जो अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान और ब्रांडिंग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी और बरसाना में होली में मुख्यमंत्री की भागीदारी ने इन त्योहारों की वैश्विक दृश्यता को और बढ़ाया है, जिससे पर्यटकों की रुचि और पैदल यातायात में वृद्धि हुई है।

सरकारी आंकड़े पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं, अयोध्या में 2023 में पर्यटकों की आमद 5.76 करोड़ से बढ़कर 2024 में 16.44 करोड़, काशी में 10.18 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़, मथुरा में 7.79 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ और प्रयागराज में 5.06 करोड़ से बढ़कर 5.12 करोड़ हो गयी है।

2025 में प्रयागराज में हुए महाकुम्भ ने पर्यटन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह न केवल श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि अयोध्या, काशी और ब्रज आने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। महाकुम्भ ने 66.30 करोड़ आगंतुकों को आकर्षित किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान हुआ।

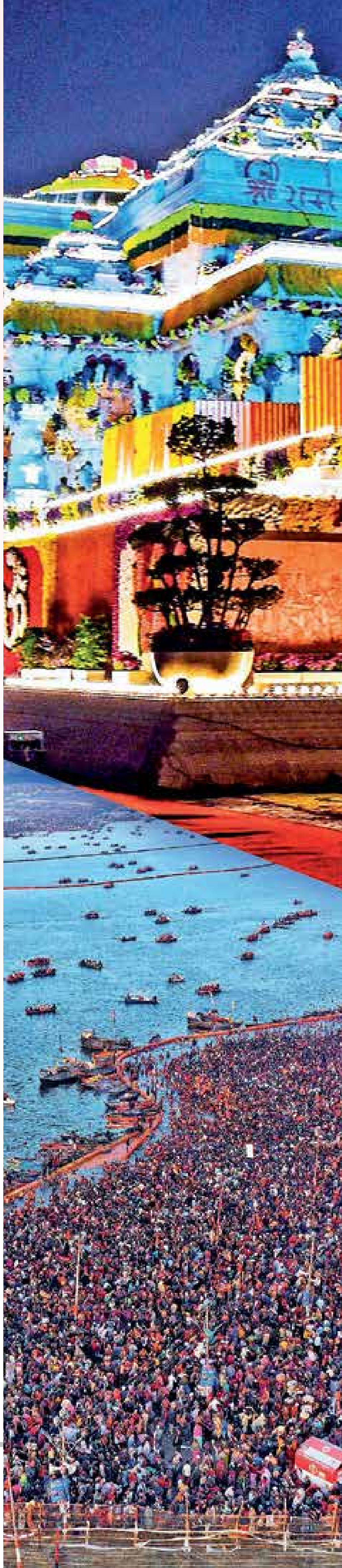

02

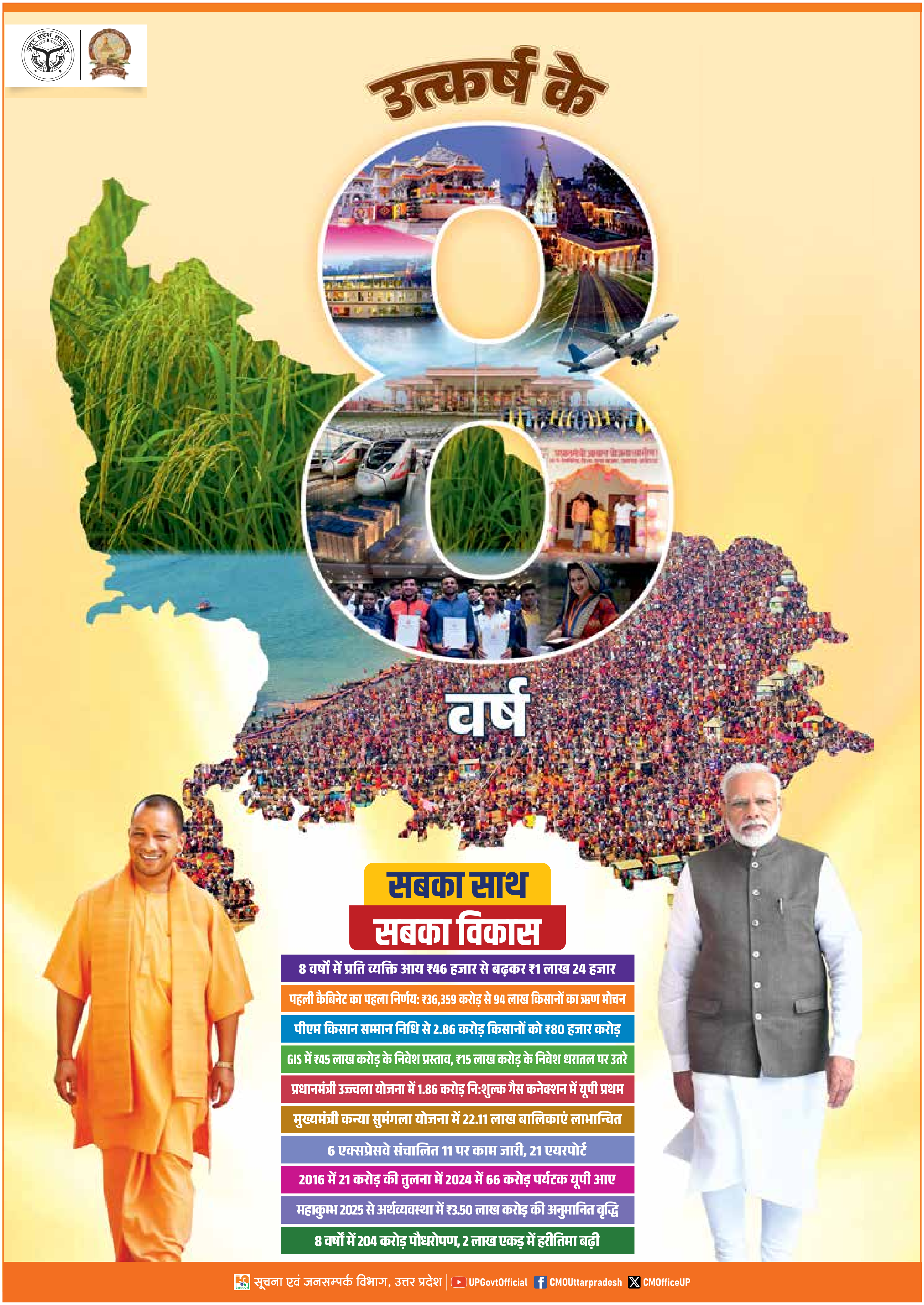
उत्कर्ष के
8
वर्ष
सबका साथ
सबका विकास
8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय ₹46 हजार से बढ़कर ₹1 लाख 24 हजार
पहली कैबिनेट का पहला निर्णय: ₹36,359 करोड़ से 94 लाख किसानों का ऋण मोचन
पीएम किसान सम्मान निधि से 2.86 करोड़ किसानों को ₹80 हजार करोड़
GIS में ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, ₹15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतरे
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.86 करोड़ नि:शुल्क गैस कनेक्शन में यूपी प्रथम
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 22.11 लाख बालिकाएं लाभान्वित
6 एक्सप्रेसवे संचालित 11 पर काम जारी, 21 एयरपोर्ट
2016 में 21 करोड़ की तुलना में 2024 में 66 करोड़ पर्यटक यूपी आए
महाकुम्भ 2025 से अर्थव्यवस्था में ₹3.50 लाख करोड़ की अनुमानित वृद्धि
8 वर्षों में 204 करोड़ पौधरोपण, 2 लाख एकड़ में हरीतिमा बढ़ी
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

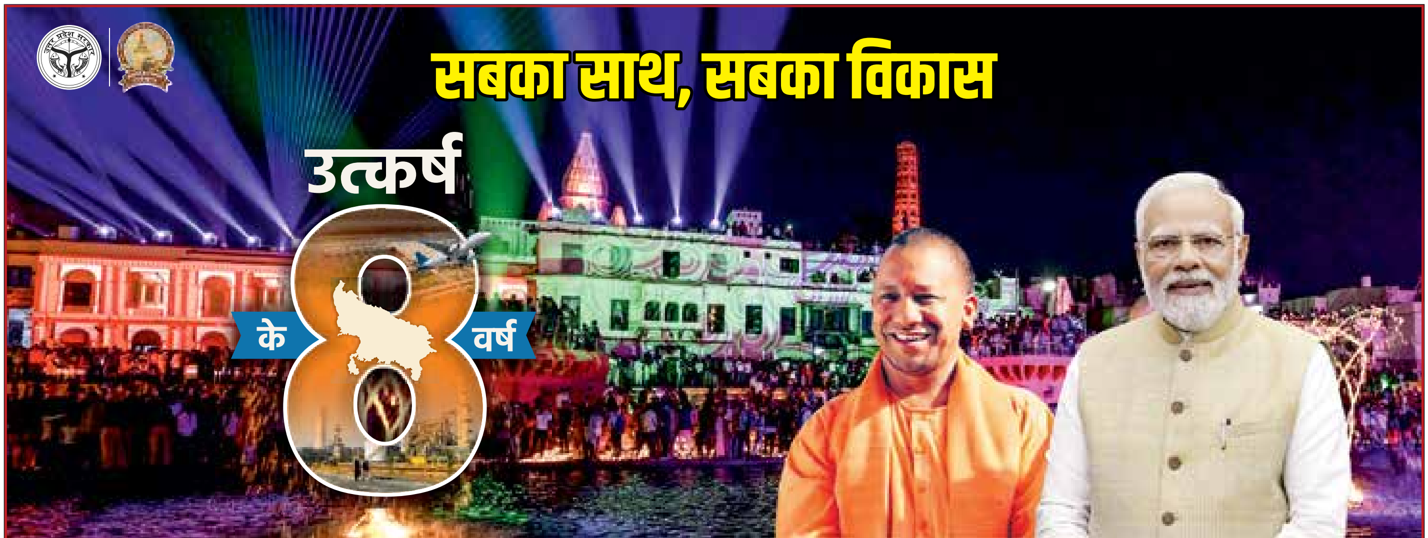

उत्तर प्रदेश नं. 1

- देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में प्रथम
- 56 लाख+ परिवारों के लिए पक्के आवास
- पीएम किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में प्रथम
- 1.86 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण
- स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि ऋण वितरण में प्रथम
- सर्वाधिक 2.75 करोड़ शौचालयों का निर्माण
- 15 करोड़ नागरिकों को नि:शुल्क राशन का वितरण
- 60 लाख माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना सहायता
- 1.58 करोड़ घरों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन
- 9 करोड़+ लोगों को ₹5 लाख तक का नि:शुल्क उपचार
- 9.57 करोड़ लोगों का जन धन बैंक खाता
- 1 करोड़ परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र वितरित

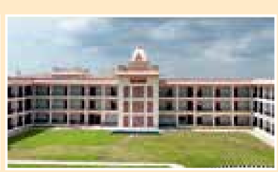

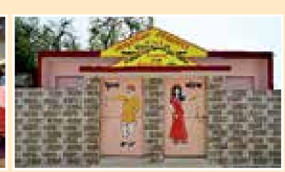

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

खुशहाल किसान, यूपी की पहचान

- पहली कैबिनेट का पहला निर्णय: ₹36,359 करोड़ का फसल ऋण मोचन, 94 लाख किसान लाभान्वित
- खाद्यान्न उत्पादन : वर्ष 2016-17 में 557.46 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 668.39 लाख मीट्रिक टन (20% वृद्धि)
- सिंचन क्षमता : वर्ष 2017 तक 82.58 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 131 लाख हेक्टेयर, 976 परियोजनाएं पूर्ण
- रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान : 2017 से अब तक ₹2.80 लाख करोड़ का भुगतान, पिछले 22 वर्षों में हुए कुल भुगतान से ₹66 हजार करोड़+ अधिक
- चीनी मिल : 3 नयी चीनी मिल, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन, 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार
- अनाज खरीद : बिचौलियों को बाहर किया, ₹43,424 करोड़ गेहूं मूल्य एवं ₹88,746 करोड़ धान मूल्य का भुगतान
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : 2.86 करोड़ किसानों को ₹80,000 करोड़+ हस्तांतरित
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत 75,000+ सोलर पंपों की स्थापना

सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश

- महिलाओं के लिए पुलिस में 20 प्रतिशत पद, 1.38 लाख+ को सरकारी नौकरी
- 10 लाख+ स्वयं सहायता समूह से 1 करोड़+ महिलाओं को रोजगार
- महिला वर्क फोर्स : 2017 में 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 35.1 प्रतिशत हुआ
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : 1.86 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन, होली व दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रीफिल
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : 22.11 लाख बालिकाएं लाभान्वित
- निराश्रित महिला पेंशन योजना : 33.55 लाख महिलाएं लाभान्वित
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : 4.22 लाख जोड़ों का विवाह संपन्न, धनराशि ₹51 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि, 3.73 लाख महिलाएं लाभान्वित
- बी.सी. सखी : 39 हजार+ ने 31,626 करोड़ का लेनदेन किया, 85.81 करोड़ लाभांश

विरासत भी, विकास भी

- महाकुम्भ 2025 में 66.30 करोड़+ श्रद्धालुओं का पुण्य स्नान
- महाकुम्भ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ₹3.50 लाख करोड़+ की वृद्धि
- 6 आध्यात्मिक कॉरिडोर के विकास से पर्यटन में वृद्धि
- अयोध्या में दिव्य-भव्य प्रभु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण
- वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विकास
- अयोध्या में भव्य-दिव्य दीपोत्सव, काशी में देव-दीपावली

काम दमदार, युवाओं को रोजगार

- 2017 में प्रति व्यक्ति आय ₹46 हजार से बढ़कर 2024 में ₹1 लाख 24 हजार
- बेरोजगारी दर : 2016 में 18% युवा बेरोजगार, 2024 में बेरोजगारी दर घटकर 3 प्रतिशत
- 8.5 लाख+ सरकारी नौकरी, 3.75 लाख+ संविदा पर नियुक्ति
- MSME एवं निजी क्षेत्र में 2 करोड़+ रोजगार, ODOP योजना से 2.54 लाख+ रोजगार
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2.27 लाख+ युवाओं को रोजगार
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान : 10 लाख नये उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य

सबके साथ सरकार

- 3,213 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा, 1,630 पर कार्य प्रगतिशील
- अनुसूचित जाति (पूर्व दशम) के 32,49,854 विद्यार्थियों को ₹708.49 करोड़ छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जाति (दशमोत्तर) के 89,31,203 विद्यार्थियों को ₹9,662.25 करोड़ छात्रवृत्ति
- पिछड़ा वर्ग (पूर्व दशम) के 62,79,519 विद्यार्थियों को ₹1,28,627.48 करोड़ छात्रवृत्ति
- पिछड़ा वर्ग (दशमोत्तर) के 1,31,05,263 विद्यार्थियों को ₹7,62,524.03 करोड़ छात्रवृत्ति
- सामान्य वर्ग (पूर्व दशम) के 8,58,750 विद्यार्थियों को ₹221.95 करोड़ छात्रवृत्ति
- सामान्य वर्ग (दशमोत्तर) के 48,13,347 विद्यार्थियों को ₹5,499.86 करोड़ छात्रवृत्ति

स्वास्थ्य का उपहार

- आयुष्मान भारत : 9 करोड़+ लोगों को ₹5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा
- 80 मेडिकल कॉलेज संचालित, 11,300 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि
- गोरखपुर एवं रायबरेली में एम्स, लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय
- महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर
- 22,681 आरोग्य मंदिर का संचालन

विकास पथ पर यूपी का रथ

- 6 एक्सप्रेसवे संचालित, 11 पर काम जारी, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के कुल एक्सप्रेसवे में 55% की हिस्सेदारी
- एक्सप्रेसवे की लम्बाई : 2017 तक 491 किलोमीटर, 2024 तक 1225 किलोमीटर
- 32 हजार किमी+ लम्बाई के मार्गों का नवनिर्माण, 25 हजार किमी के मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण
- 2017 तक केवल 04 एयरपोर्ट, 21 एयरपोर्ट की ओर अग्रसर देश का एकमात्र राज्य, जिनमें 05 इंटरनेशनल एयरपोर्ट
- देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट लगभग तैयार, सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनेगा उत्तर प्रदेश
- हल्दिया से वाराणसी तक जलमार्ग संचालित, प्रयागराज-अयोध्या तक विस्तारीकरण का कार्य जारी

सबको शिक्षा-उत्तम शिक्षा

- सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण
- 57 असेवित जनपदों में सीएम मॉडल कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण
- अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, बलरामपुर, मीरजापुर एवं मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालयों का संचालन
- प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण
- गोरखपुर में सैनिक स्कूल, फॉरेस्ट्री कॉलेज, एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी
- गोरखपुर एवं चंदौली में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय

अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस

- 2017 के पहले माफिया-अपराधी बेलगाम, 2017 के बाद कानून का राज, भयमुक्त व्यवस्था
- एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार डकैती के मामलों में 84.41%, लूट में 77.43%, हत्या में 41.01%, बलवा में 66.40%, फिरौती के लिए अपहरण में 54.72%, दहेज हत्या में 17.08% और बलात्कार के मामलों में 26.15% की कमी
- 79,984 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई
- माफिया के अवैध कब्जे से लगभग ₹3000 करोड़ की संपत्ति जब्त, अवैध संपत्तियां गिराकर उन पर गरीबों के लिए आवास
- 226 दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में ढेर, 29,111+ बदमाश जेल भेजे गए
- 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, 18 एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूनिट स्थापित
- 6 स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की वाहिनियां, 3 महिला पीएसी बटालियन स्थापित
- सभी जनपदों में साइबर थाने, 11 लाख+ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना
- 112 पुलिस कंट्रोल का रिस्पॉन्स टाइम 2017 से पहले 25.42 मिनट, 2024 में घटकर 7.24 मिनट

अंत्योदय से गरीब कल्याण

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना : 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन
- प्रधानमंत्री आवास योजना : 56 लाख+ आवासों का निर्माण
- पीएम स्वनिधि योजना : 1,80,000+ स्ट्रीट वेंडर्स को ₹3,000 करोड़ + का ऋण
- हर घर जल योजना : 2.37 करोड़ + परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल की सुविधा
- मनरेगा : 200 करोड़ मानव दिवस सृजित, 100 दिन का रोजगार देने में प्रथम

खुशहाल किसान यूपी की पहचान

उत्कर्ष के 8 वर्ष

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2.86 करोड़+ किसानों को ₹80,000+ करोड़ हस्तांतरित

- गन्ना किसानों को रिकॉर्ड ₹2.80 लाख करोड़+ गन्ना मूल्य का भुगतान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 58.07 लाख किसानों को ₹47,535.09 करोड़ की क्षतिपूर्ति
- कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में 8.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 13.7 प्रतिशत हुई
- पीएम कुसुम योजना में किसानों को 76,189 से अधिक सोलर पम्पों का आवंटन
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना लागू
- पीएम किसान मानधन योजना में 2.52 लाख किसानों को लाभार्थी कार्ड
- 49 जनपदों के 85,710 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 63 हजार से अधिक किसान लाभान्वित
- वर्ष 2016-2017 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 5.57 करोड़ मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर लगभग 6.69 करोड़ मीट्रिक टन हो गया
- कृषि विकास दर वर्ष 2016-17 में 8.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 13.7 प्रतिशत हुई
- रबी विपणन वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक 233.99 लाख मी. टन गेहूं की खरीद कर ₹43,424 करोड़ से अधिक का किसानों को भुगतान
- खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक 456.86 लाख मीट्रिक टन धान क्रय कर ₹88,746 करोड़ का भुगतान

काम असरदार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP